बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 191

नीतिगत विकास

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने 1988 में कहा था, 'मुझे लगता है कि आपको चेतावनी देनी चाहिए। अगर आपको मेरी बातें एकदम स्पष्ट लग रही हैं तो शायद आपने मेरी बातों को गलत समझा है।' तब से अब तक दुनिया भर में केंद्रीय बैंकिंग में काफी कुछ बदल चुका है। किसी बड़े केंद्रीय बैंक का कोई वरिष्ठ अधिकारी यह नहीं चाहता कि वित्तीय बाजार उसे किसी भी तरह गलत समझें। वास्तव में वे स्पष्टता सुनिश्चित करने की हर कोशिश करते हैं और नीतिगत निर्णयों को सही ढंग से आगे पहुंचाया जाता है। संचार अब एक अहम उपाय है जिसका इस्तेमाल खासतौर पर बड़े केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत निर्णयों को न्यूनतम दिक्कतों के साथ अपनाने में किया जाता है। हाल के दशकों में केंद्रीय बैंकिंग के आकलन और भविष्य की संभावित चुनौतियों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने काठमांडू में एक भाषण में दिलचस्प ढंग से बात की। इसके कुछ पहलुओं पर व्यापक चर्चा से नीतिगत स्पष्टता बढ़ेगी।

केंद्रीय बैंकों के सामने भी हाल के दशकों में अहम चुनौतियां आईं। अधिकांश केंद्रीय बैंकों के सामने उच्च मुद्रास्फीति की समस्या है क्योंकि उन्होंने शुरुआती चेतावनी वाले संकेतों को गलत समझा। वैश्विक वित्तीय संकट से तुलना करें तो ये हालात काफी अलग थे। उस समय केंद्रीय बैंक अपस्फीति की स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बैंकों ने ऋणात्मक ब्याज दर का विकल्प चुना तथा अन्य ने बहुत बड़े पैमाने पर क्वांटिटेटिव ईज़िंग को अपनाया ताकि वास्तविक अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाया जा सके।

ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब इनमें से कुछ उपायों पर केवल सैद्धांतिक चर्चा होती थी। हालांकि संकट की प्रकृति अलग थी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के तौर तरीकों को कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किया गया। उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंकों की स्थिति अधिक जटिल रही है। उनको विकसित देशों में विस्तारित अवधि तक लागू नीतियों के छिटपुट प्रभाव से भी निपटना पड़ा है। 2013 में टैपर टैंट्रम (फेडरल रिजर्व द्वारा बॉन्ड खरीद कम करने की घोषणा के बाद मची उथलपुथल) के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने वृहद आर्थिक स्थिरता मजबूत करने पर ध्यान दिया। इससे भारत को हाल के वर्षों में वैश्विक प्रभावों से निपटने में मदद मिली। दास ने भविष्य की चुनौतियों के अहम पहलुओं को भी रेखांकित किया। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन नीतिगत जटिलता बढ़ा सकता है। इससे कीमतों और मूल्य स्थिरता दोनों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। भारतीय संदर्भ में जहां खाद्य पदार्थ खपत का एक बड़ा हिस्सा हैं वहीं जलवायु झटके शीर्ष मुद्रास्फीति दर को लंबी अवधि तक ऊपर रख सकते हैं और नीतिगत प्रतिक्रिया में वृद्धि का त्याग करना पड़ सकता है। निरंतर भूराजनीतिक तनाव के कारण गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी प्रवाह बाधित हो सकता है। एक अन्य पहलू है तकनीक का विकास। तकनीक ने हाल के वर्षों में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का चेहरा बदल दिया है और उसने वित्तीय समेकन बढ़ाने में मदद की है। हालांकि यह एक नई तरह की चुनौतियां भी लाती है। उदाहरण के लिए बैंकिंग एक अस्थिर कारोबार है और भरोसे पर चलता है। विश्वास भंग होने की स्थिति में बैंकों से बहुत तेजी से जमा राशि बाहर जाती है। गत वर्ष अमेरिका में मिनी बैंकिंग संकट के समय ऐसा ही हुआ था। वित्तीय तंत्र की अंतः संबद्धता को देखते हुए कोई भी बड़ा वित्तीय संस्थान व्यवस्थागत जोखिम का शिकार हो सकता है।

ऐसे में यह अहम है कि सभी नियमित वित्तीय संस्थान हमेशा अच्छी स्थिति में रहें। रिजर्व बैंक की बात करें तो उसने भी समय के साथ समझदारी भरे कदम उठाए ताकि वे बैंकिंग और वित्तीय तंत्र में मुश्किलों को कम कर सकें।

हालांकि गलत आकलन जैसी घटनाएं भी हुई हैं, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने दशकों के दौरान काफी सुधार किया है। उन्होंने कीमतों और वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखने के लिए नए उपाय विकसित किए हैं। ये उत्पादन में सुधार के लिए आवश्यक हैं। यह विकास 'ज्ञात-अज्ञात' और 'अज्ञात-अज्ञात' दोनों तरह के हालात को हल करने के लिए जारी रहना चाहिए।

बिनय सिन्हा

भारत जैसी उभरती ताकत के लिए चुनौतियां

भारत की अंदरूनी हालत और वैश्विक छवि के बीच असंतुलन इसकी विदेश नीति के लिए चुनौती पेश कर रहा है। बता रहे हैं श्याम सरन

भारत अब भी विकासशील देश की पहचान से बाहर नहीं निकल पाया है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 डॉलर है, जो आय एवं धन में व्यापक असमानता की तरफ इशारा करती है। मानव विकास सूचकांक में भारत इस समय 193 देशों में 134वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक किसी देश की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के आकलन का अधिक उपयुक्त माध्यम है। विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का मार्ग लंबा प्रतीत हो रहा है और लगभग निश्चित है कि 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होने जा रहा है।

भारत को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बेशक निम्न से मध्यम आय वर्ग वाले देश की श्रेणी में रखा जा सकता है मगर यह उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाले देशों में शुमार है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार इस समय 3.5 लाख करोड़ डॉलर है और इस लिहाज से यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। किंतु शेष बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तथा इसके बीच अंतर काफी अधिक है। वैश्विक जीडीपी में अमेरिका की हिस्सेदारी 26.3 प्रतिशत, यूरोपीय संघ की 17.3 प्रतिशत और चीन की 16.9 प्रतिशत है लेकिन भारत की हिस्सेदारी महज 3.6 प्रतिशत है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दूसरे की तुलना में आपका वजन काफी मायने रखता है, इसलिए वृहद-आर्थिक दृष्टि से दुनिया में भारत का रुतबा औसत स्तर का माना जा सकता है।

हालांकि कुछ ऐसे कारक भी हैं, जो भारत को वजनदार बना रहे हैं। भारत की आबादी दुनिया में अब सबसे अधिक हो गई है और इसमें युवाओं की संख्या अधिक है। भारत के लिए संभवतः यह बड़ी ताकत है क्योंकि चीन सहित दुनिया के अन्य देशों में आबादी तेजी से कम हो रही है और उसमें भी उम्रदराज लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और इसका जीडीपी 6 से 6.5 प्रतिशत दर से बढ़ रहा है। अगर वृद्धि की यह दर बरकरार रही तो वैश्विक जीडीपी में ठहराव आने पर भारत आर्थिक एवं वाणिज्यिक संभावनाओं का बड़ा केंद्र बन जाएगा। भारत जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा तथा तकनीक में बदलाव जैसी चुनौतियों से निपटने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। अंतरराष्ट्रीय समस्याएं इतनी पेचीदा होती हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों या औद्योगिक एवं विकासशील देशों के समूह जी-7 के लिए भी इनका व्यापक समाधान खोज पाना मुश्किल होता है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए शक्तिशाली देश बाकी दुनिया पर अब पहले की तरह वैश्विक नियम-कायदे नहीं लाद सकते।

तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं किसी विशेष क्षेत्र में वैश्विक व्यवस्था का आकार निर्धारित करने में आगे नहीं आ पाती हैं मगर वे ऐसी व्यवस्था लागू होने से रोकने में जरूर अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं। इससे यह संदेश जा सकता है कि तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रयासों में बाधा डालती हैं। मगर इसके ठीक उलट वे पहले के मुकाबले अधिक कारगर तरीके से अपने हितों की रक्षा कर पा रही हैं। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठा चुका है और वह आगे भी ऐसा करेगा। मगर इसे वैश्विक स्तर पर पेचीदा संवाद प्रक्रिया में अपनी बात कारगर तरीके से रखने के लिए अपनी क्षमता बढ़ानी होगी।

भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास सूचकांकों में मेल नहीं दिखता है। सामाजिक विकास सूचकांकों में यह अब भी पीछे चल रहा है मगर इस बीच दुनिया में भारत की छवि में काफी सुधार हुआ है। भारत के विकास का यह ढांचा दुनिया की स्थापित अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाने वाले तौर-तरीकों से काफी अलग है। वैश्विक पटल पर दूसरे देशों की अहमियत उनके लोगों एवं सामाजिक कल्याण में सतत सुधारों के साथ-साथ बढ़ती जाती है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में सक्रिय भूमिका निभाने में उलझन का सामना करती हैं। इन देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक जिम्मेदारी उठाएं और साझा वैश्विक हितों में अधिक योगदान दें। मगर इन देशों को उन वैश्विक ढांचे की तलाश रहती है जो उन्हें घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और जरिये मुहैया कराएं। भारत जैसे देशों के लिए ऐसे ढांचे की तलाश जरूरी है क्योंकि वह विकासशील देश से बड़ी उभरती शक्ति बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है।

भारत जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका निभाना और देश के भीतर चुनौतियों से निपटने की अनिवार्यता के बीच संतुलन स्थापित करना आसान नहीं है मगर उसके लिए यह जरूरी है। विभिन्न देशों के साथ साझेदारी करने, छोटे स्तर के समझौतों, क्षेत्रीय एवं कार्यशील समूहों में सक्रिय भागीदारी निभाने में भारत की सक्रियता इसी ओर इशारा करती है। भारत उन विशेष उद्देश्यों के लिए तैयार गठबंधनों में हिस्सा ले रहा है और यह निर्णय उसके लिए लाभकारी भी रहा है।

भारत को 'क्वाड' (अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ) और 'शांघाई सहयोग संगठन' (जिसमें चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और पश्चिम एशिया हैं) का हिस्सा होने में किसी तरह का विरोधाभास नहीं दिखता। न ही इसे ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में चीन जैसे देशों के साथ सहयोग करने में कोई एतराज है। इसी तरह बिम्सटेक (जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं) का हिस्सा बनकर भी यह अन्य देशों के साथ सहयोग कर रहा है। भारत ने जी-20 सम्मेलन का सफल आयोजन किया है। ये सभी प्रयास भारत को वैश्विक शक्ति बनाते हैं। देश के भीतर भारत की क्षमता और दुनिया में इसकी छवि के बीच तालमेल का अभाव इसकी विदेश नीति के लिए जटिल चुनौतियां खड़ी करता है। दुनिया में बढ़ता कद भारत के लिए संतुष्टि की बात है मगर आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षमताओं के लिहाज से अधिक ताकतवर नहीं होने से वैश्विक समीकरण को नई दिशा देने में भारत की भूमिका सीमित रह जाती है। हमारी मुख्य चिंता अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ी है। इस लिहाज से वैश्विक ताने-बाने में भारत की स्थित सहज नहीं लगती है। व्यापार की बात हो या जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां, भारत पूरी दुनिया को सार्वजनिक उपभोग का सामान देते हैं और दूसरे देशों से ऐसा सामान लेते भी हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के अधिक सहज नियम-कायदों की हिमायत करने या अपने विकास की जरूरतों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त एवं तकनीक हस्तांतरण की मांग करने में हमारी प्राथमिकता चीन सहित दूसरे देशों से अलग है। प्रश्न यह है कि भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने वाले देश के रूप में उससे लगाई जा रही उम्मीदों को कब पूरा करना चाहिए और कब इनका विरोध करना चाहिए, जबकि ऐसा करना उसकी गरीब आबादी के लिए नुकसानदेह हो सकता है? क्या हमें दुनिया के निम्न आय वर्ग वाले विकासशील देश के रूप में अपनी पहचान को दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश की तुलना में अधिक तरजीह देनी चाहिए?

भारत के लिए यह पसोपेश वाली स्थिति है, जो अगले कई वर्षों तक बनी रहेगी। प्रत्येक स्थिति में हमें संतुलन साधना होगा ताकि वैश्विक स्तर पर बड़े देश की भूमिका निभाते समय हमारे करोड़ों नागरिकों के बुनियादी विकास पर कोई असर न पड़े। यह संतुलन भारत के नागरिकों के हितों के अनुरूप रहना चाहिए।

(लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं)

क्या राह से भटक गए हैं एफआईआई?

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी जून 2022 के मध्य से 69 प्रतिशत उछल चुका है। जून मध्य में निफ्टी 15,183 अंक पर था मगर अब यह 25,791 अंक तक पहुंच चुका है। पिछले 18 महीनों में इसमें 52 प्रतिशत उछाल आई है। ऐसा लग रहा है कि खुदरा निवेशकों, म्युचुअल फंड और अन्य देसी संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने बाजार में तेजी से मोटा मुनाफा कमाया है। हां, आंख मूंदकर दांव लगाने वाले डेरिवेटिव कारोबारियों को जरूर नुकसान हुआ है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में डेरिवेटिव कारोबारियों ने 51,689 करोड़ रुपये का घाटा झेला है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का क्या रुख रहा? यह माना जा सकता है कि अपने अथाह अनुभव, गहरे शोध और बड़ी रकम हाथ में होने के कारण उन्हें बाजार में भारी तेजी के दौरान मोटा मुनाफा कमाना चाहिए था। लेकिन एफआईआई के बारे में यहां कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं।

जून 2022 और 20 सितंबर 2024 के बीच बाजार में तेजी के दौरान एफआईआई शुद्ध बिकवाल रहे थे! जी हां, आपने ठीक ही पढ़ा। उन्होंने 1.82 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सबसे बड़ी बिकवाली जून 2022 में हुई। नवंबर 2021 से बाजार में कमजोरी का दौर शुरू हुआ था और जून 2022 में वह एकदम नीचे चला गया था। बाजार इतना नीचे था तब भी एफआईआई ने घबराहट में 58,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेच डाले। वर्ष 2021 के अंत से भारतीय एवं वैश्विक बाजार ऊंचे मूल्यांकन, अमेरिका में मुद्रास्फीति में तेजी, चीन में कोविड के बाद कमजोर सुधार और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण बाजार गिरने लगे थे। आखिर एफआईआई ने जून 2022 में किन्हें शेयर बेचे? ये शेयर डीआईआई ने खरीदे थे। जून में जब बाजार नीचे था तब डीआईआई ने 47,000 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे।

यही बाद में भी दोहराया गया। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष जनवरी में अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बाजार में खलबली मच गई तो डीआईआई को अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने 33,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर खरीद लिए। इसी दौरान एफआईआई ने घबराकर 41,000 करोड़ रुपये के शेयर बेच डाले। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि माहिर निवेशकों से भी कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं मगर बाजार में ऐसी किसी भी बड़ी घटना पर एफआईआई ने घटिया फैसले लेकर चौंकाया। एफआईआई ने पिछले साल मई और जून में बढ़-चढ़ कर निवेश किया मगर जैसे ही तेजी शुरू हुई तो अगले तीन महीनों में उन्होंने बिकवाली आरंभ कर दी। उन्होंने 76,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जो डीआईआई ने खरीद (70,000 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध खरीदारी) लिए। जब नवंबर 2023 में बाजार ऊपर भागा तो डीआईआई को मोटा फायदा हुआ। इससे एफआईआई का फैसला कहीं न कहीं बचकाना लगने लगा।

एफआईआई तब भी नहीं संभले और इस साल केवल मार्च को छोड़कर जनवरी और मई के बीच शुद्ध बिकवाल रहे। मार्च में उन्होंने 3,300 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। आम चुनाव से ठीक पहले के कुछ महीनों में एफआईआई ने 1.26 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे जबकि डीआईआई ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शेयरों की लिवाली की। एफआईआई का फैसला एक बार फिर गलत साबित हुआ। जिस दिन लोक सभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे उस दिन बाजार धड़ाम से जरूर गिरा मगर उसके बाद से लगातार तेजी बनी हुई है। आश्चर्य की बात है कि पिछले चार महीनों के दौरान एफआईआई ने काफी छोटे स्तर पर खरीदारी की और अगस्त में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की। अलबत्ता सितंबर में अब तक वे शुद्ध खरीदार रहे हैं। ये आंकड़े बड़े सौदों (बल्क डील) के बाद कुछ बदल सकते हैं मगर रुझान मोटे तौर पर स्पष्ट हैं। बाजार में तेजी के पिछले 29 महीनों में देसी संस्थागत निवेशकों ने 5.91 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शेयर खरीदे और एफआईआई ने 1.82 लाख करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की।

हालात कितने बदल गए हैं! एक दौर था, जब भारतीय बाजार में एफआईआई का दबदबा इतना अधिक था कि दिवंगत आर रवि मोहन (तब क्रिसिल के प्रबंध निदेशक) ने इस समाचार पत्र से कहा था, 'एफआईआई के प्रति लोगों का सम्मान अब डर और खुशी की मिली-जुली भावना में बदल गया है।'

आश्चर्य की बात यह नहीं है कि एफआईआई हालात भांप नहीं पाए। पेशेवर निवेशक भी कभी-कभी गलती कर बैठते हैं। उनकी शांत, पेशेवर और गहरे शोध एवं सोच विचार के बाद सही दाम पर खरीदारी करने की छवि अक्सर गलत साबित हो जाती है। मगर उनसे गलतियां अक्सर जान-बूझकर लिए गए फैसलों का नतीजा होती हैं न कि लापरवाही का।

बाजार में तेजी के दौरान एफआईआई अधिक चढ़ने वाले शेयर खरीदते हैं और खुदरा निवेशकों की तरह व्यवहार करते हैं। वर्ष 1994 में उन्होंने परिसंपत्तियों से भारी मगर कमजोर संचालन वाली भारतीय कंपनियों पर बड़े दांव लगाए थे। 1999 में भी तेजी के दौरान उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनियों पर दांव लगाए थे। ऐसा उन्होंने दूसरे निवेशकों को देखते हुए या कयासों से प्रभावित होकर अथवा कीमतें बढ़ने की उम्मीद में किया था। एफआईआई ने 60 से 80 प्रतिशत तक रकम तकनीक, मीडिया एवं दूरसंचार कंपनियों में काफी महंगे शेयरों में झोंक दी। 2005 से 2008 के दौरान बाजार में शानदार तेजी के समय उन्होंने रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा कंपनियों में ज्यादा निवेश कर दिया, जिसका नतीजा उनके लिए कमजोर प्रतिफल के रूप में सामने आया।

यह पहला मौका है जब एफआईआई वे निर्णय नहीं ले पाए, जो उनकी रणनीति के लिए सही बैठते। वे उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी क्षेत्र की कंपनियों, रक्षा एवं हरित ऊर्जा एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में तेजी का लाभ नहीं ले पाए। इनमें कई कंपनियों के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि यह स्थिति क्यों आई है। आखिरकार पेशेवर निवेश में तगड़ी होड़ होती है और प्रदर्शन को कसौटी पर हर महीने कसा जाता है। इस वजह से संस्थागत निवेशक बाजार में तेजी से चढ़ते शेयर खरीदते हैं और तेजी थमने पर उन्हें बेच देते हैं। उनके लिए चढ़ते हुए शेयर खरीदने से रुकना मुमकिन नहीं हो पाता। पिछले 30 वर्षों में पहली बार मैंने देखा है कि एफआईआई धारा के विपरीत तैर रहे हैं। अब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटा दी हैं और भारत सरकार ने भी आर्थिक वृद्धि को ताकत देने वाली नीतियां जारी रखने के संकेत दिए हैं तो क्या एफआईआई अपना रवैया बदलेंगे?

(आंकड़ों के कई स्रोत हैं मगर लेख में नकदी-बाजार निवेश के अस्थायी आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं। अन्य स्रोतों से आंकड़े अधिक एफआईआई निवेश दिखा सकते हैं।)

(लेखक डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मनीलाइफ डॉट इन के संपादक एवं मनीलाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं)

आपका पक्ष

रात्रि गश्त एवं एआई का सघन उपयोग किया जाए

रेलवे बोर्ड समय-समय पर निर्देश देता है कि पूरे साल पटरियों की 24 घंटे गश्त की जाए। हालांकि, जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि पटरियों की देखरेख करने वाले कर्मियों की कमी के कारण पूरे वर्ष रात्रि गश्त नहीं की जाती है। साबरमती एक्सप्रेस के दुर्घटना होने से पहले रात्रि गश्त नहीं हो रही थी। हालांकि अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक रात्रि गश्त का प्रावधान प्रतिकूल मौसम की स्थिति में रेल की पटरियों के रखरखाव के उद्देश्य से होता है, न कि असामाजिक गतिविधियों से इसे सुरक्षित करने के उद्देश्य से। लेकिन अब रेल पटरियों से छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा चौबीसों घंटे पटरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) आधारित समाधानों पर तेजी से कार्य करना होगा। प्रत्येक स्टेशन में सिग्नल पहलुओं और ट्रेन की गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी रिकॉर्ड करने वाला एक डेटा लॉगर होता है और प्रत्येक लोकोमोटिव/ट्रेन सेट में एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है जो गतिविधि, गति और ब्रेकिंग पर डेटा एकत्र करता है। यह विशाल डेटा साइलो में रहता है, जिसका उपयोग केवल विश्लेषण के लिए किया जाता है और कभी भी सिर्फ अलर्ट उत्पन्न करने के लिए एकत्र नहीं किया जाता है। इन अलर्ट को दिन-प्रतिदिन के आधार पर उत्पन्न करना, मैन्युअल जांच के साथ आसानी से संभव नहीं है। अतः विशेष कर पटरियों में हुई गड़बड़ियों पर शीर्ष प्रबंधकों के ध्यान के लिए एआई टूल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

सिलिगुड़ी के पास मैनागुड़ी स्टेशन के करीब मंगलवार को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी

पर्यटन को और बढ़ावा देने की जरूरत

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन दिवस मनाने की घोषणा 1980 में की थी। पहला विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 1980 को मनाया गया था। इस साल का पर्यटन दिवस का थीम है, पर्यटन और शांति। हिमाचल प्रदेश पर्यटन के नजरिये से विश्व में मशहूर है। यहां वर्ष भर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। शिमला, डलहौजी, कुल्लू-मनाली या फिर हो धर्मशाला-मैकलोडगंज प्रदेश के पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। देश के बहुत से दूसरे राज्यों में भी पर्यटक आते हैं। अगर केंद्र और प्रदेश सरकारें कोशिश करे तो देश में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए ऐतिहासिक, प्राचीन स्थान, किले आदि का खूब प्रचार किया जाए। देश के बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र भी है जो पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन उन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए परिवहन की सुविधा उचित नहीं है। इसके लिए सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी बातों पर गौर करे तो देश में हर वर्ष पर्यटकों का तांता लगा रहेगा। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्यटकों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे निर्माणों में दिशानिर्देशों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है जिससे बारिश के कारण जलजमाव हो जाता है। इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को भारतीय सैन्य वर्दी पहनकर सियाचिन स्थित 'बेस कैंप' का दौरा किया और सियाचिन युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध के मैदान में तैनात सैनिकों से कहा कि सभी देशवासी उनकी वीरता को प्रणाम करते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 27 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है, वैसा प्रबल साधन न सत्य है, न दान है और न यज्ञ है।
-वाल्मीकि

टिप्पणी पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को ऐसी टिप्पणियां करने से सतर्क रहने को कहा है, जो स्त्रियों के प्रति द्वेषपूर्ण मानी जाएं या किसी खास लैंगिक या समुदाय के खिलाफ हों। अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बेशक, उनको माफ कर दिया लेकिन उसकी तल्खी स्पष्ट दिखी। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा कहा जा सकता क्योंकि यह मूलभूत देश की क्षेत्रीय अखंडता के विपरीत है। पीठ ने कहा कि अदालतों को सतर्क रहना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऐसी टिप्पणियां न की जाएं। देश के ज्यादातर उच्च न्यायालयों द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू की जा चुकी हैं।

सोशल मीडिया पर नियंत्रण न होने और गोपनीयता के लिए खतरनाक होने के सवाल पर पीठ ने कहा कि किसी गलत बात पर पर्दा डालना कोई समाधान नहीं है, बल्कि उसका सामना किया जाना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी जिस पर नेटीजनों ने तरह-तरह के कमेंट किए थे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने महिला वकील के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों के प्रति इस तरह की पूर्वाग्रहीत बातें आम होने के बावजूद न्याय की कुर्सी पर विराजित सम्मानित अधिकारी से ऐसी उम्मीद नहीं की सकती। सर्व धर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की संवैधानिक व्यवस्था को किसी भी रूप में नकारा जाना उचित नहीं है। जजों के साथ ही वकीलों और वादियों को इस दौर में खासी सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि अब अदालत में मौजूद लोग ही न्यायिक प्रक्रिया नहीं देखते बल्कि चर्चित फैसलों पर आम लोगों की भी कड़ी नजर होती है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अब इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख चुकी है। जब इस तरह की कोई भी टिप्पणी वायरल होती है तो उस पर किए जाने वाले कमेंट्स पर सख्ती नहीं की जा सकती। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विभिन्न मौकों पर मार्गदर्शन द्वारा न्याय प्रणाली की गरिमा को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करते रहे हैं। यही कारण है कि देश की न्याय प्रक्रिया के प्रति देशवासियों में जबरदस्त विश्वास बना हुआ है। उसे कायम रखने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों को इस आदेश का गंभीरतापूर्वक अनुपालन करना चाहिए।

कश्मीर में नवोदय

जम्मू-कश्मीर में बुधवार को विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से संपन्न हो गया जो चुनाव बहिष्कार, पत्थरबाजी, हिंसा और अलगाववादी प्रवृत्तियों के लिए सुर्खियों में रहने वाले इस क्षेत्र को उम्मीद के एक नये उजाले में खड़ा करता है। अमेरिका, सिंगापुर, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, नाइजीरिया समेत 16 देश से आए प्रतिनिधि चुनाव देखने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। यह सभी राजनयिकों ने मतदाताओं से बातचीत की और मतदान को पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया। इन सभी राजनयिकों ने चुनाव प्रक्रिया के बारे में जो राय रखी हैं उससे लोगों को वर्तमान समय में राज्य की सुधरी भी स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्य में विधानसभा चुनाव को देखने के लिए विदेशी राजनयिकों का आमंत्रित करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। विदेशी राजनयिकों को आमंत्रित करने पर उमर की आपत्ति का जहां तक सवाल है तो उनसे समर्थन और सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कश्मीर में जो हालात बद से बदतर हुए उसके लिए अब्दुल्ला परिवार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी तो जम्मू-कश्मीर के हर चुनाव रैलियों में राज्य के संकट के लिए अब्दुल्ला परिवार को सीधे-सीधे कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेताओं की एक चिंता यह भी हो सकती है कि नेताओं ने भविष्यवाणियां की थी कि अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने से कश्मीर की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, लेकिन परिणाम इसके उलट आए। वस्तुतः होना तो यह चाहिए कि कश्मीर के नेता अनुच्छेद 370 को भूलकर सद्भावना और समन्वयपूर्ण वातावरण बनाएं जिससे कश्मीर का अनुच्छेद 370 विहीन पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो सके। दूसरी ओर कुछ कश्मीरी लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि वे अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने से आहत हैं। वास्तविकता यह है कि उनके मन मस्तिष्क में अलगाववादी विचार सर चढ़ कर बोल रहे हैं। इसलिए उन्हें प्रत्यक्षतः सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। इस सोच को बदलना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।

चिंतन/नृपेंद्र अभिषेक नृप

गांधी के सपनों का भारत

महात्मा गांधी का सपना एक ऐसे भारत का निर्माण करना था, जहां गांवों का विकास हो, न कि केवल शहरों का। भारत कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन विडंबना है कि विकास की मुख्यधारा शहरों में केंद्रित हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों को अपेक्षित महत्त्व नहीं मिल पाया है। अभी जब सरकारें ग्रामीण विकास के लिए तमाम योजनाएं बना रही हैं, तब भी निचले स्तर पर आवश्यक सेवा-सुविधाओं की कमी बनी हुई है।

स्वास्थ्य सेवा किसी भी समाज की नींव होती है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि शहरों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक प्रवाह है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्य केंद्र होते हैं, में अक्सर अच्छी सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों से वंचित रहते हैं। 2023 की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण कई लोग इलाज के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं। यह स्थिति गांवों में जीवन स्तर को नीचे लाती है। इसका समाधान यह हो सकता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अच्छे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उनके वेतन-भत्तों में अंतर रखा जाए ताकि वे शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी स्थिति दयनीय है। शहरों में जहां अच्छे शिक्षकों की अधिकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कम योग्य शिक्षक पाए जाते हैं। इसका परिणामतः वहां के छात्र अपेक्षित गुणवत्ता की शिक्षा से वंचित रहते हैं। ग्रामीण विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही। कई बार देखा जाता है कि गांवों में चल रही योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना जरूरी है। शहरों और गांवों के बीच की असमानता को समाप्त करने के लिए गांवों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्तों, आवास भत्तों, और अन्य सुविधाओं का विस्तार करना होगा। गांवों में स्थानीय नेतृत्व और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देकर लोगों को अपने विकास की दिशा में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करना होगा।

क्या कम हो पाएंगे यौन अपराध

चाइल्ड पोर्न

अखिलेश आर्येन्दु

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ सोशल मीडिया के दौर से पहले भी हुआ करता था? लेकिन इतना नहीं कि पानी सिर के ऊपर से गुजर जाए। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया और इंटरनेट के दुरुपयोग की घटनाएं भारत में ही हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं, बल्कि चीन, अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे तमाम देशों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है।

गृह मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो और अमेरिका की एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रेन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का अनुमोदन किया गया था। उसके मुताबिक बच्चों के पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों को हटाने के लिए इंटरनेट कंपनियों को पुलिस को सूचित करना जरूरी है। एजेंसियों ने सलाह दी है कि पोर्नोग्राफी का प्रसार करने वाले सभी तरह के एप्स और दूसरे तरह की सामग्रियों को हटाना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस आपराधिक मामले दर्ज कर सकती है। यदि कंपनियों ने कानून का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जाहिर तौर पर आज सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर पोर्नोग्राफी ही नहीं है, बल्कि अरबों की तादाद में तन-मन को खराब करने वाली सामग्रियां अटी पड़ी हैं। आज के दौर में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सामग्री डाउनलोड करने, देखने, अग्रेसित करने और साझा करने के मामले में अभी तक तकरीबन आजाद था, लेकिन सितम्बर को जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इन सभी कवायदों को उत्पीड़न संरक्षण कानून (पॉक्सो) और इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी (आईटी) अपराध को देश की शीर्ष अदालत ने गैर-कानूनी यानी अपराध घोषित किया, वह भारतीय समाज में युवाओं में बढ़ रहे तरह-तरह के अपराधों और गंदी आदतों खासकर बाल यौन शोषण और किशोर यौन शोषण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का हंटर जैसा है। अब बच्चों के अश्लील वीडियो, चित्र, लेख, कार्टून, ऑडियो, टेली फिल्म या झटपट वीडियो को देखना, डाउनलोड करना, साझा करना, अग्रेसित करना या बनाना अपराध के दायरे में माने जाएंगे। इससे जहां बाल अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी वहीं जो लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बाल यौन अपराध को करने में थोड़ा भी झिझकते नहीं थे और बाल तस्करी, अश्लील वीडियो, ऑडियो, चित्र और टेली फिल्में गुपचुप तरीके से बना लेते थे और उसका नाजायज फायदा बाल यौन शोषण में लिप्त दलाल उठाते थे, वे भी पाक्सो और आईटी कानून के तहत अपराधी माने जाएंगे। भारत में फेसबुक, ट्वूटर, एक्स,

व्हट्सअप, इंस्ट्राग्राम, टेलीग्राम, यू-ट्यूब, अमेजन, स्नेप चैट, गूगल और ऐसी ही अनेक सोशल साइटों और मीडिया प्लेटफार्म से हर बड़े स्क्रीन मोबाइल प्रयोगकर्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी प्रयोगकर्ता को शायद ही पता हो कि अश्लील वीडियो बनाना, उसे लोड करना या लाइव दुष्कर्म देखने और दिखाना बहुत बड़ा अपराध है।

शायद यही वजह है सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म का इस्तेमाल हर व्यक्ति बेखौफ होकर करता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पिछले महज दस सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही बीस करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इस दौरान भयदोहन (ब्लैकमेलिंग) फुसलाने, नाम और मजहब छिपा कर आकर्षित करने, अश्लील और कामोत्तेजक शब्दों का इस्तेमाल कर विजातीय लिंग को फंसाने, लालच देने, झूठा रुतबा पेश करने, विश्वासघात करने, फरेब और पाखंड का सहारा लेने, झूठी तारीफ करने, मजबूरी का फायदा उठाने, यौनाचार के बारे में गंदी-गंदी बातें करने और अश्लील वीडियो बना कर उससे यौन संबंध स्थापित करने के अनगिनत मामलों के बरक्स में देखें तो शिकायत के बाद भी इनमें से कई मामलों पर कोई ढंग की कार्रवाई होती ही नहीं। इससे अपराधी या कामुक व्यक्ति अपनी हवस पूरी करने के लिए उससे या दूसरी बच्ची पर जाल डालना शुरू करता है। यौनापराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है। केंद्र और राज्य सरकारों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म को अपराध के अड्डे बनाने से रोकने के लिए जरूरी है कि यौन अपराध करने वाले के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनाएं कि अपराध करने वाला जब इस तरफ बढ़े तो उसकी रूह कांप जाए।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और पहले आ जाता तो उन लाखों बच्चों को यौन शोषण से बचाया जा सकता था जो अपराधी किस्म के लोग बच्चों को बहका-फुसला या अपहरण कर उनका गंदा वीडियो बना सेक्स बाजार की दुनिया में बेचते और गलत तरीके से धन उगाही करते थे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस सालों में महज भारत में ही बाल यौन शोषण जिसमें अश्लील वीडियो, अश्लील, डरावना वीडियो, बहका कर गुपचुप तरीके से बनाए जाने वाले बाल यौन से संबंधित वीडियो और खुलेआम सेक्स करने के तथाकथित फायदे वाले वीडियो जैसे तमाम तरह के वीडियो करोड़ों की तादाद में बनाए गए, सोशल मीडिया पर डाले गए, साझा किए गए और दूसरों के पास दबाव बनाने या फंसाने के मकसद से भेजे गए। आए दिन एक से बढ़ एक बाल यौन शोषण, यौन हिंसा और बाल यौन क्रूरता की इतने बड़े पैमाने में वीडियो, समाचार, सामग्री, चित्र और ऑडियो लोगों के पास आते रहते हैं। लगता ही नहीं कि लोगों को ऐसे गैर-कानूनी अपराध और पाप किस्म की कवायद के खिलाफ समाज कभी खड़ा हो। ऐसी कवायद करने वालों को पकड़वाने या उनका सामाजिक बहिष्कार करने की कभी एक भी घटना पिछले तीस सालों में एक बार भी सुर्खियों में आई हो! अब तो लगता है जैसे बाल यौन शोषण, बाल अपराध और बाल यौन हिंसा और बाल यौन क्रूरता जैसी कवायदें समाज का ही हिस्सा बन गई हैं, और समाज मूक बना उन्हें स्वीकार करता जा रहा है। बच्चों को ब्लैकमेल करना होता है तो उन्हें बहका कर या जबरन उठाकर उनके साथ जबरन यौन संबंध बनाकर वीडियो बनाना मामूली बात बन गई है। हैरानी की बात यह है कि इस ऐतिहासिक फैसले के समर्थन में समाज के जिम्मेदार लोग भी बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे। क्या शायद इसलिए कि जैसे दूसरे तमाम आदेश शीर्ष न्यायालय ने दिए थे और उनका पालन नहीं हुआ, कहीं इसका हश्र भी उसी तरह न हो?

(लेखक के निजी विचार हैं)

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और पहले आ जाता तो उन लाखों बच्चों को यौन शोषण से बचाया जा सकता था जिन्हें अपराधी किस्म के लोग बहका-फुसला या अपहरण कर गंदा वीडियो बना सेक्स बाजार की दुनिया में बेचते और गलत तरीके से धन उगाही करते थे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस सालों में महज भारत में ही बाल यौन शोषण से संबंधित वीडियो करोड़ों की तादाद में बनाए गए, सोशल मीडिया पर डाले गए, साझा किए गए और जिनके जरिए दबाव बनाए गए

खराब खाने से हर साल चार लाख से ज्यादा की मौत

- असुरक्षित या खराब खाने से हर साल दुनिया भर में बीमारियों के 60 करोड़ मामले सामने आते हैं
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस ग्रेबेयसस के मुताबिक, इससे 4,20,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं
- चिंताजनक यह है कि जान गंवाने वाले बच्चों में 70 फीसद बच्चे पांच वर्ष से कम उम्र के होते हैं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

चीन अपने यहां सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 63 कर रहा है ताकि आबादी में गिरावट के सिलसिले को धीमा कर सके। फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 64, जर्मनी में 65 और ब्रिटेन में 66 है। तो क्या भारत में भी समय आ गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 किया जाए? इसका यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस के तहत पेंशन योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा?

मिन्हाज मर्चेंट, लेखक
@MinhazMerchant

टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने का

वर्कलोड **रजनीश कपूर**

संजय दत्त की बहुचर्चित फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' का एक डायलॉग काफी हिट हुआ था जिसमें वो हर किसी को न घबराने की सलाह देते हुए कहते थे 'टेंशन लेने का नहीं-देने का'। परंतु शायद उस फिल्म में दिए गए संदेश को कुछ लोग गंभीरता से नहीं ले सके। इसीलिए वे मामूली से तनाव को इतना बढ़ा लेते हैं जो कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो जाता है। इस फिल्म ने कठिन परिस्थितियों को गंभीरता से न लेने की सलाह दी परंतु आजकल के 'वर्क प्रेशर' और प्रतिस्पर्धा के चलते हर दूसरा व्यक्ति तनाव में दिखाई देता है।

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पुणे की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाली 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐना सेबेस्टियन की मां की चिट्ठी काफी चर्चा में रही। भारत में इस कंपनी के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में ऐना की मां ने उल्लेख किया कि किस तरह उनकी पुत्री पर कंपनी ने काम का दबाव बनाया हुआ था। मात्र चार महीने की नौकरी में दबाव इतना बढ़ गया कि इसने ऐना की जान ले ली। इस दबाव का स्पष्ट उदाहरण तब भी दिखा जब ऐना के अंतिम संस्कार में कंपनी में काम करने वाले सहकर्मी भी नहीं पहुंचे। जैसे ही ऐना की मां का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही इस कंपनी में काम कर चुके पूर्व कर्मचारियों ने अपने भयानक अनुभव भी साझा किए। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा वैसे ही कंपनी की ओर से 'वर्क प्रेशर' का खंडन किया गया। वैसे सरकार ने मामले में जांच बैठा दी है। ऐना की मृत्यु ने कॉरपोरेट जगत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, 'वर्क प्रेशर' के बढ़ते हुए तनाव के कारण दुनिया भर से ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे रहने के चलते कई लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। चीन में एक व्यक्ति ने लगातार 104 दिनों तक बिना किसी छुट्टी के काम किया और अंततः शरीर के कई अंगों की विफलता के कारण उसकी मौत हुई। वहां की अदालत ने उस व्यक्ति की कंपनी को उसकी मौत का 20 प्रतिशत तक जिम्मेदार ठहराया। वहीं अमेरिका के एक बैंक कर्मचारी की मृत्यु का कारण भी उसके काम का दबाव ही बना। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां कर्मचारियों से अधिक काम करवाने के चलते ऐसे हादसे हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में काम के दबाव- तनाव के चलते प्रति वर्ष करीब 7.50

लाख लोगों की मृत्यु होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अधिक काम करने का सीधा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है। काम का तनाव लेने से मनुष्य में हृदय रोग, डायबिटीज और स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं आज के सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में जब हम घंटों कंप्यूटर के सामने बैठ कर काम करते हैं, तो हमारे जोड़ों में जकड़न, कमर में दर्द, सरदर्द, आंखों में थकान, जैसे प्रारंभिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। तनाव के चलते हमारे शरीर में ऐसे रसायन पैदा हो जाते हैं, जो रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देते हैं। इसलिए हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तनाव के चलते जब गाड़ी चलाकर हम अपने दफ्तर से घर या घर से दफ्तर जा रहे होते हैं, तो ऐसे में दुर्घटना होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मोबाइल फोन और ईमेल के चलते हम हर समय अपने काम से जुड़े रहते हैं। इसलिए हमें काम से आराम नहीं मिल पाता। ऐसे तनाव का सीधा अनुभव आपको उस समय होता होगा जब आपके मोबाइल पर आपके बॉस का फोन बजता होगा। आप यदि अपने घर पर हों और परिवार के साथ समय बिता रहे हों, तभी आपके बॉस का फोन बजे तो आपके चेहरे पर अजीब से तनाव की झलक मिल जाती है। ऐसे में पारिवारिक सुख को भी झटका लगता है।

जानकारों के अनुसार, सप्ताह में 55 घंटे या उससे अधिक काम करने वालों में तनाव बढ़ने की संभावना अधिक होती है। तनाव अन्य बीमारियों को बढ़ावा देता है परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सफल होने के लिए कम मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत किसी को कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए हमें परिश्रम और अतिश्रम के बीच एक को चुनना चाहिए। परिश्रम किया जाए तो एक सीमा तक ही किया जाए। आपको अपने शरीर की क्षमतानुसार ही काम करना चाहिए। समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाते रहना चाहिए। नियमित रूप से तनाव-मुक्ति के कई साधन जैसे योग, ध्यान, भजन, मनोरंजन आदि का सहारा लेना चाहिए। अगर इम्प्लॉयर की बात करें तो उन्हें भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के चलते कर्मचारियों पर दबाव बनाना पड़ता है परंतु यह दबाव भी एक सीमा तक ही दिया जाए। हमारे समाज को काम और आराम के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है वरना ऐना सेबेस्टियन जैसे कई और होनहार कर्मचारियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। आजकल के युवा भी जल्द कामयाबी पाने के चक्कर में काम और आराम में संतुलन नहीं बना रहे हैं। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसलिए हर युवा और वरिष्ठ कर्मचारी को 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' फिल्म से सीख लेते हुए 'टेंशन न लेने' की आदत डाल लेनी चाहिए।

भयातुरता **श्रीराम शर्मा आचार्य**

भय में अपनी दुर्बलता की अनुभूति प्रथम कारण है और दूसरा है-हर स्थिति को अपने विपरीत मान बैठना। मन में आशंका व्यक्ति विवेकशीलता खो बैठता है, और कहा तो यहां तक जाता है कि वह अपनी परछाई से भी भयग्रस्त रहने लगता है। इस कदर कि एक आशंकाग्रस्त व्यक्ति भोजन में विष मिला होने की कल्पना करके स्त्री द्वारा बनाए, परोसे जाने पर भी शंकाशील रहते हैं। ग्रह नक्षत्रों तक के प्रतिकूल होने, दूरस्थ होने पर भी विपत्ति खड़ी करने की कल्पना करते रहते हैं। जैसा का तैसा मिल भी जाता है। डरपोकों को और अधिक डराने वाली उक्तियां बताने और घटनाएं सुनाने वाले भी कहीं न कहीं से आ टपकते हैं। अपने ऊपर भूत के आक्रमण की आशंका हो तो वैसी चर्चा करते ही ऐसे लोग तत्काल मिल जाएंगे जो उस भय का समर्थन करने वाले संस्मरण सुनाने लगें। भले ही वे सर्वथा कपोल-कल्पित ही क्यों न हों। हां में हां मिलाने की आदत आम लोगों की होती है। भ्रान्तियों का खण्डन करके सही मार्गदर्शन कर सकने योग्य बुद्धिमानों और सत्याग्रहियों की बेतरह कमी हो गई है। गिरे को गिराने वाले 'शाह मदारों' की ही भरमार पाई जाती है। फलतः भ्रमग्रस्तों को और अधिक उलझन में फंसा देने वाले ही राह चलते मिल जाते हैं। भ्रान्तियों के बढ़ने का सिलसिला इसी प्रकार चलता रहता है। ताओ धर्म के प्रवर्तक लाओत्स ने एक दृष्टान्त लिखा है-यमराज ने प्लेग को दस हजार व्यक्ति मार लाने के लिए हुकम दिया। वह काम पूरा करके लौटे तो साथ में एक लाख मृतकों का समुदाय था। यमराज ने क्रुद्ध होकर इतनी अति करने का कारण पूछा। मौत ने दृढ़तापूर्वक कहा-'उसने दस हजार से एक भी अधिक नहीं मारा। शेष लोग तो डर के मारे खुद ही मर गए हैं। मस्तिष्क को शान्त रखने में इच्छित परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अपने सोचने का तरीका बदल देने और तालमेल बिठाते हुए सौम्य और शान्त स्तर का जीवन यापन करने की कला सीखने और अभ्यास में उतारने भर से काम चल सकता है। दरअसल, जरूरी है कि हम मन से इतने दृढ़ और आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएं कि किसी भी प्रकार की शंका हमारे पास भटकने भी न पाए।

रीडर्स मेल

कंगना की बेतुकी बयानबाजी

बीजेपी सांसद एवं फिल्म स्टार कंगना रनौत, जो पहली बार सांसद बनी हैं, को अपनी बयानबाजी में संयम का परिचय देना चाहिए। तीन कृषि कानूनों, जिन्हें स्वयं प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया था, को फिर से लाने की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। कंगना को फिल्मों की तरह राजनीति में भी लंबी पारी खेलना है तो संसद की गतिविधियों में भाग लेते हुए राजनीति का ककहरा सीखना चाहिए। किसी भी राजनीतिक विषय में बोलने से पहले उस विषय का गहन अध्ययन करना चाहिए। कारण, बिना विचारे जो बोलता है, उसे पछताना भी पड़ सकता है। पता नहीं क्यों जब से वे सांसद बनी हैं, तब से बोलने के मामले में कुछ ज्यादा ही मुखर हो गई हैं। हम तो मानते हैं कि वह साहसिक महिला हैं परंतु साहसिकता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी विषय में बिना विचारे कुछ भी बोलें। पिछले दिनों राहुल गांधी पर भी उनकी बयानबाजी उचित नहीं कही जा सकती है। राजनीति में सोच विचार कर बोले गए बोल ही पूजाते हैं वरना तो छिछालेदारी होते भी देर नहीं लगती।

मनमोहन राजावतराज, शाजापुर, मप्र

न्याय मिलना ही चाहिए

जहां करना चाहिए था पुलिस अधिकारियों पर गर्व वहीं मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ उठा रही है सवाल। बदलापुर यौन उत्पीड़न अक्षय शिंदे एनकाउंटर में मारा गया। न्यायपालिका जानती है कि आरोपी कौन है। आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है तो इतना बवाल क्यों? आखिर, कब तक हम न्यायपालिका के भरोसे बैठे रहेंगे। अभी तक मोमिता के आरोपियों को फांसी हो जानी चाहिए थी। आखिर, क्यों बचाया जा रहा है आरोपी को। जिस प्रकार बहन प्रियंका रेड्डी को न्याय मिला था, उसके आरोपियों का एनकाउंटर किया गया। निर्भया को न्याय मिला था, ठीक उसी प्रकार बदलापुर कांड है। उसी प्रकार बहन मोमिता के आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी आरोपी ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी न सके। क्या बहन-बेटियों की आवाज न्यायपालिका में केवल आवाज ही बन रह जाएगी या मिलेगा न्याय? आखिर, इतनी देरी क्यों? पूछती हैं भारत की बेटियां।

मिस इंग्लिश, आईआईएमसी, जम्मू

बंदूक से नहीं निकलेगा समाधान

कश्मीर में अलगाववादियों का मुद्दा गोली और बंदूक से नहीं सुलझने वाला क्योंकि जिस दिन बंदूक शांत होंगी, उनके हाथों में बेरोजगारी का दर्द और टूटे सपनों की गूंज बाकी रह जाएगी। यह समस्या राजनीतिक से कहीं ज्यादा सामाजिक-आर्थिक है। कश्मीर के युवाओं को जब तक शिक्षा और रोजगार के सही अवसर नहीं मिलेंगे तब तक अलगाववाद की आग बुझाना मुश्किल होगा। सरकारें अक्सर सोचती हैं कि कठोर कदम और सख्त कानून से समस्या का समाधान हो जाएगा लेकिन असल में उन्हें समझना होगा कि जनता का दिल जीतने की जरूरत है, न कि डराने की। हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहां बड़ा अवसर है सामाजिक संवाद और विकास का जो सही तरीके से किया जाए तो अलगाववाद की जमीन को खोखला किया जा सकता है। कश्मीर के हर घर में रोजगार और हर युवा के पास भविष्य का सपना होगा तो बंदूक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

अवनीश कुमार गुप्ता, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 44
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहारा तल, नरेन्द्र हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR/GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 27 सितंबर 2024

तैयारी क्यों नहीं

अगर मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है तो पुणे को भी सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। देश के इन दो महत्वपूर्ण शहरों का पिछले दो दिनों में भारी बारिश ने जो हाल किया, वह हमारी टाउन प्लानिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारिश से उपजे हालात के ही चलते ही गुरुवार को पुणे की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द करनी पड़ी।

उड़ानें बाधित | बुधवार को हुई भारी बारिश ने ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया था। उड़ानें तो बड़ी संख्या में बाधित हुई ही, रेल और सड़क यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। शहर इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर ही रहे थे कि मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया।

मुंबई-पुणे बारिश से बेहाल

स्कूलों में छुट्टी | इसे देखते हुए प्रशासन ने तत्काल सार्वजनिक अपीलें जारी करनी शुरू कर दी। मुंबई में लोगों से बहुत जरूरी न होने पर घर ही में रहने को कहा गया। स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घरों से ही काम करने को कह दिया।

फंसे रहे लोग | असल में इस तरह घरों में बैठकर सुरक्षित महसूस करने की सुविधा आबादी के एक छोटे से हिस्से को ही मिलती है। एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है, जिसे रोज कमाना पड़ता है। इन लोगों को किसी भी हालात में घर से बाहर निकलना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार की इन घोषणाओं के बावजूद न केवल बड़ी संख्या में लोग जहां-तहां फंसे रहे बल्कि कुछ लोगों के मरने की भी खबरें हैं।

सरकार का प्रयास | नैशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की 18 टीमें और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (SDRF) 6 टीमें राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तैनात हैं। अन्य विभागों के कर्मचारी भी हालात से निपटने के प्रयासों में पूरी ताकत झोंके हुए हैं।

सवाल तैयारियों का | दिक्कत यह है कि ये सारे प्रयास तात्कालिक स्वरूप के हैं। सवाल तो तैयारियों का है। मुंबई महानगरपालिका देश की सबसे अमीर महानगरपालिका है। करीब 60 हजार करोड़ रुपये का उसका सालाना बजट है। फिर भी अगर अंधेरी में पानी से डूबी सड़क पर खुले मैनहोल में गिरकर एक महिला की मौत हो जाती है तो सवाल उठता है कि समय रहते इन नरभक्षी मैनहोलों को बंद करने जैसे काम यह महानगरपालिका क्यों नहीं करवा पाती। बात सिर्फ मुंबई या पुणे तक सीमित नहीं है। देश के तमाम बड़े शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटिनेंस की नाकामी उजागर होने के लिए महज एक आपदा काफी होती है। इस पर राष्ट्रीय नजरिए से समन्वित प्रयास की जरूरत है।

बात बराबरी की

अगर वे नेतृत्व करतीं

शैलेंद्र पांडेय

जॉर्ज बिल्कुल अकेला था। 1971 में जब वह इक्वाडोर के पिंटा द्वीप पर मिला, तब उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा था। उस समय तक जॉर्ज ने जीवन के करीब 6 दशक देख लिए थे। अगले 41 साल भी उसके इसी अकेलेपन में बीते। 2012 में जब उसने अंतिम सांसें लीं, तो उसके साथ उसकी पूरी प्रजाति भी खत्म हो गई। Lonesome George गैलापागोस द्वीप समूह के पिंटा आईलैंड पर पाई जाने वाली कछुओं की प्रजाति का अंतिम सदस्य था, और एक और उदाहरण जहां इंसानों के चलते किसी जाति का समूल नाश हो गया। UN की रिपोर्ट कहती है कि जानवरों और पेड़-पौधों की करीब 10 लाख प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से ज्यादातर के खात्मे के लिए जिम्मेदार होगा और है इंसानी लालच।

साइकॉलजिस्ट रिचर्ड डी राइडर का दिया टर्म है, Speciesism। इसका मतलब है अपनी प्रजाति के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रह। इस विचार के हिसाब से दूसरे जीव-जंतुओं की तुलना में इंसान खास है, उसे ज्यादा अधिकार हासिल है और उसके लिए सब जायज है। इस सोच ने अनगिनत प्रजातियों को खत्म कर दिया। इवॉल्यूशन के जिस दौर में यह सोच पनपी, क्या उसी दौर में इसे बदला जा सकता था?

बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा एक से अधिक मौकों पर कह चुके हैं कि अगर दुनिया में महिला नेता ज्यादा होतीं, तो यहां ज्यादा शांति होती। तो क्या महिलाएं Speciesism के तंग नजरिये को बदल सकती थीं? शायद, अगर हमारा विकास पुरुषों के नियंत्रण में आगे न बढ़ा होता और उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होती। महिलाओं को प्राकृतिक रूप से ज्यादा दयावान और करुणामय माना जाता है। उनके इस व्यवहार के पीछे विकास क्रम का भी योगदान है, जहां उनकी भूमिका परिवार को संभालने और देखभाल की थी। उनका यही रोल हमें आज भी दिखता है। दूसरी ओर, पुरुष इस जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ पले-बढ़े कि उन्हें हर हाल में परिवार की जरूरतों को पूरा करना है। सहज रूप से करुणा दोनों में है, लेकिन दोनों का रूप अलग है। पुरुषों की करुणा आक्रामक है, जबकि महिलाओं की सुरक्षात्मक। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रफेसर शैली टेलर ने महिलाओं और पुरुषों के इस अंतर पर रिसर्च की है। उनका कहना है कि मुश्किल हालात में पुरुषों की प्रतिक्रिया होती है, लड़ो या भागो। वहीं, महिलाएं परिस्थितियों से तालमेल बिठाने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करती हैं।

ऐसे में, एक संभावना बनती है कि अगर महिलाओं को नेतृत्व में बराबर मौका मिला होता, तो शायद प्रकृति आज संकट में न होती। तब महिलाएं शायद परिवार का पेट भरने और अन्य जरूरतों के लिए दूसरा रास्ता निकाल लेतीं। और शायद तब जॉर्ज अकेला न होता।

एकदा

गांधीजी की उदारता

बात उन दिनों की है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में थे। वह हर दिन संध्या के समय खुली हवा में घूमने के लिए जाया करते थे। वहां दोनों ओर पगडंडी थी और बीच में ही प्रधानमंत्री का आवास था। गांधीजी रोजाना गेट के सामने से गुजरते। गेट पर तैनात संतरी हर दिन गांधीजी को देखता। वह उन्हें पहचानता था, इसलिए कुछ नहीं कहता। एक दिन दूसरे संतरी की ड्यूटी लग गई गेट पर। वह गांधीजी को पहचानता नहीं था। जब महात्मा गांधी वहां से निकले तो उन्हें देखते ही संतरी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पीछे से गांधीजी को धक्का दिया और लात मारी।

Subrata Dhar

गांधीजी गिर पड़े। फिर संभल कर खड़े हो गए और संतरी से बात करने लगे। तभी घोड़े पर सवार एक गोरा उनके पास आया। वह गांधीजी का सम्मान करता था। पास आकर बोला, 'गांधीजी, मैंने सब कुछ देखा है। आप इस पर मुकदमा चलाइए। मैं आपकी ओर से गवाही दूंगा।' गांधीजी बोले, 'नहीं भाई, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। यह तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। यह मुझे नहीं जानता है।' गोरा घुड़सवार बोला, 'फिर भी ऐसे बदतमीज व्यक्ति को सबक तो सिखाना ही चाहिए।' गांधीजी बोले, 'यह अकेला सजा का पात्र क्यों बने? यहां तो सभी गोरे हिंदुस्तानियों के साथ खराब व्यवहार करते हैं। सजा मिले तो सभी को मिले।' यह सब देखकर वह संतरी गांधीजी के पैरों पर गिर गया। गांधीजी उसे उठाते हुए बोले, 'जाओ अपना काम करो।' गांधीजी को सलाम करके संतरी अपना काम करने लगा। गोरा घुड़सवार भी गांधीजी की उदारता के आगे नतमस्तक हो गया और अपनी राह पर चल पड़ा।

संकलन : रेनू सैनी

US में हुए हालिया सम्मेलन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा को लेकर मंच ने की अहम पहल

चीन को कैसे क़ाबू में करेगा Quad

हर्ष वी. पंत

कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में Quad लीडर्स के सम्मेलन में कहा, 'यह संस्था बनी रहेगी। सदस्य देश एक दूसरे से सहयोग करेंगे, आपसी साझेदारी भी होगी और तालमेल भी बना रहेगा।' मोदी ने बहुत कम शब्दों में इसके जरिये कई हलकों को संदेश दे दिया। इनमें वे भी शामिल थे, जो हमेशा Quad की आलोचना करते रहते हैं। और वे भी, जो इस मंच की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े करते रहते हैं।

भारत की भूमिका | आज दुनिया के जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए यह बात बहुत मायने रखती है। आज कई वैश्विक मंचों की अहमियत नहीं रह गई है। ऐसे में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाले Quad जैसे नए मंच को लेकर उनकी प्रतिबद्धता का साफ मतलब है। मतलब यह कि दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में नाटकीय बदलाव आया है। साथ ही, इस बदलती दुनिया में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है।

आपसी सहयोग | इसी को ध्यान में रखते हुए Quad की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। बेशक, इसकी रफ्तार धीमी रही है, लेकिन 2017 में इसके वजूद में आने के बाद से इस मंच ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है।

- हालिया सम्मेलन में Quad कैंसर मूनशॉट इनीशटिव का एलान हुआ। इसके तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में cervical कैंसर से लड़ने की पहल होगी।
- हिंद-प्रशांत में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस मंच के तहत सामूहिक पहल की जाएगी। इसके लिए हाई एफिशिएंसी और किफायती कूलिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे और उन्हें लगाया जाएगा।
- Quad STEM फेलोशिप के मार्फत चार साल की अवधि वाला इंजिनियरिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए टेक्निकल इंस्टिट्यूट का खर्चा भारत सरकार उठाएगी।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा को डिवेलप और लागू करने के लिए बुनियादी सिद्धांतों पर भी सहमति बनी है।
- सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन क्षेत्र में कंटिंजेंसी नेटवर्क सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग को भी सदस्य देशों ने अंतिम रूप दे दिया है।

पार्टनर्स की मदद | समुद्री सुरक्षा को लेकर Quad अब सक्रिय होता दिख रहा है। इसने हिंद-प्रशांत के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देश रीजनल पार्टनर्स के लिए ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जिसे (MAITRI) नाम दिया गया है। हिंद-प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रॉजेक्ट का भी एलान किया गया। इसके तहत चारों देश मिलकर एयरलिफ्ट कैपेसिटी बनाएंगे और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी कुदरती आपदा की सूरत में इससे राहत और बचाव कार्य में मदद मिलेगी।

पोर्ट इन्फ्रा | हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंडरसी केबल नेटवर्क्स की क्षमता बढ़ाने और मजबूत करने के सिलसिले में भी चारों देशों के बीच सहयोगी जारी है। इसके साथ इस बार के सम्मेलन में हिंद-प्रशांत में टिकाऊ और मजबूत बंदरगाह इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए सदस्य देशों के अपने-अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करने पर सहमति बनी। इसके लिए Quad Ports of the Future Partnership प्रोग्राम शुरू किया गया।

आलोचकों का रुख | Quad की आलोचना भी होती रही है। खासतौर पर इसकी धीमी रफ्तार को निशाना बनाया जाता है। आलोचक कहते रहे हैं कि जिन क्षेत्रों पर इसमें सहयोग की बात होती है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। वे चुनिंदा चीजों पर सहयोग करने की सलाह देते आए हैं। इस मंच में चार ऐसे देश शामिल हैं, जिनके रणनीतिक लक्ष्य एक हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने की क्षमता अलग-अलग। इस संदर्भ में खासतौर पर भारत दूसरों से अलग है। जहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी अलायंस पार्टनर्स रहे हैं, वहीं भारत की दिलचस्पी औपचारिक अलायंस में नहीं रही है। इसके बावजूद हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और सबके लिए खुला बनाए रखने को लेकर ये देश साथ आए हैं।

सुरक्षा की झलक | इस क्षेत्र में भविष्य में किस तरह की सुरक्षा होगी, उसकी उन्होंने एक झलक भी दी है। एक तरह से वे दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर और दक्षिणपूर्व एशिया में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए एक भरोसेमंद वैकल्पिक व्यवस्था देने में कामयाब रहे हैं। चीन शुरू से ही Quad को खारिज करता आया है। वह इसे नैटो का हिंद-प्रशांत वर्जन बताता आया है।

दिलचस्प इनोवेशन | आज दुनिया में भारी उथलपुथल मची ही है। ऐसे में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए नए आइडिया की जरूरत है। Quad हालिया वर्षों में शायद अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से सबसे दिलचस्प इनोवेशन है। 2007 में इस आइडिया को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके 10 साल बाद इसे शुरू किया जाना ही इसकी अहमियत जाहिर कर देता है।

(लेखक इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

10 साल में 'मेक इन इंडिया' से क्या मिला

संदीप वेम्पति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक पहले 25 सितंबर 2014 को 'मेक इन इंडिया' को लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य था भारत को ग्लोबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना। इसके लिए सरकार ने कई सुधार किए, कई नीतियां और योजनाएं लागू कीं। बिजनेस को आसान बनाने के लिए मंजूरी से जुड़े नियमों को आसान बनाया गया, GST और IBC जैसे सुधार किए गए। नीतियों के स्तर पर कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% (सरचार्ज और सेस छोड़कर) कर दिया गया। साथ ही, पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया, पीएम गति शक्ति और नैशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जैसी योजनाएं शुरू की गईं।

नई योजनाएं | मार्च 2024 तक सीमित समय के लिए कॉरपोरेट टैक्स रेट को घटाकर 15% (सरचार्ज और सेस छोड़कर) कर दिया गया था। ऐसा कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए किया गया था। भारत की निर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साल 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की शुरुआत हुई। साल 2014 के बाद जो मुक्त व्यापार समझौते हुए, उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। नए औद्योगिक शहरों के विकास के लिए नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। MSME पर ध्यान दिया गया।

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा | मेक इन इंडिया पर फोकस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है। साल 2013-14 में जो Gross Value Added 17.13 लाख करोड़ रुपये था, वह 2023-24 में 38.19 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2013-14 में रोजगार का डेटा 5.49 करोड़ था, जो 2022-23 में 6.31 करोड़ हो गया। FDI और माल निर्यात में भी बढ़ोत्तरी हुई है। 2004 से 2014 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 97.7 बिलियन डॉलर था और 2014 से 2024 के बीच यह 165.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया। Merchandise Exports 2013-14 में 314.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 437.06 बिलियन डॉलर हो गया।

आयातक से निर्यातक | PLI से 1.28 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ। इससे 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला और 10.8 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ। देश का निर्यात चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बढ़ा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वित्तीय वर्ष 2017 में 48 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 101 बिलियन डॉलर हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात भी बढ़ा। वहीं, रक्षा उत्पादन में 217% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। रक्षा क्षेत्र में भारत अब आयातक से निर्यातक बन गया है और 90 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद एक्सपोर्ट कर रहा है।

AI Image

कॉमन रूम

सेमीकंडक्टर पर फोकस | खिलौनों, वैक्सीन और रेल कोच का निर्यात भी बढ़ा है। आगे अब देश का सेमीकंडक्टर मिशन भारत में बनी चिप के निर्यात का रास्ता खोलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह ग्रोथ इसलिए खास है, क्योंकि दुनिया कम आर्थिक विकास और युद्ध जैसे मसलों से जूझ रही। यह कहना होगा कि मेक इन इंडिया के तहत जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उनके बारे में एक दशक पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने इस पर और ध्यान दिया है। 2024 के बजट में FDI को आसान बनाने और विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स रेट को कम करने की घोषणा हुई है। नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। बजट में महत्वपूर्ण खनिज मिशन और समुद्र से खनिज निकालने की योजनाओं की घोषणा भी की गई। मेक इन इंडिया के अंतर्गत मोदी सरकार चिप निर्माण, बायो-मैन्युफैक्चरिंग, शिप निर्माण और स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है।

दुनिया का कारखाना | भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं और मेक इन इंडिया के तहत उठाए गए कदमों की वजह से भारत दुनियाभर की कंपनियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। इससे देश एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में उभरेगा और इससे 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।

(लेखक अर्थशास्त्री और स्तंभकार हैं)

कश्मीर में पाकिस्तानी 'ज़हर' भी मुद्दा

पूनम पाण्डे

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब तीसरे चरण की यानी आखिरी राउंड की वोटिंग होनी है। चुनावी मुद्दों के अलावा ध्यान खींचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं। अलगाववादी नेता भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। यहां तक कि प्रतिबंधित संगठन के लोग भी निर्दलीय उम्मीदवार के जरिए चुनाव में शामिल हो रहे हैं।

खास बात यह कि कश्मीर और जम्मू दो अलग क्षेत्र ही नहीं हैं, दोनों की डेमॉग्रफी भी अलग है। दोनों के चुनावी मुद्दों में भी अंतर जाहिर तौर पर होगा ही। जम्मू रीजन में तीन ऐसे मुद्दे सामने आए जो जम्मू के पॉश गांधी नगर इलाके से लेकर नौशेरा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के गांवों तक में छाए हुए हैं। लोग इन मुद्दों पर सिर्फ बात ही नहीं कर रहे बल्कि यह उनके लिए चिंता का बड़ा विषय है। वे इन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट देने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन पोलिंग बूथ तक पहुंचते पहुंचते ये मुद्दे कितने हावी रहे या रहेंगे, यह नतीजों से साफ होगा।

10 साल पहले तक नहीं देखा था चिट्टा

इन चुनावों में जम्मू में ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। नौशेरा में सीमा से लगे गांव वालों ने कहा कि हमारे लिए चिट्टा (हेरोइन) पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यह हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। छोटे-छोटे बच्चे तक इसके आदी बन रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि दस साल पहले तक तो हमने चिट्टा देखा भी नहीं था। तब यहां ड्रग्स का कुछ असर नहीं था और ना ही इसकी बात होती थी। जब ड्रग्स की खेती यहां नहीं होती है तो फिर ड्रग्स यहां कैसे आ रहा है और क्यों इसे रोकने में सब असफल हैं? उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, ये ड्रग्स उन्हें मार देगा, भविष्य तो कुछ बचेगा ही नहीं।

इसी तरह की बातें सुंदरबनी के गांवों में भी लोगों ने कहीं। सुंदरबनी के कई गांव एलओसी के पास हैं। जम्मू में भी

ड्रग्स के बढ़ते असर को लेकर लोगों ने चिंता जाहिर की। गांधी नगर जम्मू के पॉश इलाकों में आता है। यहां लोगों ने बताया कि ड्रग्स की लत कई लोगों को ले डूब रही है। उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले ही एक बच्चा ड्रग्स खरीदने के लिए एसी की आउटडोर यूनिट चुराने की कोशिश कर रहा था और वह उसके पैर पर गिर गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 250 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त हुई। 2022 में इसकी मात्रा बढ़कर 300 किलोग्राम से अधिक हो गई। 2023 में 319 किलो ड्रग्स और इस साल पहले छह महीनों में ही 100 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुई। सीमा पार से लगातार ड्रोन के जरिए ड्रग्स के पैकेट गिराने के मामले भी सामने आते रहे हैं।

जम्मू में एलओसी के पास के इलाके अपनी बहुत सी जरूरतों के लिए सेना पर निर्भर रहते हैं। चाहे इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प हो या फिर पानी की जरूरत पूरी करनी हो, लोगों का आखिरी सहारा यहां सेना ही है। यहां से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं। लेकिन सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से यहां लोग नाराज हैं। चुनावी मुद्दे पूछने पर लोग अग्निवीर का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि सेना में नौकरी कर युवा जब रिटायर होकर आते थे तो वह इतने सक्षम होते थे कि अपना पक्का घर बना सकें या फिर अपने लिए दुकान खोल सकें। लेकिन अग्निवीर के तौर पर चार साल की नौकरी के बाद युवा क्या करेंगे, यह सवाल सबकी जुबान पर है।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मसला

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना ये मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए भी है और लोगों के लिए भी। BJP जहां अपने चुनाव प्रचार में आर्टिकल 370 हटाने को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए उसके नाम पर वोट मांग रही है, वहीं नैशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आर्टिकल 370 की वापसी की कोशिश करने का वादा कर रहे हैं। जम्मू में कुछ सीटों पर ऐसे समुदाय हैं, जो आर्टिकल 370 हटने से बेहद खुश हैं क्योंकि पहले उन्हें बराबरी का हक नहीं था और आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्हें बराबरी का व्यवहार मिल रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग और वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। वे इस कदम के लिए खुलकर सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने हमारा भला किया हम उनका साथ देंगे। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि आर्टिकल 370 हटने से उनका हक मारा गया। वे इसे रोजगार से जोड़कर देखते हैं। जम्मू के कई गांवों में लोगों ने कहा कि अब बाहर के लोग यहां आकर नौकरी ले रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है। वे इसे रोजगार के साथ ही सुरक्षा से भी जोड़कर देख रहे हैं। एलओसी के पास के गांव के लोगों ने कहा कि बाहर से कौन आ रहा है इसका हमें पता नहीं रहता। कौन चोर है और कौन गुंडा है, हमें कैसे पता चलेगा? वे अगर यहां अपराध करते हैं तो हम तो उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ न्याय पर भरोसा

27 सितंबर का संपादकीय 'जबान संभाल के' पढ़ा। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की विवादास्पद टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख महत्वपूर्ण है। यह न केवल न्यायपालिका के लिए, बल्कि समाज के सभी हिस्सों के लिए एक चेतावनी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय अखंडता और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह के मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसमें पारदर्शिता का भी सवाल उठा है। पारदर्शिता के बिना किसी को भी उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे कोर्ट की कार्यवाही में खुलापन और जवाबदेही सुनिश्चित हो पाएगी।

चिंतन शर्मा, ईमेल से

■ जांच में लापरवाही

यह पत्र 27 सितंबर के लेख 'एक्शन मिलावटी तो खाना शुद्ध कैसे मिलेगा' से संबंधित है। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक गंभीर मुद्दा है। यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मिलावट की वजह से तमाम लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट से लोगों की आस्था को भी ठेस लगी है। देखने वाली बात यह है कि जब त्योहारों में डिमांड दोगुनी, तिगुनी बढ़ जाती है, तो रातों-रात दूध और मावे की सप्लाई कैसे बढ़ जाती है। इस मामले में सख्त जांच की जरूरत है।

नीलेश कुमार, नोएडा

■ US से बेहतर रिश्ते

23 सितंबर को प्रकाशित संपादकीय 'बेहतरी की ओर' पढ़ा। भारत और अमेरिका के संबंध पहले के मुकाबले लगातार बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के साथ मधुर रिश्ते की शुरुआत 21वीं सदी से ही शुरू हो गई थी, भले ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष बदलते रहे हों। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर संतुलित रुख अपनाया और क्वॉड के मंच पर अपनी मजबूत भूमिका तय की। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता को रोकने की साझा जरूरत पर जोर दिया है।

माम चंदसागर, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

कंगना बोलीं, कृषि कानूनों पर अपना बयान वापस लेती हूं- खबर

- क्या कमान से और जबान से छूटा तीर वापस हो सकता है?

सुरेंद्र प्रसाद

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

प्रकृति सिखाती है ग्लोबलाइजेशन के सही मायने

सलिल पांडेय

पेड़-पौधे, जंगल, नदी-झरने, पर्वत-नदियां-सब सृष्टि के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। संस्कृत में 'वसुधैव कुटुम्बकम' का महामंत्र ऋषियों-मनीषियों ने इसीलिए दिया क्योंकि मानव जीवन के कल्याण के लिए प्रकृति के ये सारे अंश सहायक हैं। इसी वजह से हर आध्यात्मिक अनुष्ठान के प्रारंभ में संकल्प लिया जाता है, 'आपः शांति, वनस्पतयः शांतिः, अंतरिक्ष शांति, औषधयः शांति'। इस संकल्प के जरिए इनके अस्तित्व के कायम रहने की कामना करते हैं। भारत भूमि से उठने वाले इस महामंत्र ने पूरी सृष्टि को महत्व दिया। तभी तो इस मंत्र में ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा रची-बसी है।

हालांकि, जीवों में सर्वश्रेष्ठ मानव समुदाय ने इन संकल्पों से पीछे हटना शुरू कर दिया। विकास के नाम पर और स्वार्थ के चलते प्रकृति पर अंधाधुंध आक्रमण होने लगे। सबसे ज्यादा आक्रमण पेड़-पौधों और जंगलों पर हुआ। कुएं-तालाबों को भरकर अट्टालिकाएं खड़ी की जाने लगीं। कल-पुर्जों के बल पर नदियों की धाराओं को बंधक बना लिया गया। गगनचुंबी इमारतें ऐसी बन गईं कि जैसे पौराणिक कथाओं में सूर्य का मार्ग अवरुद्ध करने का उल्लेख है। जल स्रोतों में नगरीय क्षेत्रों से निकलने वाले कूड़े और औद्योगिक विषाक्त पदार्थों की भरमार हो गई है।

प्रकृति ने लंबे समय तक इन आक्रमणों को चुपचाप सहा, लेकिन जब सहनशक्ति जवाब देने लगी और अति की सीमाएं लांघी जाने लगीं, तब प्रकृति ने भी अपना अस्तित्व जताना शुरू किया। कोविड जैसी महामारी ने मानवता को बेचैन कर दिया। डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों ने भी जनहानि की। भूस्खलन, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने मानव समुदाय पर कहर ढाया। इन हालात में हम प्रकृति को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन, ये घटनाएं बार-बार हमें याद दिलाती हैं कि अगर प्रकृति सुरक्षित है, तो सब सलामत रहेगा। ऐसी घटनाएं एक चेतावनी और हमारे लिए सीख होती हैं। जैसे हमारे माता-पिता और शिक्षक हमारी गलतियों पर छोटी-सी सजा देकर अहसास दिलाते हैं, वैसा ही कुछ प्रकृति भी करती है। वह समय-समय पर हमें चेतावनी भेज रही है कि अब संभल जाओ। हाल के समय में जंगलों के हिंसक जानवर मानव बस्तियों में घुसने लगे हैं। जब इनका आशियाना उजड़ता है, तो मानव बस्ती की ओर रुख करना इनकी मजबूरी बन जाती है। जानवर प्रकृति पर हो रहे आघातों का बदला लेने लगे हैं। इंसान जब प्रकृति पर हमला करता है, तब कभी प्रभाव और कभी कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर बच जाता है, लेकिन प्राकृतिक सुरक्षा प्रहरी ये जंगली पशु अपना कानून चलाते हैं।

इसलिए, इन विषम स्थितियों से बचने के लिए हर हाल में प्रकृति की सुरक्षा जरूरी है। अन्यथा, आगे और भी भयानक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि मानवता की भलाई प्रकृति के संरक्षण में ही निहित है। अगर हम प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में असफल रहे, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज ही से हमें प्रकृति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

श्रीलंका के राष्ट्रपति

अनुरा कुमारा दिसानायके

अनुरा कुमारा दिसानायके का श्रीलंका का राष्ट्रपति बनना इस द्वीप देश में वंशवादी व मध्यमार्गी प्रशासन से परिवर्तन का संकेत है। श्रीलंका की वामपंथी 'जनता विमुक्ति पेरामुना'-जेवीपी के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को नए राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई जो इस द्वीप देश में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन है। श्रीलंका के प्रमुख वामपंथी व्यक्तित्व दिसानायके का सत्ता में आगमन ऐसे समय हुआ है जब श्रीलंका आर्थिक अस्थिरता, युद्ध-पश्चात समझौते की चुनौतियों तथा राजनीतिक पार्टियों के प्रति विश्वास के संकट का सामना कर रहा है। उनका राष्ट्रपति बनना न केवल श्रीलंका में एक नया अध्याय है, बल्कि इसके महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभाव, खासकर सबसे निकटस्थ पड़ोसी भारत पर भी पड़ेंगे। दिसानायके का चुनाव श्रीलंका में एक व्यापक राजनीतिक जागरूकता का भी प्रतीक है। इस देश पर दशकों से वंशवादी परिवारों तथा मध्यमार्गी गठबंधनों ने शासन किया है। सत्ता में लंबे समय तक रहे राजपक्षे परिवार ने ढांचागत विकास की एक विरासत छोड़ी, पर उसने श्रीलंका को आर्थिक संकट में भी फंसा दिया जिसमें भारी कर्ज-संकट भी शामिल है। दिसानायके का राष्ट्रपति बनना श्रीलंका की जनता में परिवर्तन की बढ़ती इच्छा का प्रतीक है। इसमें खासकर नौजवान शामिल हैं जो भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से अलग हट कर जवाबदेही व पारदर्शिता चाहते हैं।

वामपंथी होने के नाते दिसानायके की विचारधारा की जड़ें समाजवादी सिद्धान्तो में निहित हैं जिनमें संपत्ति के पुनः वितरण, भूमि सुधार तथा मजबूत कल्याणकारी नीतियां शामिल हैं। उनके राजनीतिक मंच ने आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने तथा हाशियाकृत समुदायों को मजबूत करने पर जोर दिया है। कठोर आर्थिक विभाजनों तथा नस्ली तनावों वाले देश में यह दृष्टिकोण एक नये संभावित परिवर्तन का संकेत देता है कि प्रशासन को जमीनी स्तर पर विकास व समावेशन पर जोर देते हुए काम करना चाहिए। उनके राष्ट्रपति बनने से उन नीतियों को बल मिल सकता है जो विदेशी निवेश पर समाज कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। भारत लंबे समय से श्रीलंका के राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। गृह युद्ध से लेकर द्वीप देश के आर्थिक दीवालियापन तक भारत ने लगातार उसे सहायता दी है, फिर चाहे वह वित्तीय सहायता हो, राजनयिक समर्थन या मानवीय सहायता। हालांकि, राष्ट्रपति के रूप में दिसानायके इन स्थितियों में नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। दिसानायके भारत के प्रति ज्यादा सतर्क दृष्टिकोण अपना सकते हैं। हालांकि, वे भारत-श्रीलंका संबंधों का महत्व स्वीकार करते हैं, पर वे श्रीलंका की संप्रभुता बनाए रखने तथा किसी एक देश पर अति-निर्भरता से बचने के बारे में मुखर रहे हैं। अपने शुरुआती भाषणों में दिसानायके ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के बजाय घरेलू आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता का संकेत दिया था जिसका अर्थ संभवतः ज्यादा संरक्षणवादी नीतियां हैं। इसका परिणाम भारतीय निवेशों की ज्यादा कठोर जांच हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ चीन से दूरी बनाना भी हो सकता है। राष्ट्रपति दिसानायके दो देशों के बीच खासकर कृषि, शिक्षा और सामाजिक विकास में ज्यादा गहरे सहयोग के रास्ते खोल सकते हैं। भारत श्रीलंका का मजबूत सहयोगी रहा है, पर चीन को शामिल करने की रणनीतियां भी दिसानायके का विदेश नीति दृष्टिकोण तय करेंगी। दिसानायके ने कर्ज-जाल राजनय के प्रति चिन्ता प्रकट की है जिससे श्रीलंका की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि अनुरा कुमारा दिसानायके के चीन के साथ कैसे संबंध रहते हैं।

पर्यटन पर पीएम मोदी का विज़न

इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हमारे बीच एक ऐसे नेता हैं जो न केवल हमारे प्रधानमंत्री हैं बल्कि वे अतुल्य भारत के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर और हिमायती हैं।

गजेन्द्र सिंह शेखावत
(लेखक, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं)

एक दशक पहले तक भारतीय पर्यटन को पर्यटन क्षेत्र में अन्य देशों के समकक्ष या उनसे आगे स्थापित करने के लिए भी एक ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत सामान्य बात थी। जिस तरह अन्य देश अपने देश के पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु सुविख्यात फिल्मी सितारों और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन राशि खर्च कर रहे थे ठीक उसी तरह यहां भी यह महसूस किया गया कि अतुल्य भारत कोएक नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

पिछले एक दशक में और पिछले 100 दिनों से भारत के केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैंने सभी को यह कहते सुना है कि इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हमारे बीच एक ऐसे नेता हैं जो न केवल हमारे प्रधानमंत्री हैं बल्कि वे अतुल्य भारत के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर और हिमायती हैं। अपनी हर भूमिका में, वे भारत की बेहतरी के लिए काम करते हैं। मैं यह देखकर अत्यंत विस्मित और प्रेरित होता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री सदैव पर्यटन को अत्यंत महत्व देते हैं।

एक प्रधानमंत्री के रूप में वे निरंतर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें देश में पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास के लिए 'सरकार के प्रत्येक स्तर' पर कार्य करना है। लगभग 1,50,000 किलोमीटर लम्बा सड़क नेटवर्क बनाए जाने, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए 500 नए हवाई रूट और 150 हवाईअड्डे शुरू किए जाने, तेज गति वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत और लगभग 100 पर्यटन परियोजनाओं को पूरा किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में 250 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएं (डीटीवी) दर्ज की गईं जो वर्ष 2014 में भारत द्वारा दर्ज 128 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) का लगभग दोगुना है।

इस राष्ट्र के वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में वे अतुल्य भारत के विस्मयकारी पहलुओं को विश्व के समक्ष रखने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की जी-20 अध्यक्षता इस मायने में अनूठी रही कि इन बैठकों का आयोजन देश भर के 60 अलग-अलग स्थानों पर किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन था कि भारत की जी-20 अध्यक्षता को माध्यम बनाकर इन 60 गंतव्यों की पर्यटन पेशकशों के साथ-साथ उनकी संस्कृति, क्विज़ीन तथा शिल्प की वैश्विक मंच पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। पिछले वर्ष जी-20 के कारण पर्यटन में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 में भारत के पर्यटन क्षेत्र में होटल के नए कमरे सबसे अधिक संख्या में बनाए गए।

एक जन-नायक के रूप में उन्होंने विश्व की यात्रा पर निकलने से पहले अपने देश भारत को देखने-समझने के लिए राष्ट्र को 'देखो अपना देश' हेतु प्रेरित किया है। स्वच्छता के महत्व की सीख देकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उत्तरदायी पर्यटन हम सभी का सहज स्वभाव बन जाए। हर अवसर पर वे वैश्विक प्रवासी भारतीयों को अतुल्य भारत का प्रतिनिधि बनने की उनकी भूमिका निरंतर याद दिलाते हैं कि वे अपने विदेशी मित्रों और परिचितों को इस बात की जानकारी दें कि भारत की यात्रा किस प्रकार उनके लिए अविस्मरणीय हो सकती है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक के रूप में उनके द्वारा लक्षद्वीप, काजीरंगा, कन्याकुमारी, श्रीनगर और अन्य कई स्थलों की यात्रा करने मात्र से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में ऐसे गंतव्यों की यात्रा करने और भारत की कम लोकप्रिय पर्यटन पेशकशों का अनुभव करने की अभूतपूर्व रुचि देखी गई है।

पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री की निजी रूचि और भागीदारी को और अधिक स्पष्टकरने के लिए मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पर्यटन विभाग में मुझे अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर देते समय कहा था कि वे मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहे हैं ।तब से मेरानिरंतर यह प्रयास रहा है कि समावेशी सामाजिक-आर्थिक प्रगति और विकास के माध्यम के रूप में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमभारत में इसके लिए एक व्यावसायिक योजना तैयार करें।

अवसंरचना विकास में भारत द्वारा तेजी से की जा रही प्रगति का लाभ उठाते हुए नए पर्यटन गंतव्य विकसित करना इस व्यावसायिक योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए और अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इन नए गंतव्यों की परिकल्पना की गई है । वर्ष 1947 में हमारी स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 2014 तक भारत में किसी पर्यटक गंतव्य को शुरूआत से समग्र और समावेशी तरीके से विकसित करने का एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है । वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विश्व को एकता नगर और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की भेंट देने के बाद से इसमें परिवर्तन आया है।

माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप एकता नगर में पर्यटन को प्रमुख आधार के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए और अनेक उपाय किए गए । रोजमर्रा के आधार पर गंतव्य के रख-रखाव और प्रबंधन के लिए विशिष्ट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और शासन प्राधिकरण स्थापित करने के साथ-साथ अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई । स्थानीय लोगों और युवाओं को पर्यटन से संबंधित सेवाओं और कार्यों के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई। अच्छे होटल, रिजॉर्ट और अन्य आवास स्थापित करने के लिए निजी निवेशों को शामिल किया गया । पीपीपी मोड में विभिन्न थीमों में अनेक नए आकर्षणों, कार्यकलापों और अनुभवों की शुरूआत की गई।

इन सभी और अन्य कई कार्यकलापों के कारण एकता नगर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 4.5 लाख से 10 गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 45 लाख हो गई थी । इसके अलावा, इन सभी प्रयासों से एकता नगर के स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन अर्थव्यवस्था के माध्यम से आजीविका के नए साधन का सृजन हुआ है जो वर्ष 2014 से पहले इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था । एकता नगर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने हमें पर्यटन विकास और संवर्धन का एक नया मॉडल दिया है - एक ऐसा मॉडल जिसे ऐसे प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का सृजन करने के लिए एक उदाहरण के रूप में अपनाया जा सकता है।

स्वदेश दर्शन और प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों के विकास जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, पर्यटन मंत्रालय अब 'सरकार के हर स्तर पर'चयनित गंतव्यों को विकसित करने के संयुक्त प्रयासों द्वारा देश में पर्यटन संबंधी गंतव्य विकास कीअगुआई कर रहा है। ऐसे अधिक प्रभावकारी हस्तक्षेपों की शुरूआत के प्रयास किए जा रहे हैं जो विभिन्न गंतव्यों में पर्यटक अनुभव को पूरी तरह से बदल सकते हैं। साथ ही, निजी निवेश को सार्वजनिक निवेश का पूरक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भारत में पर्यटन संबंधी गंतव्य विकास के लिएदोनों एक संयुक्त शक्ति के रूप में कार्य कर सकें। इन गंतव्यों में मंत्रालय की विभिन्न पहलों के माध्यम से, कौशल निर्माण और डिजिटलीकरण जैसे पर्यटन साधनों को बेहतर बनाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही हैताकि पर्यटन के लाभ उस गंतव्य में ही स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों को प्राप्त हो सकें।

प्रधानमंत्री के जन भागीदारी के विजन से प्रेरित होकर, मंत्रालय ने देखो अपना देश पीपुल्स च्वाइस 2024 नामक एक राष्ट्र-व्यापी पोल शुरू किया है ताकि नागरिक 5 श्रेणियों में भारत में अपने सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों और गंतव्यों के बारे में जानकारी दे सकें । आगे बढ़ने के अपने प्रयासों में जनता की आवाज को शामिल करने के लिएपीपुल्स च्वाइस 2024 में शीर्ष पर आने वाले गंतव्यों को विशेष सहायता और निधि प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें दुनिया के समक्ष सर्वश्रेष्ठ अतुल्य भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक पर्यटन स्थलों के रूप में परिवर्तित किया जा सके।

ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब माननीय प्रधानमंत्री हमें विकसित भारत के अपने विजन की याद न दिलाएं । पर्यटन हमें उस महान विजन को पूरा करने के लिएअनेक अवसरप्रदान करता है। इस विश्व पर्यटन दिवस पर, मैं इस विजन को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं, ताकि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की ही तरह अतुल्य भारतीय बन सकें।

महिला सशक्तीकरण एवं बच्चों का पोषण

अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से, परिवारों को पौष्टिक घर का बना भोजन खाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

स्वप्ना मजूमदार
(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं)

कुछ साल पहले, जब चेतना, महिलाओं, किशोरों और बच्चों के बीच स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता पर काम करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था, एक सर्वेक्षण कर रही थी, तो उसने पाया कि अहमदाबाद, गुजरात के वासना की शहरी झुग्गी में रहने वाले बड़ी संख्या में बच्चे, किराने की दुकानों पर मिलने वाले पैकेज्ड आलू के चिप्स और अन्य अस्वास्थ्यकर स्नैक्स के लगभग आदी हो चुके हैं। वे अक्सर घर का बना खाना नहीं खाते थे, बल्कि ऐसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते थे।

परिणामस्वरूप, उनमें से कई कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित हो गए। बच्चों को पैकेज्ड फूड से दूर रखने के लिए चेतना ने जो रणनीति अपनाई, उनमें से एक यह थी कि पारंपरिक गुजराती स्नैक्स और पूरक खाद्य पदार्थ जैसे शेरो, सुखदी और लाड कैसे स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हो सकते हैं। माताओं और देखभाल करने वालों की मौजूदगी में उन्हें पकाने से उन्हें अपने बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के नए तरीके सीखने में मदद मिली। पांच सप्ताह तक 1 से 5 साल के कम वजन वाले बच्चों को प्रोटीन, वसा और आयरन युक्त पूरक आहार भी दिया गया। चेतना टीम ने सप्ताह में तीन बार एक निश्चित समय पर परिवारों का दौरा किया और 30 मिनट की पद्धति अपनाई।

इसका मतलब यह सुनिश्चित करना था कि बच्चा 30 मिनट तक बैठा रहे जबकि देखभाल करने वाले उसे घर का बना खाना खिलाएँ। प्रत्येक बच्चे के लिए, 36 बार घर का दौरा किया गया। हस्तक्षेप के सात से नौ महीनों के भीतर, बच्चे केवल घर का बना खाना खा रहे थे। उनकी कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए, उनके मेनू में गेहूं के आटे और बंगाल चने के मिश्रण से बनी रेसिपी भी शामिल की गई। धीरे-धीरे बच्चों द्वारा खाए जा रहे अन्य पोषक तत्वों के साथ-साथ कैलोरी भी बढ़ गई। नौ महीने के अंत में 166 कम वजन वाले बच्चों का वजन किया गया, जिनमें से 36त्र बच्चे पूरी तरह से पोषित पाए गए। केवल पैकेट वाला खाना खाने वाले सभी 35 बच्चों ने घर का बना खाना खाना शुरू कर दिया। इस आदत को बनाए रखने के लिए, चेतना ने इन झुग्गियों में रहने वाले आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की माताओं और अन्य महिलाओं को कौशल प्रदान करने का विचार बनाया ताकि वे भी ऐसे पौष्टिक नाश्ते बनाकर आर्थिक रूप से लाभ उठा सकें। अगस्त 2023 में, उन्होंने इन झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं को दोनों काम करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया - अपने बच्चों को अस्वास्थ्यकर नाश्ते से दूर करके घर के बने खाने की ओर ले जाना और साथ ही पोषण-उद्यमी बनना।

25 महिलाओं के पहले बैच ने आहार, स्वस्थ खाने के महत्व और नाश्ते में पोषण जोड़ने के बारे में कुछ पाठों के साथ शुरुआत की। पोषण संबंधी शिक्षा को बढ़ाने के अलावा, उन्हें पैकेजिंग, मार्केटिंग और व्यवसाय प्रबंधन के बारे में सलाह दी गई।

झुग्गी में एक रसोई स्थापित की गई और महिलाओं को पेशेवर होने और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने खजूर के लड्डू, रागी और चुकंदर के शकरपारे जैसे बाजरे से बनी पारंपरिक खादी और साथ ही स्वादिष्ट फूले हुए बाजरे और नाचोस जैसी पौष्टिक मिठाइयां बनाना सीखा।

महिलाओं ने अपने उत्पादों को पड़ोसियों के साथ-साथ दुकानदारों को भी बेचना शुरू कर दिया। 2024 के पहले तीन महीनों में, 25 महिलाएं लगभग 60,000 किलोग्राम घर का बना नाश्ता बेचने में सक्षम थीं। वे अब 4000 से 5000 रुपये महीना कमा रहे हैं।

35 वर्षीय चंपाबेन मकवाना, जो एक गृहिणी और दो बच्चों की मां हैं, के लिए पोषण-उद्यमी बनना आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के उनके सपने को साकार कर रहा है। 5000 रुपये की उनकी मासिक आय ने उन्हें अपने पंख फैलाने और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन व्यवसाय में उतरने का आत्मविश्वास दिया है। वह न केवल परिवार की वित्तीय स्थिरता में योगदान करने में सक्षम है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने बेटे के पेट दर्द को भी रोक सकती है, क्योंकि वह पैकेज्ड स्नैक्स की जगह घर के बने विकल्पों का इस्तेमाल करती है। पोषण-उद्यमी बनने से 18 वर्षीय भावना सरगरा की जिंदगी बदल गई है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में फेल होने के बाद, सरगरा ने उम्मीद खो दी और दिशाहीन हो गई। उद्यमिता प्रशिक्षण ने नए दरवाजे खोले और अभिनव पाक तकनीकों और व्यंजनों ने उन्हें 5000 रुपये प्रति माह कमाने में सक्षम बनाया। आय में इस वृद्धि ने उन्हें अपनी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ट्यूशन कक्षाओं में दाखिला लेने की स्वतंत्रता दी है।

वह अपनी 12वीं बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। इसके अतिरिक्त, वह अपने परिवार को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है और अपने छोटे भाई-बहनों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह सर्वविदित है कि चिप्स और नूडल्स जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में वसा, नमक और चीनी के अस्वास्थ्यकर स्तर होते हैं। इसका एक कारण यह है कि इन उत्पादों में पायसीकारी, योजक, परिरक्षक और स्टेबलाइजर पाए जा सकते हैं जो आमतौर पर घरेलू रसोई में उपयोग नहीं किए जाते हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके।

अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से, परिवारों को पौष्टिक घर का बना भोजन खाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि इनके सेवन से टाइप-2 मधुमेह के साथ-साथ अन्य जीवनशैली से संबंधित बीमारियों के विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। अध्ययनों के अनुसार, अस्वास्थ्यकर खाद्य उत्पादों के आक्रामक विपणन का सबसे बड़ा प्रभाव सबसे कम आय वर्ग के 20 प्रतिशत समुदायों पर पड़ता है, जो पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5.5 प्रतिशत खर्च करते हैं। हालांकि, चेतना पहल से पता चलता है कि पैकेज्ड सभी चीजें अस्वास्थ्यकर नहीं होती हैं। यह पौष्टिक और स्वस्थ हो सकती हैं। इसके लिए बस इच्छाशक्ति और पोषण शिक्षा की आवश्यकता होती है।

आप की बात

संकट में सिद्धारमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में राज्यपाल द्वारा जांच की अनुमति देने के मामले में हाई कोर्ट ने इसे उचित बताया है। चूंकि जांच खुद मुख्यमंत्री की होनी है तो पद पर रहते हुए वे अपने प्रभुत्व से जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सत्ता मिलते ही पार्टी के उच्च पदों पर आसीन नेता अपनी अगली सात पीढ़ियों के जीवनयापन की व्यवस्था में जुट जाते हैं। सत्ता के मद में चूर होकर और सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर वे अपने पद का पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वहां नीचे के अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है। सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकायुक्त कर रहे हैं। फिलहाल तो कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया का बचाव कर रहे हैं, पर बाद में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुर्सी की लड़ाई तेज हो सकती है। विडंबना है कि विदेशी एजेंसियों की छोटी-मोटी खबरों के आधार पर मोदी को भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेटने का प्रयास करने वाले राहुल गांधी इस मामले पर एकदम चुप हैं। भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ट्रस्ट पर भी हैं।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

जलवायु परिवर्तन का कारण

जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका और एशिया के कई इलाकों में भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। मौसम एवं वातावरण में उतार-चढ़ाव के कारण इस धरती पर लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है। इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही जलवायु परिवर्तन ने धरती के कई भागों में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां सूखा, लू, हांड़ कपाने वाली ठण्ड, तूफान, बाढ़, जंगलों में आग लोगों को संकट में डालती है, वहीं समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई शहर एवं कस्बे डूब रहे हैं। इन सब के जिम्मेदार हम इंसान ही हैं। चार दशकों में वनों की कटाई के कारण अमेज़न वर्षावन ने जर्मनी और फ्रांस के संयुक्त क्षेत्र के बराबर वन क्षेत्र खो दिया है। 1985 से 2023 तक धरती का 12.5 प्रतिशत हरित आवरण मुख्य रूप से खनन और कृषि के कारण नष्ट हो गया। इंपीरियल कॉलेज लंदन की शोधकर्ता क्लेयर बार्न्स ने कहा, कभी न खत्म होने वाली गर्मी और कम बारिश ने पारिस्थितिकी तंत्रों को अत्यधिक ज्वलनशील टिंडरबॉक्स में बदल दिया है। इस प्रकार धरती का सबसे बुद्धिमान, प्राणी समझा जाने वाला मनुष्य खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और दोष बदलते मौसम पर मढ़ रहा है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

योगी का प्रशंसनीय कदम

खान-पान की वस्तुओं में मिलावट, कारीगरों द्वारा रोटी बनाने में थूक, शाकाहारी समोसों में मांस व जूस में गंदगी मिलाने जैसी घटनाएँ प्रकाश में आने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी कर कठोर कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम अत्यंत प्रशंसनीय है। इससे प्रेरणा लेकर कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी होटल व रेस्टोरेंट स्वामियों को पहचान उजागर करना अनिवार्य किया गया है । पहचान छिपाकर कुछ व्यापारी ऐसे घृणित काम करते हैं। भगवान तिरुपति के महाप्रसादम तक ऐसी गंदगी मिलाने वालों को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश का अनुसरण करते हुए देश के सभी होटलों, ढाबों व रेस्टोरेंटों पर मालिकों व उनके कर्मचारियों का नाम लिखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूध, घी, सरसों के तेल, शहद, खोया व अन्य दुग्ध पदार्थों में मिलावट करने वाले संगठित गिरोहों के खिलाफ सभी राज्यों की पुलिस को मिल कर संगठित अभियान चलाने के साथ सफल अभियोजन के माध्यम से इनको कठोरतम दंड देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुनिया में सबसे तेज प्रगति करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खाद्य पदार्थों में इस प्रकार की मिलावट कलंक है।

- सुधाकर आशावादी, मेरठ

आत्मनिर्भर भारत

भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस सफलता के पीछे सरकार की मेक इन इंडिया योजना है। मेक इन इंडिया से भारत ने आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने में बड़ी छलांग लगाई है। मोबाइल फोन निर्यात में पिछले दस साल में साढ़े सात हजार प्रतिशत की चकित करने वाली प्रगति हुई है। देश मे इस्तेमाल होने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल यहीं बने हैं। मोबाइल निर्माण में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है। भारत दुनिया का चौथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत में खिलौनों का निर्माण 239 प्रतिशत बढ़ा है। 2014 में स्टार्टअप संख्या 350 थी जो अब बढ़कर 1.40 लाख हो गई है। रक्षा क्षेत्र में भारत बड़ी तेजी से आयातक से निर्यातक देश बन रहा है। आज भारत बड़े-बड़े हथियार स्वयं बनाने में सक्षम हो गया है। मेक इन इंडिया के कारण पिछले दस वर्षों में एफडीआई में119 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पहली बार भारत का वस्तु निर्यात 400 अरब डॉलर के पार पहुँचा है। आत्मनिर्भर भारत जल्द ही विकसित भारत बनेगा।

- ललित शंकर, गाजियाबाद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

दैनिक जागरण

विचार ही व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देते हैं

मुश्किल में सिद्दरमैया

कर्नाटक सरकार ने सीबीआइ जांच के लिए दी गई सहमति एक ऐसे समय वापस ली, जब मुख्यमंत्री सिद्दरमैया इस गंभीर आरोप से घिरे हैं कि मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण के तहत उनकी पत्नी को गलत तरीके से महंगे प्लाट आवंटित किए गए। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय पहुंचे, लेकिन उसने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब प्लाट आवंटन घोटाले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग तेज हो रही थी, तभी कर्नाटक सरकार ने सीबीआइ जांच की सहमति वापस ले ली। इससे यही लग रहा है कि कर्नाटक सरकार यह नहीं चाहती कि प्लाट आवंटन मामले की जांच सीबीआइ के हाथ जाए। पहली नजर में यह 'चोर की दाढ़ी में तिनका' वाला मामला लगता है। यदि सिद्दरमैया यह दावा कर रहे हैं कि प्लाट आवंटन में उनकी पत्नी को कहीं कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया गया तो फिर वह किसी जांच से क्यों बच रहे हैं? उन्हें तो किसी भी तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार रहना और दिखना चाहिए था। हालांकि अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का विकल्प खुला है, लेकिन यदि उन्हें वहां से राहत नहीं मिलती तो उन पर त्यागपत्र देने का दबाव बढ़ जाएगा और कांग्रेस के लिए उनका बचाव करना कठिन होगा।

यदि अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पर जब भी किसी मुख्यमंत्री ने घपले-घोटाले की जांच का सामना किया है तो उसने त्यागपत्र दिया है। पता नहीं, सिद्दरमैया क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने सीबीआइ जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति वापस लेकर अपनी मुसीबत बढ़ाने का ही काम किया है। कर्नाटक से पहले विपक्ष शासित कई राज्य इस तरह की सहमति वापस ले चुके हैं। ध्यान रहे कि किसी मामले में सीबीआइ जांच के लिए संबंधित राज्य की सहमति चाहिए होती है, बशर्ते उच्चतर न्यायपालिका ने इसके आदेश न दिए हों। इसका कारण यह है कि इस एजेंसी का गठन जिस दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत किया गया है, वह यह कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों की सीबीआइ जांच के लिए उनसे सहमति लेनी होगी। ऐसी कोई बाध्यता ईडी और एनआइए के सामने नहीं है। अच्छा होगा कि इस विसंगति को दूर किया जाए और सीबीआइ को भी ईडी और एनआइए जैसे अधिकार प्रदान किए जाएं। इसी के साथ सीबीआइ की कार्यप्रणाली को भी सुधारना होगा, ताकि उसकी प्रतिष्ठा बढ़े और ऐसे आरोप न उछलें कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि राजनीतिक मामलों की जांच में सीबीआइ का रिकार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है और इसी कारण हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि उसे पिंजरे के तोते वाली अपनी छवि से मुक्ति पानी चाहिए।

मिलावट की जांच जरूरी

आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं के प्रसाद में मिलावटी घी की खबर सामने आने के बाद फिर से यह मांग उठने लगी है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। झारखंड के खुले बाजार में बिक रहे घी, दूध से बने उत्पाद और मिठाइयों में मिलावट की भरमार है। घी से लेकर पनीर और मसाले में भी मिलावट की जा रही है, लेकिन इसे देखनेवाला कोई नहीं है। मिलावटी घी में 25 प्रतिशत घी और बाकी मात्रा में पाम आयल तथा घी का सुगंध लाने के लिए एसेंस मिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य की एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला लाचार बन कर रह गई है। खाद्य जांच प्रयोगशाला में मैनपावर की कमी है। इसके अलावा विशेषज्ञों, केमिकल्स, मशीनों आदि की कमी के कारण मिलावटी खाद्य पदार्थों की सभी पारा मीटर पर जांच नहीं हो पा रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के प्रविधान के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच 14 दिनों में हो जानी चाहिए, लेकिन यहां महीनों लग जाते हैं। लैब को मिली एनएबीएल की मान्यता भी समाप्त हो गई है। जिस कारण जांच बंद है। ऐसे में झारखंड में मिलावटखोरों पर पूरी तरह नकेल नहीं लग पा रही है। झारखंड हाई कोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थ को लेकर गंभीर टिप्पणी करते हुए चिंता जताई है। अदालत ने पूछा है कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने राज्य में चार फूड लैब बनाने की बात कही है।

एफएसएसएआइ के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच 14 दिनों में हो जानी चाहिए, लेकिन झारखंड में महीनों लग जाते हैं

समस्या न बनने पाए श्रीलंका

हर्ष वी. पंत

श्रीलंका में पहली बार सत्ता में आई वामपंथी सरकार को समझना होगा कि नए वैश्विक ढांचे में पुराने सोच से काम नहीं चलेगा

आदित्य जी. शिवमूर्ति

श्रीलंका के हालिया चुनाव में जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी को जीत हासिल हुई और उसके नेता अनुरा कुमारा दिसानायके नए राष्ट्रपति चुने गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने ढांचागत बदलाव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए जनादेश दिया है। नई सरकार की विदेश नीति को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। दिसानायके के अतीत और वैचारिक झुकाव को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है। हालांकि वर्तमान आर्थिक एवं भूराजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यही संभावना अधिक है कि श्रीलंका उसी राह पर आगे बढ़ेगा, जिसमें वह भारत और चीन के साथ संतुलन साध सके। सुशासन और सुधारों को लेकर नई सरकार से जुड़ी उम्मीदें भी दीर्घकाल में भारत और उसके सहयोगियों को लाभ पहुंचाएंगी।

जेवीपी पिछली सदी के सातवें दशक में अस्तित्व में आई। अपने मार्क्सवादी चिंतन और सिंहली राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते आरंभ से ही उसका रवैया भारत विरोधी रहा। दक्षिण एशिया में भारतीय 'विस्तारवाद' से निपटना उसके वैचारिक लक्ष्यों में से एक रहा। इसने 1971 में पहली बार श्रीलंका राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे तुरंत ही दबा दिया गया। तब कोलंबो एयरपोर्ट की सुरक्षा के अलावा सरकार के अनुरोध पर भारत ने सामुद्रिक निगरानी का भी काम किया। हालांकि 1987 से 1990 के बीच दूसरे दौर के इसके विद्रोह में भारत विरोधी तेवर कहीं तीखे थे। जेवीपी ने श्रीलंका-भारत के उस समझौते का भी विरोध किया था, जिसके तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को अनुमति दी गई थी। अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने और भ्रष्ट एवं अक्षम कुलीन तबके को हटाने में भी इस संगठन ने अपने भारत विरोधी रवैये को नए तेवर दिए।

वर्ष 1994 में जेवीपी सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ी, मगर मतदाताओं की पारंपरिक पसंद नहीं बन पाई। जब 2022 के आर्थिक संकट में लोग स्थापित व्यवस्था और नेताओं से आजिज आ गए, तब दिसानायके की लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई। जेवीपी के बढ़ते ग्राफ ने भारत को भी इस पार्टी के साथ सक्रियता बढ़ाने की दिशा में उन्मुख किया। चूंकि चुनावी नतीजों को लेकर भारी अनिश्चितता जुड़ी थी तो भारत के लिए सत्ता के प्रमुख दावेदारों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी था। इसी सिलसिले में चुनावों से पहले भारत ने श्रीलंका के विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई नेताओं से बात भी की। दिसानायके भी इन नेताओं में शामिल रहे।

भारत की व्यावहारिक सक्रियता उसकी पड़ोसी-प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। चूंकि समय के साथ श्रीलंका का भूराजनीतिक महत्व और बढ़ा है तो भारत भी वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाकर लाभ उठाने के प्रयास में लगा है। जिस समय श्रीलंका आर्थिक दुश्वारी और अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने चार अरब डालर के कर्ज के साथ ही करेंसी स्वैप, अनुदान और क्रेडिट लाइन जैसे कई उपायों से उसे मदद पहुंचाई। इसके अलावा कई आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति की। इस पड़ोसी देश पर चीन की बढ़ती पकड़ को देखते हुए भारत ने अपने प्रयासों की गति और बढ़ाई। इसी का नतीजा है कि भारत श्रीलंका में एयरपोर्ट और बंदरगाहों को अपग्रेड करने के साथ ही त्रिनकोमाली क्षेत्र के विकास और अक्षय ऊर्जा, रिफाइनरी, एनर्जी ग्रिड एवं पेट्रोलियम पाइपलाइन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। तमाम भारतीय कंपनियां श्रीलंका सरकार के उपक्रमों में निवेश में दिलचस्पी दिखा रही हैं।

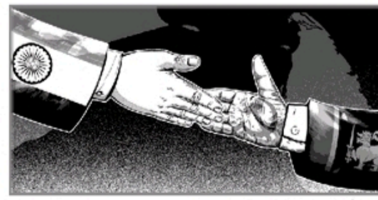

अवधेश राजपूत

जेवीपी के स्तर पर भी बदलाव की आहट दिखती है। उसे महसूस हो रहा है कि समकालीन विश्व में शीत युद्ध वाली मानसिकता से काम नहीं चल सकता। चुनावों के दौरान भी यह रवैया दिखा। उसे यह लगता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भारत का भूराजनीतिक कद और उसकी आर्थिकी बहुत मददगार हो सकती है। दिसानायके ने श्रीलंका के विकास और बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के जो चुनावी वादे किए हैं, उनकी पूर्ति भारत के साथ सहयोग से ही संभव हो सकती है। सरकार पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिये भी राजस्व बढ़ाना चाहती है। उसमें भी भारत की अहम भूमिका होगी। इसलिए भारत की चिंताओं पर गौर करना जेवीपी के लिए जरूरी होगा। उसके घोषणा पत्र में भी उल्लेख था कि किसी भी देश विशेषकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को उसकी जमीन और जल एवं वायु सीमा से इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी भारत को देखना होगा कि श्रीलंका उसके हितों के लिए समस्या न बनने पाए।

यह तय है कि नई सरकार चीन के साथ भी संतुलन साधने की दिशा में बढ़ेगी। बीजिंग भी अपनी साम्यवादी विचारधारा को देखते हुए नई सरकार के साथ सक्रियता बढ़ाएगा। दिसानायके भी चुनाव पूर्व भारत से पहले चीन का दौरा कर चुके हैं। करीब सात अरब डालर के साथ बीजिंग श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक बना हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए चीन के ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। जैसे हंबनटोटा में रिफाइनरी के लिए 4.5 अरब डालर के निवेश की पेशकश श्रीलंका के लिए जरूर लुभावनी होगी, जिससे उसे अपनी आर्थिकी को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।

हालांकि चुनाव जीतने के बाद वादों को पूरा करने की नई चुनौती उत्पन्न होती है। देखना होगा कि दिसानायके इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। दिसानायके ने कुछ कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसका संभावित निवेश पर कुछ असर पड़ सकता है। जैसे अदाणी एनर्जी की परियोजना को लाल झंडी दिखाना। हो सकता है कि वह कुछ ऐसे फैसले लें, जो चीन के गले न उतरें, जो तमाम तिकड़मों के सहारे देशों के शोषण की योजना पर काम करता है। हालांकि अगर दिसानायके नीर-क्षीर विश्लेषण के साथ इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह भारत और उसके जैसे सोच वाले साझेदारों के लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि तब चीन के लिए अनुचित लाभ की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। साथ ही श्रीलंका के तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी बढ़ेगी।

(पंत आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष और शिवमूर्ति एसोसिएट फेलो हैं)

response@jagran.com

ग्रामीण भारत की सूरत बदलती कृषि

तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की स्थिरता पर संदेह प्रकट करने वालों को निराशा हाथ लगी है। पहले सौ दिनों में ही सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार का पूरा जोर सरकारी कामकाज के तरीके में बड़े सुधार और गुड गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक ले जाने पर है। इसके लिए वह भूमि रिकार्ड से लेकर सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण पर फोकस कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। इसीलिए सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ-साथ उसकी मानिटरिंग और नौकरशाही की जवाबदेही तय करने के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं। सरकार के तीसरे कार्यकाल की जो उपलब्धियां आज दिख रही हैं, उसकी कवायद लोकसभा चुनाव घोषित होने के पहले से ही शुरू कर दी थी। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि वह अगले पांच साल का रोडमैप और सौ दिनों का एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान लागू करने के लिए सचिवों की दस समितियां बनाई गईं। सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी गई। राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई। कारोबारियों, सिविल सोसायटी और युवाओं से भी सुझाव मांगे गए। इसके लिए दो हजार से अधिक बैठकें की गईं। इन सभी के निष्कर्ष से एक्शन प्लान का रोडमैप बना।

सरकार कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग-धंधों का विकास हो। इसी को देखते हुए कृषि आधारभूत ढांचा फंड का विस्तार किया गया है। गत दिनों इसके तहत सात योजनाओं के लिए 14,200 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपये, फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपये, कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये और पशु स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये मुख्य हैं। सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की कवायद में भी जुटी है। इसके लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में देश भर में किसानों का पंजीकरण शुरू होगा। किसानों को आधार कार्ड की भांति एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसकी सहायता से न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रमों और योजनाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। कार्ड होने से सरकार को भी योजनाएं बनाने, उनके क्रियान्वयन और विस्तार में सहायता मिलेगी। सरकार ने अगले साल मार्च तक पांच करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। पहले सौ दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत 9.3 करोड़ किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी फसलों पर 100 से लेकर 550 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया, वहीं रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाया, ताकि घरेलू तिलहनों को अच्छा मूल्य मिल सके।

रमेश कुमार दुबे

सरकार कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग-धंधों का विकास हो

छोटी जोतों को लाभकारी बनाने की कोशिश। फाइल

वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने दलहनी-तिलहनी फसलों एवं मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है। इसके बावजूद दलहनी-तिलहनी और मोटे अनाजों की सरकारी खरीद में अपेक्षित सुधार नहीं आया। इसका कारण है कि देश में सरकारी खरीद, भंडारण और विपणन का ढांचा गेहूं तथा धान जैसी चुनिंदा फसलों एवं इलाकों तक ही सिमटा है। अब सरकार दलहनी-तिलहनी और मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद, भंडारण एवं विपणन का देशव्यापी नेटवर्क बना रही है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि अनाजों के केंद्रीकृत भंडारण पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों में स्थानीय उपज को भंडारित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाएगा। इस प्रकार खेती से लेकर थाली तक विविधता आएगी। सरकार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को भी अंतिम रूप दे रही है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में तीन लाख पैक्स का गठन करना है, जो अभी 65,000 हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। राज्य सरकार एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मक्का, ज्वार और बाजरा की खरीद करेगी। इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। उपज की बिक्री का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। इससे गेहूं-धान वाली सफलता मोटे अनाजों एवं दलहनी-तिलहनी फसलों में दोहराई जाएगी।

गेहूं-धान जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे बढ़कर सरकार विविध फसलों की खेती और उन पर आधारित उद्योग-धंधों के विकास पर फोकस कर रही है। इसी को देखते हुए बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है। मछुआरों के कल्याण के लिए भी सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में जहां देश में हर साल 80 लाख टन मछली का उत्पादन होता था, वहीं आज भारत हर साल 170 लाख टन मछली का उत्पादन कर रहा है। इसी तरह पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी सरकार राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण से ही लगातार घाटे का सौदा बन रही छोटी जोतों को लाभकारी बनाया जा सकेगा।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दोषारोपण

मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी, बाधा, दुख, संताप, पीड़ा, अभाव आते हैं, वे प्रायः उनके लिए किसी अन्य को दोषी ठहराते हैं। जबकि सभी दुख-सुख, शांति-अशांति, लाभ-हानि के पीछे कर्म फल का विधान है। कर्म का फल ईश्वरीय विधान के अनुसार निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पाप एवं बुरे कर्म का फल दुख है और पुण्य कर्मों का फल सुख, आनंद, शांति, खुशी, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा है।

जीवन में दुख-सुख का क्रम निरंतर चलता रहता है। जब दुख की घड़ी जीवन में आती है, तभी हमें जीवन जीने का सच्चा अनुभव एवं सीख प्राप्त होती है और अपने एवं पराए की पहचान भी हो पाती है। प्रतिकूल समय मनुष्य के सोच, समझ को बढ़ाता है। प्रायः लोग प्रतिकूल समय में भयभीत होते हैं और घबराकर अपना धैर्य खो देते हैं। यह उस मनुष्य की कायरता है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो संघर्षरत रहते हैं, वे ही शूरवीर और कालजयी कहलाते हैं। ज्ञानी मनुष्य दुख-सुख में सम स्थिति में रहते हैं। वह दुख में नहीं दुखी होता है और न वह सुख में इठलाता है। अपनी जीवन की गाड़ी को परमात्मा को सौंप देता है, चाहे परमात्मा जिस तरह से उसकी जीवन की गाड़ी को चलाए। वह सदा परमात्मा के निर्देश के अनुपालन में अपने जीवन जीने का कर्तव्य एवं दायित्व समझता है।

भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम के जीवन में भी दुख आते रहे। माता सीता को गर्भावस्था में वन में रहना पड़ा। उन्होंने इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया। अज्ञानी जन वनगमन के विषय में कैकेयी एवं मंथरा को दोषी ठहराते हैं। जबकि पद्म पुराण में वर्णित है कि मां सीता पर एक शुक पक्षी की आह का प्रकोप था। श्रीराम को विश्वमोहिनी स्वयंवर के दौरान देवर्षि नारद का शाप था। राजा दशरथ को पुत्र वियोग का शाप श्रवण कुमार के पिता से मिला था। अतः दुख, सुख अपने कर्मों के फल हैं। इनके लिए किसी को दोषी ठहराना अज्ञानता है, जो विवाद एवं द्वेष को बढ़ाता है।

मुकेश ऋषि

विकृत मानसिकता पर लगाम

डा. मोनिका शर्मा

बाल पोर्नोग्राफी न केवल बाल शोषण को बढ़ावा देने वाली सामग्री है, बल्कि यह अमानवीय सोच का सबसे कुरूप चेहरा भी है

उच्चतम न्यायालय ने बाल पोर्नोग्राफी देखने-सहेजने को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आइटी अधिनियम के तहत आपराधिक कृत्य करार दिया है। साथ ही संसद को सुझाव दिया है कि कानून में संशोधन कर 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द के स्थान पर 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' का इस्तेमाल किया जाए। उसने न्यायिक प्रक्रिया में भी इन शब्दों से परहेज करने की बात कही है। अदालत के अनुसार, 'बाल पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोर्नोग्राफी की अवधारणा दो वयस्कों के बीच स्वैच्छिक यौन क्रिया का सुझाव देती है, इसलिए बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के लिए इस शब्द का उपयोग करना अनुचित होगा।'

बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री देखने-सहेजने पर लगाम लगाने और उचित शब्दों के प्रयोग से जुड़ी दोनों ही बातें मानवीय मनः स्थिति को गहराई से प्रभावित करने वाली हैं। बच्चों के शोषण से जुड़ी विकृत मानसिकता पर लगाम लगाने का यह प्रभावी तरीका है। ऐसी सामग्री को देखने-प्रसारित करने वाले लोग आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इस सामग्री को बनाने के लिए बच्चों का शोषण किया जाता है। नतीजतन बाल पोर्नोग्राफी बाल तस्करी का एक बड़ा कारण बन गया है। बच्चों के शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और यौन दुर्व्यवहार के बाद खुलासे के भय से जान तक ले लेने के मामले समने आने लगे हैं। इसी के चलते उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' शब्द अधिक सटीक रूप से इस वास्तविकता को दर्शाता है कि ये चित्र और वीडियो केवल अश्लील नहीं हैं, बल्कि उन घटनाओं के रिकार्ड हैं, जहां किसी बच्चे का यौन शोषण और दुर्व्यवहार किया गया या जहां किसी स्व-निर्मित दृश्य चित्रण के माध्यम से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को दर्शाया गया।

चिंतनीय है कि इंटरनेट पर खुलेपन के नाम पर कुत्सित सामग्री के रूप में अनगिनत अश्लील वीडियो एवं क्लिपिंग उपलब्ध हैं। महानगरों से लेकर गांवों तक विकृत मानसिकता की जड़ बन रही अश्लील सामग्री पहुंच रही है। बाल पोर्नोग्राफी तो वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से विस्तार पाने वाला व्यवसाय बन गया है, जिससे जुड़ा हर पहलू बच्चों के शोषण की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। बाल पोर्नोग्राफी न केवल बाल शोषण की विकृति को बढ़ावा देने वाली सामग्री है, बल्कि यह अमानवीय सोच का सबसे कुरूप चेहरा भी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बरकरार रहनी चाहिए कश्मीर की शांति

'खतरा बन सकते हैं कश्मीरी अलगाववादी' शीर्षक से युक्त आलेख में विजय क्रांति द्वारा व्यक्त की गई यह आशंका महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनावों के बीच कश्मीर में उभर रहे अलगाववाद की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। वस्तुतः कश्मीर घाटी में पूरी तरह से पैर जमा चुके देशद्रोही जिहादी आतंकवाद और अलगाववाद का केंद्र सरकार ने जिस तरह से सफाया किया है, उससे भारत विरोधी पाकिस्तानी एजेंडे की हवा निकल गई है। मोदी सरकार ने यदि अपने पहले कार्यकाल में कश्मीर में फैले आतंकवादी नेटवर्क की कमर तोड़ने का काम किया तो दूसरे कार्यकाल में बड़ी कुशलता के साथ कश्मीर के अस्थायी अनुच्छेद-370 और 35-ए को संवैधानिक रूप से निर्मूल कर दिया। इससे न केवल कश्मीर की अलगाववादी राजनीति को झटका लगा, अपितु कश्मीर के शांतिप्रिय जनमानस में मोदी सरकार के प्रति विश्वास भी कायम हुआ है। आज कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हो रहे शांतिपूर्ण मतदान को लेकर कश्मीर में शांति बहाली के जो कयास लगाए जा रहे हैं, वह इसी विश्वास का प्रतिफलन है। बावजूद इसके अंदरखाने अलगाववाद की राजनीति करने वाले विधानसभा के प्रत्याशियों द्वारा जिस तरह से कश्मीर के 1951 वाले स्टेटस की बहाली को हवा दी जा रही है, वह शुभ संकेत नहीं है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आए अलगाववादी नेता शेख अब्दुल रशीद का कश्मीर के चुनावी माहौल में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के साथ अंदरखाने होने वाला गठजोड़ चिंतित करने वाला है। ऐसे में यदि भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक दल चुनाव जीत कर आने वाले निर्दलीय अलगाववादी तत्वों के सहयोग से सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो कश्मीर की शांति को पलीता लग सकता है।

डा. बीपी पांडेय, अलीगढ़ (उप्र)

मेलबाक्स

मेक इन इंडिया : मेकिंग इंडिया

मेक इन इंडिया अभियान शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में सही कहा गया है कि कुल मिलाकर मेक इन इंडिया अभियान कुछ हद तक तो सफल है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना है। हमारे देश के आकार-प्रकार के मद्देनजर मेक इन इंडिया अभियान को हर स्तर पर सफल बनाने में सभी संबद्ध पक्षों एवं स्टेकहोल्डर्स को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी आवश्यक है। विगत 10 वर्षों में जो इस दिशा में प्रगति हुई है उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं जिनके अथक प्रयासों से इस अभियान को बल मिला है। मोबाइल से मिसाइल तक देश में मेक इन इंडिया ने अपनी धाक जमाई है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार की ओर से जहां कैपेक्स में वृद्धि की जा रही है वहीं हमारे उद्योगपतियों/व्यवसायियों को देशहित में देश में विनिर्माण की वस्तुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मोबाइल और रक्षा क्षेत्र में आज निर्यात सुकून भरा है वैसी ही स्थिति अन्य वस्तुओं की होनी चाहिए। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस चाहिए तो मात्र दिशा। इसमें सरकारी प्रयासों के साथ ही साथ उद्योग-जगत को भरोसे में लेना होगा। जमीनी स्तर पर उनकी जो समस्याएं हैं, उनके समाधान खोजने होंगे। इसके साथ ही कृषि नीति में आवश्यक बदलाव कर तिलहन और दलहन की खेती पर हमें ध्यान केंद्रित कर इस दिशा में आत्मनिर्भर बनना होगा तभी हम आयात-निर्यात में सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मामले में न केवल हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपितु इनके अधिकाधिक निर्यात पर फोकस करना होगा। आज भारत की विश्व-पटल पर जो स्थिति है उसके चलते दुनिया भारत पर विश्वास करती है। इस विश्वास को भुनाने के लिए आवश्यक है कि हमारे सभी राजनीतिक दल कोई ऐसा झूठा नैरेटिव तैयार न करें जिससे हमारे देश की छवि धूमिल हो और दुनियाभर के निवेशकों का विश्वास हिले। कर्मचारी से लेकर व्यापारी तक और पक्ष-विपक्ष के हर नेता को देशहित में अपना सक्रिय योगदान देना होगा तभी हम देश की विभिन्न समस्याओं से पार पाएंगे।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

10 लाख से अधिक ऐसे युवा इंजीनियरों की आवश्यकता होगी देश में अगले तीन वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र को जो कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) समेत अन्य अत्याधुनिक तकनीकों के विशेषज्ञ होंगे, नैसकाम की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार।

आजकल

कौशल के अभाव में रोजगार की गति धीमी

एक एचआर कंसल्टिंग फर्म की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत ही आवश्यक कौशल से युक्त हो पाते हैं। इनमें से केवल 45 प्रतिशत ऐसे होते हैं जो नौकरी में आने पर उद्योग के मानकों या कसौटियों पर खरे उतर सकते हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में व्यापक योगदान देने वाले इंजीनियरों की भूमिका को देखते हुए ये आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। रोजगार की गति को बढ़ाने के लिए इस दिशा में भी गंभीरता से ध्यान देना होगा

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

प्रतीकात्मक

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हम अक्सर इसकी चर्चा करते नहीं अघाते हैं कि आइटी और इंजीनियरिंग का मामला हो, तो भारत इसका एक वैश्विक पावरहाउस है। हमारे हजारों युवाओं ने तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचकर अपनी मेधा और उपयोगिता साबित भी की है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू देश के भीतर ही नजर आ जाता है। चपरासी जैसे सरकारी पदों के आवेदकों में ऊंची और प्रोफेशनल डिग्री वालों की संख्या हमें हैरान करती है। इन्हें लेकर मीडिया में सनसनीखेज खबरें बनती हैं कि कैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की ऊंची डिग्री रखने वाले युवा चपरासी, माली और सफाईकर्मी के पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इस विरोधाभास पर दो-तीन जवाब भी अक्सर दिए जाते हैं। एक तो यह कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा हो गई है कि युवा किसी भी तरह से कोई भी नौकरी करने को तैयार हैं। दूसरा उत्तर है कि यह मोह सरकारी नौकरी का है, जिसमें काम नहीं करने पर भी अमूमन नौकरी नहीं जाने (स्थायित्व) का भरोसा रहता है। लेकिन इसकी एक तीसरी वजह भी प्रकाश में आती है, जिसे उद्योग जगत अक्सर जाहिर करता है। इंडस्ट्री के अनुरूप नौकरी योग्य कौशल (स्किल) के मामले में नामी शिक्षण संस्थानों तक से प्रोफेशनल और ऊंची डिग्री लेकर रहे युवा किसी काम के नहीं हैं। ऐसे में उन्हें नौकरी पर रखने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं।

इस समस्या से जुड़ा ताजा आंकड़ा एक एचआर कंसल्टिंग फर्म की एक रिपोर्ट से जाहिर हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान अब हर साल जो 15 लाख इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, उनमें से केवल 10 प्रतिशत को ही नौकरी मिलने की कोई उम्मीद बंधती है। हालांकि एक विश्लेषण कहता है कि शिक्षण संस्थानों से निकल रहे इंजीनियरों में से 60 प्रतिशत युवा वैसे तो जरूरी हुनर यानी कौशल (स्किल) से लैस बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से केवल 45 प्रतिशत ऐसे होते हैं जो नौकरी में आने पर इंडस्ट्री के मानकों-कसौटियों पर खरे उतर सकते हैं।

यह आकलन देश के भविष्य के मद्देनजर पैदा होने वाली चुनौतियों के संबंध में भयावह क्यों है- इसकी एक तस्वीर नैसकाम के अनुमान में दिखती है। गैर लाभकारी इंडस्ट्री संगठन- नेशनल एसोसिएशन आफ साफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नैसकाम का अंदाजा है कि अगले दो-तीन वर्षों में भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 10 लाख से ज्यादा ऐसे युवा इंजीनियरों की जरूरत है जो कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) समेत अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में महारत रखते हों। इतना ही नहीं, देश के तीव्र डिजिटलीकरण की जरूरतों के तहत मांग-आपूर्ति में फिलहाल जो अंतर 25 प्रतिशत चल रहा है, वह 2028 तक बढ़कर 30 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। ये चुनौतियां इतनी गंभीर इसलिए भी हुई हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग से जुड़े क्षेत्रों में तेजी से विविधता आई है। एआइ के अलावा सेमीकंडक्टर उत्पादन और इलेक्ट्रानिक उद्योग में पैदा हुई नई संभावनाओं जैसे ईवी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, डाटा विश्लेषण आदि ने इंजीनियरिंग डिग्री के सामने विशाल लक्ष्य स्थापित कर दिए हैं।

इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि इंजीनियरिंग में नौकरी के विकल्प एकरेखीय नहीं रह गए हैं। बल्कि इसमें लाखों नए अवसर पैदा हुए हैं। पर समस्या यह है कि ज्यादा शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पारंपरिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में सिमटी हुई है। वहां नई तकनीकों के तेजी से उभरने और संबंधित कौशल विकसित करने लायक संसाधन (इंफ्रास्ट्रक्चर) और मार्गदर्शन का अभाव है। ऐसे में जो युवा इंजीनियर डिग्री लेकर रोजगार के बाजार में आते हैं, अपने आधे-अधूरे कौशल और सीमित ज्ञान के कारण उद्योग जगत की अपेक्षाओं से तालमेल बिठाने में नाकाम हो जाते हैं। उद्योग जगत चाहता है कि ऐसे डिग्रीधारी युवा पहले दिन से सौंपे गए कामकाज को पूरी कुशलता से निपटाएं।

नहीं मिल रहे काबिल : जब मामला पढ़े-लिखों में बढ़ती बेरोजगारी का हो, तो इस बारे में अब यह जरूर कहा जा सकता है कि यह मर्ज पुराना हो चुका है। छह साल पहले 2016 में भी एचआर कंसल्टिंग फर्म टीमलीज ने विश्व की 42 हजार महत्वपूर्ण कंपनियों के बीच कराए गए अपने सर्वेक्षण के आधार पर कहा था कि विश्व स्तर पर खोजबीन करने के बाद भी इनमें से 47 प्रतिशत कंपनियों को प्रतिभावान और कौशलयुक्त युवा अपने यहां रिक्त पदों पर तैनाती के लिए नहीं मिल रहे हैं। भारत में तो 48 प्रतिशत कंपनियों ने यह शिकायत की थी कि उन्हें नौकरी की अपेक्षाओं के अनुरूप काबिल लोग नहीं मिल रहे। उस समय सबसे खराब स्थिति आइटी सेक्टर की बताई गई थी, जहां कंपनियां युवाओं में स्किल की कमी से जूझ रही थीं।

डिग्री से काबिलियत का गलत आकलन : असल में उद्योग जगत को अब यह सोच बदलने की भी जरूरत है कि किसी बड़े या विदेशी शिक्षण संस्थान से ली गई डिग्री काबिलियत की असली कसौटी है। बड़ी डिग्री और कौशल के बीच का जो द्वंद्व है, वह युवाओं द्वारा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए की जा रही कवायदों और प्राइवेट सेक्टर में योग्य लोगों की कमी संबंधी तथ्यों से साफ हो जाता है। इसकी हकीकत यह है कि जिन डिग्रियों के बल पर कई नौजवान प्राइवेट छोड़ कोई भी सरकारी नौकरी कर लेने का दम भरते नजर आते हैं, उनमें से ज्यादातर तो क्लर्क बनने लायक भी नहीं होते हैं। भारतीय उद्योगों के संगठन- एसोचैम और रोजगारों की स्थितियों का आकलन करने वाली संस्था- एस्पायरिंग माइंड अतीत में इस बारे में बता चुके हैं। एसोचैम ने वर्ष 2015 में जारी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि आइआइएम और चुनिंदा प्रबंधन संस्थानों के अलावा ज्यादातर संस्थानों से मैनेजमेंट की शिक्षा-डिग्री पाए नौजवान किसी नौकरी के काबिल नहीं हैं। उनकी ट्रेनिंग इस स्तर की नहीं है कि उन्हें डिग्री के अनुसार नौकरी दी जा सके।

एसोचैम के अनुसार, आइआइएम के अलावा अन्य संस्थानों से आए छह-सात प्रतिशत छात्र ही कायदे की नौकरी के योग्य होते थे। बाकी छात्र तो आठ या दस हजार रुपये महीना वाली नौकरी के लायक थे- भले ही उन्होंने डिग्री पर लाखों रुपये क्यों न खर्च किए हों। कुछ यही दशा इंजीनियरिंग में भी पाई गई। संस्था- एस्पायरिंग माइंड तो कई वर्षों से लगातार यह कहती रही है कि देश में संस्थानों से निकले करीब आठ प्रतिशत इंजीनियर ही ठीक-ठाक नौकरी पाने के योग्य होते हैं। समय आ गया है जब स्वयं युवाओं समेत सामाजिक संगठन और सरकार में इस बात पर विचार हो कि नौजवानों के लिए कागजी योग्यताओं का वजन बढ़ाते हुए सरकारी नौकरी पाने के अंतहीन प्रयास करना जरूरी है या फिर किसी काम के लिए स्वयं को वास्तव में योग्य साबित करना। उन्हें देखना होगा कि आज भी गांव का नौजवान कस्बाई या शहरी नौजवान के मुकाबले इसलिए ज्यादा संतुष्ट है, क्योंकि उसे स्थायी किस्म की सरकारी और ऊपर से आकर्षक दिखने वाली किसी प्राइवेट नौकरी के पीछे नहीं भागना है। इसके उलट उसे या तो स्वयं का कोई कारोबार शुरू करना होता है या फिर पारंपरिक पेशे में अपना हुनर दिखाते हुए आजीविका का प्रबंध करना होता है।

सरकार और समाज को भी अब यह देखने की जरूरत है कि अधिक पूंजी लगाकर कम रोजगार पैदा करने की नीति न तो देश और न ही युवाओं का कोई भला कर रही है। वहीं युवाओं को भी सरकारी नौकरी में स्थायित्व खोजने के बजाय अपनी योग्यता साबित करने पर जोर देना होगा जो कागजी डिग्रियों से ज्यादा इस पर निर्भर करती है कि वे असल में कितने हुनरमंद हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण में छिपी है असली कुंजी

इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आइटी, कंप्यूटर या रोबोटिक साइंस आदि क्षेत्रों से जुड़े उद्योग युवाओं में जिस हुनर की तलाश कर रहे हैं, वह अकेले पारंपरिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के बल पर उनमें पैदा कर पाना असंभव है। इस हुनर या कौशल में आए अंतर को पाटने के लिए जरूरी है कि शिक्षा को व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिसशिप के साथ जोड़ा जाए। औपचारिक शिक्षा के साथ अप्रेंटिसशिप का तालमेल करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि युवा किसी भी क्षेत्र में पहले दिन से पूरे कौशल के साथ काम करने के लिए तैयार हों। वास्तविक दुनिया यानी उद्योग जगत के असली अनुभव और वहां मिलने वाले मार्गदर्शन से प्रशिक्षु उद्योग की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप जरूरी कौशल विकसित कर सकते हैं। ऐसा करना पेशेवरों और कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद है। यहां हमें यह भी देखना होगा कि हमारे देश में अप्रेंटिसशिप को एक लंबे अरसे तक कोई महत्ता नहीं दी गई थी, जिसकी कीमत हमारा शिक्षा जगत और युवा चुका रहे हैं। असल में, देश में वर्ष 2000 के आसपास तक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया गया। जब देश में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, तब साक्षरता दर 51 प्रतिशत थी। इसका अर्थ यह हुआ कि देश की आधी आबादी अनपढ़ थी। यह तबका खेती-किसानी पर आश्रित था। लेकिन जब इसी दशक में स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया और कंप्यूटर तकनीक के आगमन के साथ व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की जरूरत महसूस होने लगी, तब से यह तस्वीर बदलने लगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) ऐसी पहली योजना थी, जिसमें कौशल विकास का एक अलग अध्याय था। इस तरह कह सकते हैं कि योजनागत स्तर पर कायम उपेक्षाओं ने ही आज हमारे युवाओं में हुनर का अभाव पैदा किया है। लेकिन समय आ गया है कि इस स्थिति में तेजी से सुधार किया जाए।

(डा. संजय वर्मा)

खरी-खरी

बेवजह बदनाम लड्डू

प्रभुनाथ शुक्ल

हमारी अच्छी भली जिंदगी में कई बार 'आ बैल मुझे मार' की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा भी होता है कि न चाहते हुए भी कई बार हम चर्चा-ए-आम हो जाते हैं यानी बद से अच्छे बदनाम की दशा को प्राप्त हो जाते हैं। जी हां, हम बेचारे लड्डू की ही बात कर रहे हैं। वह बेवजह बदनाम हो गया। टीवी की बहस में सरेआम हो गया।

शादी का लड्डू तो आपने खाया होगा। कहा जाता है कि शादी का लड्डू जिसने खाया वह पछताया और जिसने उसका स्वाद नहीं चखा, वह भी पछताया। ठीक वही हालत हमारे लड्डू की हो गई है। अब जिसने प्रसाद के रूप में उसे खाया है, वह पछता रहा है।

आप कुछ भी करें, लेकिन लड्डू को बेवजह बदनाम मत करिए, वरना कितने बेचारे कुंवारे रह जाएंगे। वे वर्षों से शादी का लड्डू खाने का सपना संजोए हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। शादी को लेकर उनके मन में अभी तक जो लड्डू फुट रहे हैं, उसे फूटने दीजिए। उनके सपनों पर पानी फेरने का काम मत कीजिए। वैसे भी अब भगवान को भी शुद्ध प्रसाद की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मिलावट के इस दौर में शुद्धता की गारंटी कहां है। जब मनुष्य के रक्त में मिलावट, मुनाफाखोरी, नफरत, जातिवाद, अलगाववाद आदि समाया है, फिर उसका सोच कैसे शुद्ध होगा।

हालांकि लड्डू की पीड़ा हमारे देवों के अलावा उनके भक्तों को भी बहुत है, तभी तो एक सियासी भक्त 11 दिनों के उपवास पर चले गए हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हम तो अब असली चीजों का स्वाद ही भूल गए हैं। घी, तेल, दूध, मिठाई और मसाला सब कुछ नकली आ गए हैं।

फिलहाल धरतीलोक के लिए एक बुरी खबर है। हाल के लड्डू विवाद और उस पर छिड़ी राजनीति पर देवलोक खासा नाराज है। धरती का टेंडर निरस्त कर सीधे देवलोक से प्रसाद भेजने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का भक्तों ने दिल से स्वागत किया है। वैसे राजनीतिक दलों ने इस पर चिंता जताते हुए इसे भक्तों के लोकतांत्रिक अधिकारों और आस्था के विरुद्ध बताया है। इसे देवलोक की तानाशाही बताया गया है, परंतु इस निर्णय से भगवान और भक्त दोनों खुश हैं।

पोस्ट

पूर्वोत्तर स्थित असम में इतनी गर्मी हो रही है कि स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। पश्चिम में मुंबई भारी बारिश हो रही है। मौसम के मिजाज में इतना अंतर देखा था पहले?

हृदयेश जोशी@hridayeshjoshi

हिमाचल सरकार ने यूपी सरकार की तर्ज पर खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। क्या राहुल गांधी और खरगे समेत कांग्रेस के शीर्ष नेता जिस तरह योगी को कोस रहे थे, उसी तरह अपने सीएम को भी कोसेंगे? लगता तो यही है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार भाजपा की नीतियों पर चल रही है।

प्रकाश नारायण सिंह@prakashnarayal8

हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों खासतौर से मौजूदा विधायकों का ग्रामीण इलाकों में कुछ विरोध हो रहा है। उनसे जवाब-तलब करने तक तो ठीक है, लेकिन उनका रास्ता रोकना और गांव में न घुसने देने का उलटा असर भी हो सकता है।

सत्या चौधरी@satyagodara

'लापता लेडीज' अच्छी फिल्म हो सकती है, पर क्या वह भारत से जाने वाली बेस्ट फिल्म है? खासकर जब चुनी गई 29 फिल्मों में महाराजा, आट्टम, थंगालान, श्रीकांत जैसी फिल्में भी थीं।

मीनाक्षी कंडवाल@MinakshiKandwal

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या मेक इन इंडिया योजना अपने लक्ष्य पूरे करते दिख रही है?

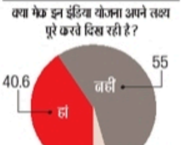

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या खान-पान की दुकानों पर उनके मालिक का नाम लिखे जाने से खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट रुकेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

डेमोक्रेसी की हवा विश्व रहा है सूंघ,
नेता अपने देश के कितु रहे हैं ऊंघ।
कितु रहे हैं ऊंच झूठ की फांक पंजीरी,
देखो कैसे वोट डालते हैं कश्मीरी!
भले होय मतदान कहीं कुछ कम या वेसी,
रहनी जिंदाबाद चाहिए डेमोक्रेसी!!

\- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

चुनावी तीर और लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

चुनावी लहर पर सवार झारखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच वाक् युद्ध चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राज्यव्यापी परिवर्तन रैली के माध्यम से लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक अलग-अलग रैलियों के माध्यम से भ्रष्टाचार, घुसपैठ, लैंड जिहाद और नौकरी तथा भत्ते के नाम पर सरकार की वादाखिलाफी का मुद्दा उठा रहे हैं। उधर, सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्यमंत्री भाजपा के बाहरी नेताओं को गिद्ध की संज्ञा देते हुए कभी उन्हें घर में नहीं घुसने देने तो कभी गुजरात के समंदर में फेंक देने की बात कर रहे हैं और झारखंडी स्वाभिमान का सवाल उठाकर लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद कर रहे हैं।

हेमंत सरकार की ओर से महिलाओं के लिए हाल ही में शुरू की मंईयां सम्मान योजना के भी जोर-शोर से चर्चे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपये डाले जा रहे हैं। भाजपा ऐन चुनाव के वक्त यह योजना लाने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं, झामुमो और कांग्रेस इस योजना का चुनावी लाभ लेने के लिए इसे जोर-शोर से प्रचारित कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में पूरे राज्य में मंईयां सम्मान यात्रा निकाल रही हैं। उनके साथ राज्य सरकार की दो महिला मंत्री और झामुमो, कांग्रेस तथा राजद के तमाम नेता भी घूम-घूम कर माहौल बना रहे हैं।

हेमंत सोरेन। फाइल

हिमंत विस्वा सरमा। फाइल

फिलहाल प्रदेश में पक्ष-विपक्ष की राजनीति परिवर्तन यात्रा और मंईयां सम्मान यात्रा के इर्द-गिर्द घूम रही है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन पूरे राज्य में आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस बहाने वह विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं के बीच हेमंत सरकार की मंईयां सम्मान योजना की लोकप्रियता ने भाजपा की चिंता बढ़ाई है। यही वजह है कि भाजपा ने इसके मुकाबले गोगो दीदी योजना लांच करने की घोषणा कर दी है, जिसमें लड़कियों को जन्म के साथ ही हर महीने 2100 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है। वस्तुतः गोगो संताली शब्द है, जिसका अर्थ है मां। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि अक्टूबर में जारी होने वाले भाजपा के चुनावी घोषणापत्र (संकल्प पत्र) में ऐसी कम से कम सात योजनाओं की भाजपा घोषणा करेगी।

हेमंत सरकार की मंईयां योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों और महिलाओं को मिल रहा है, वहीं भाजपा इससे एक कदम आगे बढ़कर गोगो दीदी योजना में मां और बेटी दोनों को योजना का लाभ देगी। नवजात बच्चों तक को इस योजना के दायरे में लाया गया है। इसी कड़ी में झारखंड के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही 2.87 लाख रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया जाएगा। इस बीच झामुमो से भाजपा में गए पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मंईयां योजना के श्रेय लेने पर हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है। एक सभा में चम्पाई ने कहा है कि आज जिस योजना के नाम पर हेमंत सरकार छाती ठोक रही है, मुख्यमंत्री रहने के दौरान उसकी रूपरेखा मैंने ही तय की थी।

खैर, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि मतदाताओं को मंईयां योजना पसंद है या गोगो दीदी योजना। वैसे भी, रेवड़ी श्रेणी की ये योजनाएं अंततः राज्य के खजाने पर ही असर डालेंगी। हमारे पास प्रचुर खनिज संपदा है। प्रकृति की इस राज्य पर बहुत बड़ी कृपा है। हमारे पास रोजगार से संबंधित योजनाओं की भरमार होनी चाहिए, ऐसी योजना जिससे लोगों को काम मिले और वे आत्मसम्मान के साथ पैसा और रोटी कमा पाएं।

मंथन

भारत हित में क्वाड की सक्रियता

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों से नई चुनौतियां उभर रही हैं, जिनसे निपटने के लिए क्वाड को गंभीर कदम उठाने होंगे और भारत को अपने हितों के अनुरूप सक्रियता बढ़ानी होगी

डा. नवीन कुमार मिश्र
भू-राजनीतिक मामलों के जानकार

इसी सप्ताह अमेरिका में संपन्न क्वाड की बैठक में अन्य वैश्विक नेताओं के साथ नरेन्द्र मोदी। फाइल

विश्व में ध्रुवीकरण की गति बढ़ी है, जो आर्थिक, वैचारिक और भू-राजनीतिक रूप में दिखाई देती है। अमेरिका के वर्चस्व वाले विश्व में चीन उसके समक्ष चुनौतियों को प्रस्तुत कर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नया आकार देने का इरादा रखता है। इसके लिए अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन कर्ज-जाल से लेकर सैन्य धमकी का प्रयोग कर दूसरे देशों की संप्रभुता को चोट पहुंचाता है। चीन की आक्रामक आर्थिक और व्यापार नीतियों तथा पूर्वी और दक्षिणी चीन सागरों एवं अन्य कई जगहों पर इसकी विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड वर्ष 2017 से अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। इसी के निमित्त 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्वाड की शीर्ष स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया है कि जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और भारत का चतुर्भुज गठबंधन (क्वाड) किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियम-आधारित व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के लिए है। क्वाड की बैठक के अलावा वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और नरेन्द्र मोदी की मुलाकात हुई, जहां भारत और अमेरिका के बीच इंडो-पैसिफिक इकोनमिक फ्रेमवर्क और ड्रग फ्रेमवर्क जैसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए।

चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा : पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन, दक्षिण एशिया और ताइवान जलडमरूमध्य में चीन आक्रामक स्थिति में है। दक्षिण चीन सागर में 'बलपूर्वक और डराने वाले युद्धाभ्यास' तथा चीन की बढ़ती आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण संपूर्ण विश्व चिंतित है। चीन के समुद्री विस्तार को नियंत्रित करने के लिए क्वाड सदस्य के चारों देश वर्ष 2025 में एक संयुक्त तटरक्षक मिशन पर सहमत हुए हैं और प्रशांत द्वीप देशों व दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ समुद्री सुरक्षा संबंधों को विकसित करने, डेटा और सूचना साझा करने पर सहमत हुए। इसके अतिरिक्त आसियान और कई यूरोपीय देशों ने हिंद-प्रशांत के लिए अपनी रणनीतियां और दृष्टिकोण विकसित किए हैं, जिससे क्वाड की प्रासंगिकता और भी स्पष्ट हो जाती है। भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिम के पास भारत का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा, वैश्विक राजनीति में रूस को पूरी तरह से चीन के पक्ष में जाने से रोकने के लिए भी भारत ही एकमात्र विकल्प है। क्वाड की बैठक में जो बाइडन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'अमेरिका के पास हिंद महासागर में भारत के अनुभव और नेतृत्व से सीखने के किए बहुत कुछ है।' चीन के साथ भूमि सीमा क्वाड सदस्यों में केवल भारत ही साझा करता है, जिसने लंबे समय से चीन की आक्रामकता का सामना किया है।

भारत के दृष्टिकोण की स्वीकार्यता : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर से लेकर अफ्रीका के तटों तक के बारे में भारत के दृष्टिकोण की स्वीकार्यता बढ़ रही है। अमेरिका अपने सेंट्रल कमांड के माध्यम से हिंद महासागर और अफ्रीका में क्वाड भागीदारों के साथ काम करने पर सहमत हुआ है। अपने भौगोलिक संदर्भ में क्वाड अपनी ऊर्जा और ध्यान को हिंद-प्रशांत के तीन उप-क्षेत्रों पर केंद्रित कर रहा है। इनमें दक्षिण प्रशांत, आसियान क्षेत्र और हिंद महासागरीय क्षेत्र शामिल हैं। यह समूह संबंधित संस्थानों में प्रशांत द्वीप समूह फोरम, दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर काम शुरू कर सकता है, जो उनके संबंधित उप-क्षेत्रों में उनके केंद्रीय महत्व को पहचानता है।

वैश्विक संघर्ष : विश्व वर्तमान में संघर्षों में उलझा हुआ है। एक तरफ अमेरिका, रूस और चीन के बीच चल रहे वैश्विक संघर्ष में भारत को रूस के साथ संबंधों को बनाए रखने और अमेरिका व उसके साझेदारों के साथ साझेदारी को गहरा करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने स्वयं को आर्थिक, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का प्रयास करके अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश की है तथा क्वाड में आंतरिक समन्वय को भी सफल बनाया है।

क्वाड पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से एकजुट व प्रासंगिक हो गया है। क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक विकल्प प्रदान करती है, तो उन्हें चीन पर पूरी तरह से निर्भरता को कम करती है। क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए युद्धपोत नहीं भेज रहा है, लेकिन अब इस क्षेत्र के भविष्य के निर्माण के लिए तैयार है। यह बेहतर और सतत विकास के लिए आसियान, प्रशांत द्वीप समूह फोरम और आइओआरए को भी संलग्न करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन व जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का कार्यकाल समाप्त होने तथा अगला क्वाड शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 में भारत में होने के कारण भारत की केंद्रीय स्थिति होने वाली है। ऐसे में क्वाड की बढ़ती सक्रियता चीन के विस्तारवादी मंसूबों को नियंत्रित करने में सक्षम साबित हो सकती है।

हिन्दुस्तान 1936

त्योहार पर लापरवाही

किसी पर्व के अवसर पर कोई अकाल मौत दुखी ही नहीं करती, बल्कि विचलित कर देती है। बिहार में जीवित्पुत्रिका या जितिया या जीउतिया का व्रत-पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और माताएं अपने बच्चों को लेकर नदियों-सरोवरों के तट पर जाती हैं, जहां स्नान, ध्यान, दान की परंपरा श्रद्धापूर्वक निभाई जाती है, पर ऐसे पावन अवसर पर बिहार भर में डूबने की अलग-अलग घटनाओं में करीब पचास मौतों ने झकझोर कर रख दिया है। जान गंवाने वालों में 36 से ज्यादा बच्चे हैं, सात महिलाएं हैं और बाकी पुरुष। यह पहली बार है कि जीवित्पुत्रिका के अवसर पर ऐसी त्रासदी हुई है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, सीवान, रोहतास, सारण, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज और अरवल जिलों से डूबने की घटनाएं सामने आई हैं। एक जैसी स्थितियों के चलते इतनी मौतें हुई हैं और मौत के कारणों के विस्तार में जाना चाहिए और तभी हम जान सकेंगे कि ऐसा क्या गलत हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है। यह अच्छी बात है कि राज्य सरकार तत्काल चार-चार लाख रुपये की मुआवजा राशि देने में जुट गई है, मगर इस बात का मौका मुआयना जरूर करना चाहिए कि घाटों पर क्या इंतजाम थे? क्या सुरक्षा के जरूरी इंतजामों की अनदेखी हुई है?

निस्संदेह, बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) का काम बढ़ गया है। केवल मुआवजा बांट देने से काम पूरा नहीं हो जाएगा। यह अच्छी बात है कि डीएमडी ने खोज और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की कई टीमों को लगाया है। बचाव कार्य की सराहना होनी चाहिए, मगर जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, उन पर शिकंजा भी कसना चाहिए। पूरब के व्रत-पर्व में अनेक मौके आते हैं, जब नदियों के पास जाने की अनिवार्यता होती है। आजकल नदियों में पानी बढ़ा हुआ है और तटों की सीमारेखा ही नहीं, रूपरेखा भी बिगड़ी हुई है। ऐसे में, उफनती नदियों के पास क्या लोगों को बड़ी संख्या में जाने देना चाहिए था? जहां यदा-कदा सेतु बनते ही टूट जाते हों, वहां तटों-घाटों की गुणवत्ता की चर्चा भला कैसे की जाए? यह प्रश्न सहज ही उभरता है, जब तट-घाट सुरक्षित नहीं थे, तब बच्चों को उनके निकट क्यों जाने दिया गया और क्यों नहाने के लिए असुरक्षित छोड़ दिया गया?

ध्यान रहे, दोष सिर्फ जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों का नहीं है। घाट के पास गए आम लोगों को भी जरूर सोचना चाहिए कि जान बड़ी है या कर्मकांड?

पर ध्यान रहे, दोष केवल सरकारी अधिकारियों का नहीं है। घाट के पास गए लोगों को भी सोचना चाहिए कि जान बड़ी है या कर्मकांड? व्रत-पर्व का अर्थ कतई यह नहीं कि जान को खतरे में डाल दिया जाए। काश! लोग ही अपने स्तर पर तटों-घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाते। छठ के समय लोग आगे बढ़कर स्वयं घाटों को सुरक्षित बनाते हैं, पर जितिया के अवसर पर भयंकर लापरवाही हो गई। व्रत के नाम पर जान से खेलने का दाग लग चुका है। अच्छे से पता है कि जितिया का व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए ही करती हैं, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, उन्हें लंबा जीवन मिले, पर यह चिंता जितिया के अवसर पर कहां चली गई? यह सवाल अब लंबे समय तक पीछा करेगा और करना भी चाहिए। यह त्रासदी इशारा है कि विशेष रूप से माता-पिता की सोच में सुधार-बदलाव जरूरी है। पारिवारिक और सामाजिक अनुशासन जरूरी है, ताकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी की नौबत न आने पाए। जीवन सिर्फ साहस-दुस्साहस नहीं है, सावधानी भी है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 27 सितंबर, 1949

अणु-शक्ति का प्रयोग

द्वितीय महायुद्ध की सबसे भयंकर घटना जापानी नगरों नागासाकी तथा हिरोशिमा का अणु-बम से विनाश है। मित्रपक्ष ने यह करके जापान को परास्त कर दिया यह सच है, और यह भी असंदिग्ध है कि मित्रपक्ष ने यह संहार-कार्य किया, इसीलिए उसे 'सभ्य' संसार ने चुपचाप हजम कर लिया; परन्तु इसीलिए ऐसे कृत्य को अच्छा नहीं कहा जा सकता। युद्ध के भी आखिर कुछ नियम होते हैं जिनके विरुद्ध आचरण को 'अधर्म' कहा जाता है। आजकल धर्म की भाषा में न सोचा जावे तो भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के रूप में ऐसे नियम बने हुए हैं जिनका उल्लंघन युद्ध में वर्जित है। अतः जो हो गया सो तो हो गया, आगे के लिए यह निश्चय करना ही है कि अणु-शकित का उपयोग युद्ध में संहार-कार्य के लिए किया जावे या नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रश्न काफी समय से उपस्थित भी है। जहां तक युद्ध में अणु-शक्ति के प्रयोग का सम्बन्ध है, कोई इस मत का नहीं मालूम पड़ता कि युद्ध में अणु-शक्ति काम में लाई जाये; परन्तु उसके प्रयोग को किस प्रकार रोका या नियंत्रित किया जाये, यह मतभेद का विषय बन रहा है।

विश्व इस समय प्रधानतः दो शक्तियों में विभक्त हो रहा है। एक ओर अमरीका का प्राधान्य है और दूसरी ओर सोवियत रूस का। संयोगवश अणु-शक्ति का अणु-बम के रूप में प्रयोग अमरीकी कुशलता से सम्भव हुआ है, अतः अमरीका का यह चाहना स्वाभाविक है कि जिस शक्ति से वह सबका संहार करके अपना प्राधान्य रख सकता है, उसका रहस्य और कोई न जानने पाये। ब्रिटेन और कनाडा उसके प्रयोग में किसी रूप में भागीदार रहे हैं, इसलिए उन तक उसने उसका कुछ रहस्य सीमित रखा है, किन्तु निर्माण का कार्य उन्हें भी नहीं करने दिया गया है, तब उससे भिन्न विचारधारा और लगभग समान शक्ति वाले सोवियत रूस को वह कोई भेद जानने देना चाहेगा, यह कल्पना ही व्यर्थ है। अमरीका का इस भेद को अपने तक सीमित रखने का आग्रह स्वभावतः रूस को संशयात्मक बनाता है और हम देख रहे हैं कि युद्ध काल के दोनों मित्र एक-दूसरे के विरुद्ध जाकर तृतीय महायुद्ध का भय उत्पन्न कर रहे हैं। तृतीय युद्ध यदि हुआ तो इन दो महाशक्तियों के बीच ही अन्ततोगत्वा वह होगा, ऐसी आज सामान्य धारणा है।

औरतों को रुलाती चंद आवाजें

अदालतों से आती कुछ टिप्पणियां महिला-विरोधी सोच की ओर इशारा हैं। हमारे न्यायालयों को 'स्कूल ऑफ डिसेंसी' कहा जाता है, पर उनका पूरी तरह शालीन होना बाकी है।

कमलेश जैन | अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही कहा है कि अदालतों को स्त्रियों पर टिप्पणी करते वक्त नारी-द्वेष से भरी व प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसी टिप्पणी का असर नकारात्मक होता है, जिससे न सिर्फ न्यायाधीश की छवि खराब होती है, बल्कि पूरी न्याय-व्यवस्था कठघरे में खड़ी हो जाती है। शीर्ष अदालत ने यह बात पटना उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के संदर्भ में कही, जिसमें कहा गया था कि मेकअप की सामग्रियां किसी विधवा के काम नहीं आतीं। निस्संदेह, यह अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी है। यह नारी-भावना और शालीनता के खिलाफ भी है। देखा जाए, तो यह पूरा मामला न्यायाधीश की परिभाषा को नए सिरे से व्याख्यायित करता है। दरअसल, हाईकोर्ट यह सुनवाई कर रहा था कि पीड़ित महिला जहां से गायब की गई और बाद में मार डाली गई, क्या वह उसी कमरे में रहती थी, जहां से उसे अगवा किया गया था। उस कमरे में शृंगार की सामग्रियां भी मिली थीं और जिरह के दौरान यह भी साक्ष्य में आया कि उस कमरे में एक विधवा भी रहती थी। उच्च न्यायालय की टिप्पणी इसी संदर्भ में थी।

इस मामले से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वह महिला वकील के खिलाफ असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। वीडियो में महिला वकील से कहा गया कि वह दूसरे पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, इतना कि अगली बार वह उसके अंडरगारमेंट्स का कलर भी बता सकती हैं। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। ऐसी टिप्पणियां न सिर्फ कानूनन गलत हैं, बल्कि आपत्तिजनक भी हैं। ऐसे मामले कहीं न कहीं महिला-विरोधी सोच को दर्शाते हैं और संकेत देते हैं कि 'स्कूल ऑफ डिसेंसी' कहे जाने वाले हमारे न्यायालयों का भी अभी शालीन होना बाकी है।

सच यही है कि स्त्रियों के बारे में इस तरह की तुच्छ सोच वर्षों से चली आ रही है। कुछ न्यायाधीश भी इसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आते हैं। मुझे पांच दशक पहले की वह घटना याद आ रही है, जब मैंने वकालत की शुरुआत की थी। उस समय पटना उच्च न्यायालय में महिलाओं से जुड़े मामले में बहस करना काफी मुश्किल होता था। जब ऐसे मामले शुरू होते, तो एक व्यंग्यात्मक, अनपेक्षित मुस्कान सबके चेहरे पर तैर जाती थी। यह जानते हुए भी कि दुष्कर्म-पीड़िता के लिए अपने साथ हुई बर्बरता का वर्णन करना कितना मुश्किल होगा, उसको बार-बार ब्योरा देने को कहा जाता, मानो अदालत कक्ष में मौजूद लोग उसका रस ले रहे हों। यह स्थिति तब होती थी, जब याचिका में एफआईआर की कॉपी लगी होती है और यह भी लिखा होता है कि किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ऐसी ही एक बहस में जब मैं अपील के लिए खड़ी हुई, तो मैंने 'बलात्कार' या 'दुष्कर्म' शब्द का जिक्र तक नहीं किया। चूंकि वह केस सेक्शन 375 का था, इसलिए न्यायाधीश से मुखातिब होकर मैंने कहा, आरोप अमुक पेज व अमुक पैराग्राफ में है और ब्योरा अमुक पेज व अमुक पैराग्राफ में, कृपया इसे पढ़ लिया जाए। कहने का मतलब यह है कि बिना शालीनता भंग किए भी अपनी बात रखी जा सकती है, बस इसके लिए आपको कुछ संजीदा होना है। दुर्भाग्य है, अदालतों में कई बार इसका अभाव दिखता है।

दिक्कत यह है कि महिलाओं से जुड़े मामलों को कैसे संबोधित किया जाए, इसकी चर्चा कानून में कहीं नहीं है। यह स्व-विवेक का मसला है और अपेक्षा की जाती है कि हर गवाह, वकील और खासकर न्यायाधीश शालीनता का परिचय देंगे। वैसे देखा जाए, तो इसकी उम्मीद अदालतों से ही नहीं, घर और समाज, सभी से होनी चाहिए। हमारे देश में सदियों से महिलाएं दोयम दर्जे की इंसान समझी जाती रही हैं, इसलिए अदालतों में भी हमें इसकी झलक मिल जाती है, जबकि जिन घरों में बेटियों को बेटों की तरह पाला जाता है, वहां बेटियां हर क्षेत्र में या तो बेटों के बराबर हैं या उनसे अधिक ऊंचाई पाती हैं।

अदालत में फैसला सुनाते वक्त हृदय और आत्मा, दोनों के निष्पक्ष होने की उम्मीद की जाती है। इसी से न्यायाधीश की महत्ता भी स्थापित होती है। कानून की बुनियादी पढ़ाई करते वक्त ही यह बात विद्यार्थियों के मन में बैठाने की कोशिश होती है। बावजूद इसके, यदि अदालत कक्ष में जेंडर से जुड़ी प्रतिकूल टिप्पणियां आ रही हैं, तो यह बहुत हद तक उस व्यक्ति की सोच से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, वह वैसा ही न्यायाधीश होता है। मन में स्त्रियों के प्रति संदेह रखने वाले जज से भला कैसे अपेक्षा करेंगे कि वह महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता दिखाएंगे?

इंग्लैंड, अमेरिका में हम इस तरह के मामले नहीं देखते, क्योंकि वहां का समाज महिलाओं के प्रति दुराग्रह नहीं रखता। मगर हमारे समाज में महिलाओं के प्रति ऐसा संकीर्ण नजरिया है कि हम गाली भी लैंगिक शब्दों से देते हैं। मुझे याद है कि निर्भया मामले की जब सुनवाई हो रही थी, तब इस मुकदमे से जुड़े एक वकील ने आपसी बातचीत में कहा था कि मिठाई का डिब्बा खुला रहेगा, तो लोग खाएंगे ही। असल में, वह इस बात से खफा थे कि निर्भया अपने मित्र के साथ इतनी देर शाम को बाहर गई ही क्यों थी? अगर वह बाहर नहीं जाती, तो उसके साथ ऐसी दुर्घटना ही नहीं होती। जब एक वकील की ऐसी टिप्पणी हो, तो अदालत कक्ष में स्त्रियों के प्रति उसका रवैया कैसा होता होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है?

साफ है, न्यायपालिका से जुड़े तमाम लोगों को यह प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि औरतों से जुड़े मामले में कैसी संवेदनशीलता उन्हें दिखानी चाहिए। वकीलों के लिए यह दिशा-निर्देश तो है कि उनको किस तरह के कपड़े पहनकर अदालत में आना चाहिए, किस तरह के आचरण का परिचय देना चाहिए या फिर बहस किस शालीनता से करनी चाहिए, लेकिन औरतों के प्रति व्यवहार को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण हम लैंगिक टिप्पणियां सुनते आ रहे हैं। इसे बंद करने का वक्त आ गया है। जिस तरह अदालतों में अश्लील सवाल-जवाब को अब खत्म कर दिया गया है, महिला-विरोधी टिप्पणियां भी इतिहास बन जाएंगी, यदि हम महिला-विरोधी टिप्पणी करने वालों को कानूनी कठघरे में खड़ा करने लगें। इन लोगों के दंडित होते ही महिला-विरोधी टिप्पणियां भी स्वतः बंद हो जाएंगी।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

यहां-वहां ठहरी-बची गरीबी का जाल टूटना चाहिए

अनुराग बेहार | सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

हमने हवाई अड्डे से चार लेन वाला राजमार्ग पकड़ा और तीन घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। जाहिर है, सड़क बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम दो लेन वाली सड़क पर आए और 80 किलोमीटर की दूरी तीन घंटे में तय की। इस बार सड़क इतनी खराब थी कि आगे की यात्रा के लिए वाहन बदलने की नौबत आ गई। अगले 10 किलोमीटर की यात्रा हमें ऊंचे चेचिस वाले वाहन से करनी पड़ी, क्योंकि सड़क पथरीली थी और पतली भी। उस कठिन डगर के बाद हमें आगे दो किलोमीटर की यात्रा के लिए बाइक पर सवार होना पड़ा और एक जगह पहुंचकर बाइक का आगे बढ़ना भी असंभव हो गया। तब हम यात्रा पूरी करने के लिए 15 मिनट पैदल चले।

हमने वह दोपहर गांव में बिताई, वहां के निवासियों से सुना कि वे अपने छोटे-छोटे खेतों की पैदावार बढ़ाने, अपने पहाड़ी क्षेत्र में बेहतर जल प्रबंधन करने और आम के बगीचे लगाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन परिवारों में से कुछ की वार्षिक आय अधिकतम 40,000 रुपये से लेकर कई लोगों के लिए शून्य तक थी। गांव के उस टोले में कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। हल्का सिग्नल पाने के लिए कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डिजिटल सत्यापन या लेन-देन की जरूरत होती है, पर यह या तो उपलब्ध नहीं है या फिर उन तक पहुंचना कठिन है।

भारत में ऐसी हजारों बस्तियां हैं और ऐसे लाखों लोग इनमें रहते हैं, जो लगभग हर उस चीज से दूर हैं, जिन्हें विकास का प्रतीक माना जाता है।

गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय ने आस-पास की बस्तियों को भी सेवा प्रदान कर रखी है। इसमें एक शिक्षक और 40 बच्चे हैं। शिक्षक ने 300 रुपये प्रति माह पर कमरा किराये पर ले रखा है और वहीं रहते हैं। पहले शिक्षक यहां आते ही स्थानांतरण की कोशिश में लग जाते थे, पर यह शिक्षक दो साल से टिके हैं। निकटतम निजी स्कूल इस गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर में है। निकटतम निजी अस्पताल 60 किलोमीटर दूर एक अन्य शहर में है। देश की सबसे बुनियादी सुविधा मतलब सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। एक नर्स के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का निकटतम पीएचसी सेंटर लगभग छह किलोमीटर दूर है। अगर गांव में किसी का पैर टूट जाए, तो उसे स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यदि किसी बीमारी के लिए सप्ताह में दो बार जांच की जरूरत पड़ जाए, तो मुमकिन ही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हो या निजी अस्पताल, दोनों में महज 40 प्रतिशत तक ही स्टाफ हैं।

यह मानव बस्ती अकेली नहीं है। भारत में ऐसी हजारों बस्तियां हैं और ऐसे लाखों लोग इनमें रहते हैं, जो लगभग हर उस चीज से दूर हैं, जिन्हें विकास का प्रतीक माना जाता है। ऐसे वंचित गांवों से लोगों का बाहर जाना और बाहर से लोगों का यहां आना बहुत संघर्षपूर्ण है। सभी प्रकार की गरीबी में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। जैसे गरीबी में हम न्यायसंगत, निष्पक्ष और सुरक्षित नौकरियां और आजीविकाएं पैदा करने में असमर्थ रहते हैं। दूरदराज की ऐसी गरीबी को दूरियां घटाकर ही मिटाया जा सकता है।

दूसरे प्रकार की गरीबी आमतौर पर किसी हवाई अड्डे से एक या दो घंटे की दूरी के अंदर ही होती है। यहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और प्रति व्यक्ति बहुत कम भूमि व अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। यहां की हर चीज पर सामाजिक रीति-रिवाजों और संरचनाओं की बुरी पकड़ होती है और यह इस गरीबी की सबसे बड़ी विशेषता है। सामाजिक और सार्वजनिक संस्थान भी गरीबी के इस जाल में मजबूती से फंसे हुए हैं और काफी हद तक निष्क्रिय हैं। यदि आप एक महिला हैं, तो बाजार आपकी पहुंच से बाहर होंगे, मोबाइल फोन भी नहीं होगा और आपका भोजन परिवार का बचा हुआ खाना होगा। ऐसी गरीबी को मिटाने के लिए सभी को मिलकर मुकाबला करना होगा।

तीसरी तरह की गरीबी हमारे और आपके ठीक बगल में मौजूद है। मलिन बस्तियों, झुग्गियों में रहने वाले लोग मजदूर होते हैं, सफाई का काम करते हैं या इमारतें, सड़कें बनाते हैं, पर स्वयं लाभ से दूर रह जाते हैं। यह उन लाखों जिंदगियों के प्रति उदासीनता है, जो हर पल हमें घेरे रहती हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, पर कुछ नहीं करते। वे गरीबी में रह सकते हैं, पर देश के असल गरीब तो हम हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सर्वज्ञ होने की संभावना

वेदों में यह प्रश्न पूछा गया है- *कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति?* यानी ऐसी कौन सी वस्तु है, जिसका ज्ञान हो जाने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है? हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी दर्शन हैं, सब के सब उसी के निर्णय में लगे हुए हैं, जिनके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जगत के तत्वों को थोड़ा-थोड़ा करके जानना चाहे, तो उसे अंततः समय लग जाएगा; क्योंकि फिर तो उसे बालू के एक-एक कण को अलग-अलग रूप से जानना होगा। इस प्रकार सब कुछ जानना असंभव है।

फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहां है? एक-एक विषय को अलग-अलग रूप से जानकर मनुष्य के सर्वज्ञ होने की संभावना कहां है? योगी कहते हैं, सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमूर्त तत्व है। उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। इसी प्रकार, वेदों में संपूर्ण जगत को उस एक अखंड निरपेक्ष सत्स्वरूप में सामान्यीकृत किया गया है। जिन्होंने इस सत्स्वरूप को पकड़ा है, उन्होंने संपूर्ण विश्व को समझ लिया है। उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को इस प्राण में सामान्यीकृत किया गया है। अतएव जिन्होंने प्राण को पकड़ा है, उन्होंने संसार में जितनी शारीरिक या मानसिक शक्तियां हैं, सबको पकड़ लिया है। जिन्होंने प्राण को जीता है, उन्होंने अपने मन को ही नहीं, वरन सबके मन को जीत लिया है। उन्होंने सबको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों की सामान्यीकृत अभिव्यक्ति है।

किस प्रकार प्राण पर विजय पाई जाए, यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है। प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश हैं, सबका यही एक उद्देश्य है। हर एक साधनार्थी को, उसके सबसे समीप जो कुछ है, उसी से साधना शुरू करनी चाहिए। उसके निकट जो कुछ है, उस सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है और मन उससे भी निकटतर। जो प्राण संसार में सर्वत्र व्याप्त है, उसका जो अंश इस शरीर और मन में कार्यशील है, वही अंश हमारे सबसे निकट है।

संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है और मन उससे भी निकटतर। जिस साधक ने इन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने सब कुछ जान लिया।

यह जो क्षुद्र प्राणतरंग है, जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप में परिचित है, वह अनंत प्राण-समुद्र में हमारे सबसे निकटतम तरंग है। हम उस क्षुद्र तरंग पर विजय पाएंगे, तभी समस्त प्राण-समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं। जो योगी इस विषय में कृतकार्य होते हैं, वे सिद्धि पा लेते हैं, तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती। वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं। हम सभी देशों में ऐसे संप्रदाय देख सकते हैं, जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं।

स्वामी विवेकानंद

अनुलोम-विलोम

अलगाववाद

बंदूक से अलगाववाद नहीं सुलझेगा

कश्मीर में अलगाववाद का मुद्दा केवल गोली और बंदूक से नहीं सुलझने वाला, क्योंकि जिस दिन बंदूकें शांत होंगी, उनके हाथों में बेरोजगारी का दर्द और टूटे सपनों की गूंज बाकी रह जाएगी। यह समस्या जितनी राजनीतिक है, उससे कहीं ज्यादा सामाजिक और आर्थिक है। कश्मीर के नौजवानों को जब तक शिक्षा और रोजगार का सही अवसर नहीं मिलेगा, तब तक अलगाववाद की आग बुझाना मुश्किल है। सरकारें अक्सर सोचती हैं कि कुछ कठोर कदम और सख्त कानून से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन असल में उनको यह समझना होगा कि यहां दिल जीतने की जरूरत है। हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहां एक बड़ा अवसर है सामाजिक संवाद और विकास का, जो अगर सही तरीके से किया जाए, तो अलगाववाद की जमीन खोखली की जा सकती है। सच यही है कि जिस दिन कश्मीर के हर घर में रोजगार और हरेक युवा के पास भविष्य का सपना होगा, उस दिन शायद ही कोई गुमराह करने वालों के जाल में फंसे।

अवनीश कुमार गुप्ता, टिप्पणीकार

चुनाव से मिलता संदेश

जम्मू-कश्मीर में लोग तंत्र पर कितना भरोसा करने लगे हैं, इसका पता विधानसभा चुनाव से साफ-साफ चलता है। पहले चरण में सात जिलों की 24 सीटों पर करीब 61 फीसदी तथा दूसरे चरण में 26 सीटों पर 57 फीसदी से ज्यादा मतदान का होना न सिर्फ ऐतिहासिक है, अपितु लोकतंत्र के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था का प्रतीक भी है। गौरतलब यह भी है कि घाटी के जिन इलाकों में अनुच्छेद-370 हटाने का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, वहां भी बढ़-चढ़कर लोगों ने मत डाले। अलगाववादियों के फरमान को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उम्मीद से अधिक मतदान करके यह जता दिया कि उन्हें मशीनगन नहीं, मतदान पर भरोसा है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मिला लोकतंत्र का यह खुशनुमा पैगाम संकेत है कि जम्मू-कश्मीर के लोग अपने भविष्य को लेकर अब जागरूक हैं और बदलाव चाहते हैं। लंबे वक्त से संघर्ष, अस्थिरता और दहशत से जूझ रहे इन लोगों का यह उत्साह उल्लेखनीय है, जो बताता है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर वे अपने सूबे की दशा-दिशा तय करने को आतुर हैं। कश्मीर से इस नई सुबह की उम्मीद सभी भारतीयों को थी। मतदान में लोगों का उत्साह साफ संकेत है कि वे कश्मीर में शांति, पूर्ण जम्हूरियत और विकास चाहते हैं।

हर्षवर्द्धन, टिप्पणीकार

हर मसले का हल बातचीत नहीं

जाने-माने कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं- *क्षमा शोभती उस भुजंग को/ जिसके पास गरल हो/ उसको क्या जो दंतहीन/ विषरहित, विनीत, सरल हो... सहनशीलता, क्षमा, दया को/ तभी पूजता जग है/ बल का दर्प चमकता उसके/ पीछे जब जगमग है।* मतलब साफ है। यदि हम ताकतवर रहेंगे, तभी हमारे द्वारा क्षमा करने का कोई मतलब है, क्योंकि भगवान राम भी तीन दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे और अनुनय-विनय करते रहे, लेकिन समुद्र अपने अहंकार में चूर रहा और जैसे ही प्रभु ने अपने बाण निकाले, सिंधु देह धरकर सामने प्रकट हुआ और भगवान को रास्ता मिल गया। यानी, अलगाववादी हों या आतंकवादी, उनसे निपटने का यही एकमात्र तरीका है, आपको हर हाल में हथियार उठाना ही पड़ेगा। अनुनय-विनय का उन पर कोई असर नहीं होता। ऐसी सोच अपने आप में हास्य का विषय है। जो लोग बंदूक की भाषा समझते हैं, उन्हें भला शांति की भाषा से कैसे समझायी जा सकती है? ऐसा करने पर वे हमें हल्के में लेंगे, बेखौफ अपनी गतिविधियां चलाएंगे।

अगर बातचीत से कश्मीर मसले का हल संभव होता, तो 1947-48 में ही यह हो गया होता। पाकिस्तान से चार-चार बार युद्ध करने की नौबत ही नहीं आती। हमारा यह पड़ोसी देश बार-बार अपने दहशतगर्दों को कश्मीर के रास्ते भारत भेजता है और यहां के नौजवानों को उकसाने का प्रयास करता है। यह तो भला हो हमारे सुरक्षा बलों का कि वे अपनी जान की बाजी लगाकर न सिर्फ ऐसे आतंकियों का सफाया करते हैं [illegible] स्थानीय लोगों में अलगाव[illegible] जो मोहब्बत है, उसे भी [illegible] प्रयास करते हैं। यहां के [illegible] मानो आग में घी डाल[illegible] रहे हैं। वे ऐसे-ऐसे ब[illegible] के लोगों को उकसाते हैं। अगर बातचीत से ही मसले का समाधान होता, तो ऐसे राजनेता भारतीय राजनीति में आ ही नहीं पाते। इस बार भी लोकसभा चुनाव में अलगाववादी समर्थक नेता की जीत हुई है, जबकि विधानसभा चुनावों में कई अलगाववादी समर्थक नेता मैदान में हैं, जिनको अपनी जीत का पूरा विश्वास है।

साफ है, बातचीत एक हद तक ही सही है। अगर आपने अपनी ताकत का एहसास इन अलगाववादियों को नहीं कराया, तो वे समुद्र की तरह आपकी राह में खड़े रहेंगे और आप उनके सामने [illegible]ते रह जाएंगे। उनसे निपटने का [illegible] बंदूक और गोली। जो [illegible] दुश्मन हैं, उनको [illegible] का हक नहीं है, [illegible]सी भी [illegible]खरेगा।

[illegible]न, टिप्पणीकार

चिंतन

घरेलू हिंसा एक्ट सभी धर्म की महिलाओं पर लागू

घरेलू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आधार को स्पष्ट कर सभी महिलाओं को राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि घरेलू हिंसा एक्ट देश की हर महिलाओं पर लागू होता है। यह एक सिविल नेचर का कानून है और यह भारत की हर महिला पर लागू होता है, चाहे वह महिला किसी भी धर्म या सामाजिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हो। उच्चतम न्यायालय की जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा एक्ट (डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट) 2005 सभी वर्ग व धर्म की महिलाओं पर लागू होता है। महिलाओं को भारतीय संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह कानून है। डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट एक सिविल कोड की तरह है, इस तरह से यह भारत की तमाम धर्म व समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं पर लागू होता है। दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को महिला ने चुनौती दी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। चूंकि भारतीय समाज में घरेलू हिंसा व्यापक है, यह सभी धर्मों व जातियों के सामाजिक ताने-बाने में है। घरेलू हिंसा से पुरुष व महिलाएं दोनों पीड़ित हैं, पर अधिकतर महिलाएं शिकार होती हैं। 32 फीसदी विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, 18 से 49 वर्ष की आयु के बीच की 29.3% विवाहित भारतीय महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का सामना किया है; 18 से 49 वर्ष की 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक, वैवाहिक हिंसा की शिकार 87 फीसदी महिलाएं मदद नहीं मांगती हैं। लैंगिक असमानता, मादक पदार्थों का सेवन, दहेज प्रथा, वित्तीय तनाव, सामाजिक-सांस्कृतिक मानक, असुरक्षा या अधिकार से उपजी एक साथी पर प्रभुत्व और नियंत्रण की इच्छा, सामाजिक व आर्थिक तनाव, मानसिक अवस्था, शिक्षा और जागरूकता का अभाव आदि के चलते परिवार में घरेलू हिंसा देखने को मिलती है। भारत में सख्त कानून है, लेकिन इसका दुरूपयोग भी होता है। परिवार में महिलाओं को सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी कवच है। कानून सभी महिलाओं के लिए समान है। कोई भी नहीं कह सकता है कि वह विशेष धर्म से है, तो उस पर घरेलू हिंसा एक्ट लागू नहीं हो सकता है। वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कार्य करता है। लैंगिक आधार पर भूमिकाओं एवं शक्तियों के संबंध में विचारधाराओं में परिवर्तन लाना एक मूलभूत शर्त है। परस्पर सम्मान को बढ़ावा देने तथा समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक मानसिकता के उन्मूलन के लिए पुरुष-महिलाओं पर केंद्रित पहल आवश्यक हैं। कानून प्रवर्तन, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट जैसे हितधारकों के लिए लैंगिक परिप्रेक्ष्य से प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। पूरी न्यायालयी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को निःशुल्क अथवा कम लागत वाले विधिक सहायता तक पहुंच की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उत्तरजीवियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु रोजगार संबंधी प्रशिक्षण व वित्तीय साक्षरता कौशल की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से सभी वर्ग की महिलाओं को मदद मिलेगी।

प्रथम 'अतुल्य भारतीय' का विज़न

पर्यटन दिवस
गजेन्द्र सिंह शेखावत

> इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हमारे बीच एक ऐसे नेता हैं जो न केवल हमारे प्रधानमंत्री हैं बल्कि वे अतुल्य भारत के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर और हिमायती हैं। अपनी हर भूमिका में, वे भारत की बेहतरी के लिए काम करते हैं। मैं यह देखकर अत्यंत विस्मित और प्रेरित होता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव पर्यटन को अत्यंत महत्व देते हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में वे निरंतर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें देश में पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास के लिए कार्य करना है। इस राष्ट्र के वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में वे अतुल्य भारत के विस्मयकारी पहलुओं को विश्व के समक्ष रखने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं।

एक दशक पहले तक भारतीय पर्यटन को पर्यटन क्षेत्र में अन्य देशों के समकक्ष या उनसे आगे स्थापित करने के लिए भी एक ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत सामान्य बात थी। जिस तरह अन्य देश अपने देश के पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु प्रसिद्ध फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन राशि खर्च कर रहे थे, ठीक उसी तरह यहां भी यह महसूस किया गया कि अतुल्य भारत को एक नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है। भारत के केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैंने सभी को यह कहते सुना है कि इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हमारे बीच एक ऐसे नेता हैं जो न केवल हमारे प्रधानमंत्री हैं बल्कि वे अतुल्य भारत के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर और हिमायती हैं। अपनी हर भूमिका में, वे भारत की बेहतरी के लिए काम करते हैं। मैं यह देखकर अत्यंत विस्मित और प्रेरित होता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री सदैव पर्यटन को अत्यंत महत्व देते हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में वे निरंतर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें देश में पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास के लिए कार्य करना है। लगभग 1,50,000 किलोमीटर लम्बा सड़क नेटवर्क बनाने, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए 500 नए हवाई रूट और 150 हवाईअड्डे शुरू किए जाने, तेज गति वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और लगभग 100 पर्यटन परियोजनाओं को पूरा किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में 250 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएं (डीटीवी) दर्ज की गईं, जो वर्ष 2014 में भारत द्वारा दर्ज 128 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) का लगभग दोगुना है।

इस राष्ट्र के वैश्विक प्रतिनिधि के रूप में वे अतुल्य भारत के विस्मयकारी पहलुओं को विश्व के समक्ष रखने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की जी-20 अध्यक्षता इस मायने में अनूठी रही कि इन बैठकों का आयोजन देशभर के 60 अलग-अलग स्थानों पर किया गया। मोदी जी का यह विजन था कि भारत की जी-20 अध्यक्षता को माध्यम बनाकर इन 60 गंतव्यों की पर्यटन पेशकशों के साथ-साथ उनकी संस्कृति, विरासत तथा शिल्प की वैश्विक मंच पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। पिछले वर्ष जी-20 के कारण पर्यटन में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 में भारत के पर्यटन क्षेत्र में होटल के नए कमरे सबसे अधिक संख्या में बनाए गए। एक जन-नायक के रूप में उन्होंने विश्व की यात्रा पर निकलने से पहले अपने देश भारत को देखने-समझने के लिए राष्ट्र को 'देखो अपना देश' हेतु प्रेरित किया है। स्वच्छता के महत्व की सीख देकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उत्तरदायी पर्यटन हम सभी का सहज स्वभाव बन जाए। हर अवसर पर वे वैश्विक प्रवासी भारतीयों को अतुल्य भारत का प्रतिनिधि बनने की उनकी भूमिका निरंतर याद दिलाते हैं कि वे अपने विदेशी मित्रों और परिचितों को इस बात की जानकारी दें कि भारत की यात्रा किस प्रकार उनके लिए अविस्मरणीय हो सकती है। उनके द्वारा लक्षद्वीप, काजीरंगा, कन्याकुमारी, श्रीनगर और अन्य कई स्थलों की यात्रा करने मात्र से घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों में ऐसे गंतव्यों की यात्रा करने और भारत की कम लोकप्रिय पर्यटन पेशकशों का अनुभव करने की अभूतपूर्व रुचि

देखी गई है। पर्यटन में प्रधानमंत्री की निजी रुचि और भागीदारी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पर्यटन विभाग में मुझे अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर देते समय कहा था कि वे मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तब से मेरा निरंतर यह प्रयास रहा है कि समावेशी सामाजिक-आर्थिक प्रगति और विकास के माध्यम के रूप में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम भारत में इसके लिए एक व्यावसायिक योजना तैयार करें। पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इन नए गंतव्यों की परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व को एकता नगर और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की भेंट देने के बाद से इसमें परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप एकता नगर में पर्यटन को प्रमुख आधार के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए और उपाय किए गए। स्थानीय लोगों और युवाओं को पर्यटन से संबंधित सेवाओं और कार्यों के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई। अच्छे होटल, रिजॉर्ट और अन्य आवास स्थापित करने के लिए निजी निवेशों को शामिल किया गया। पीपीपी मोड में विभिन्न थीमों में अनेक नए आकर्षणों, कार्यकलापों और अनुभवों की शुरुआत की गई। इन सभी और अन्य कई कार्यकलापों के कारण एकता नगर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 4.5 लाख से 10 गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 45 लाख हो गई थी। इन सभी प्रयासों से एकता नगर के स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन अर्थव्यवस्था के माध्यम से आजीविका के नए साधन का सृजन हुआ है जो वर्ष 2014 से पहले इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था।

एकता नगर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने हमें पर्यटन विकास और संवर्धन का एक नया मॉडल दिया है, एक ऐसा मॉडल जिसे ऐसे प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का सृजन करने के लिए एक उदाहरण के रूप में अपनाया जा सकता है। स्वदेश दर्शन और प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों के विकास जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थापित मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, पर्यटन मंत्रालय अब 'सरकार के हर स्तर पर' चयनित गंतव्यों को विकसित करने के संयुक्त प्रयासों द्वारा देश में पर्यटन संबंधी गंतव्य विकास की अगुआई कर रहा है। ऐसे अधिक प्रभावकारी हस्तक्षेपों की शुरुआत के प्रयास किए जा रहे हैं जो विभिन्न गंतव्यों में पर्यटक अनुभव को पूरी तरह से बदल सकते हैं। साथ ही, निजी निवेश को सार्वजनिक निवेश का पूरक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भारत में पर्यटन संबंधी गंतव्य विकास के लिए दोनों एक संयुक्त शक्ति के रूप में कार्य कर सकें। इन गंतव्यों में मंत्रालय की विभिन्न पहलों के माध्यम से, कौशल निर्माण और डिजिटलीकरण जैसे पर्यटन साधनों को बेहतर बनाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है ताकि पर्यटन के लाभ उस गंतव्य में ही स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों को प्राप्त हो सकें। प्रधानमंत्री के जन भागीदारी के विज़न से प्रेरित होकर, मंत्रालय ने देखो अपना देश पीपुल्स च्वाइस 2024 नामक एक राष्ट्र-व्यापी पोल शुरू किया है ताकि नागरिक 5 श्रेणियों में भारत में अपने सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों और गंतव्यों के बारे में जानकारी दे सकें। शीर्ष पर आने वाले गंतव्यों को विशेष सहायता और निधि प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें दुनिया के समक्ष सर्वश्रेष्ठ अतुल्य भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक पर्यटन स्थलों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें विकसित भारत के अपने विज़न की याद न दिलाएं। पर्यटन हमें उस महान विज़न को पूरा करने के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। इस विश्व पर्यटन दिवस पर, मैं इस विज़न को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं, ताकि हम अपने प्रधानमंत्री की ही तरह 'अतुल्य भारतीय' बन सकें।

(लेखक केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

इजराइल-हमास युद्ध
डॉ. एस.डी. वैष्णव

बादशाह से पहले वज़ीर की ख़बर ले रहा है इजराइल

कवि बिलाल पठान 'वास्कोडिगामा' की एक कविता याद आ रही है- ''युद्धों के उत्तर हमेशा शून्य आते हैं/ एक दिन आग से मुठभेड़ करते हुए पानी मारा गया/ और एक दिन पानी से मुठभेड़ करते हुए आग मारी गई।'' वर्तमान की वैश्विक परिस्थितियों के मध्यनजर यह कविता बहुत प्रासंगिक बन जाती है। आज हम जिस युद्धाक्रांत समय के साये में जी रहे हैं, वहां से सिर्फ भय और टकराहट की लपटें उठती नजर आ रही हैं। 8 अक्टूबर 2023 को मिडिल-ईस्ट में हमास ने जिस युद्ध का आगाज किया, अब एक साल बाद उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। कुछ दिन पूर्व लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी ब्लास्ट में अपने दर्जनों लड़ाके गंवा चुके हिज्बुल्लाह ने प्रत्युत्तर में इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ संकेत दिया है कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वाले को हम मिट्टी में मिला देंगे। और यह चेतावनी उन्होंने हिज्बुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों को एक साथ दी है। इसके बाद इजराइल ने लगातार लेबनान पर हवाई हमले किए, जिससे वहां के निवासियों के सामने विस्थापन की समस्या उत्पन्न होने लगी है। युद्ध के मोर्चे पर इजराइल 'थ्रीएच' से एक साथ संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी साफ कहा है कि यदि ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाया, तो इजराइल के समर्थन में वे उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। इधर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद जिस तरह से अपना काम कर रही है, मेरे जेहन में उनके द्वारा किया गया 'ऑपरेशन थंडरबोल्ट' बार-बार उठ रहा है। मोसाद अपनी आगे की रणनीति पर पहले से ही काम करना शुरू कर देती है और समय आने पर उसे अंजाम भी देती है। इजराइल-फिलिस्तीन का जमीनी मुद्दा बहुत पुराना है। कई बार इन दोनों देशों के बीच आपसी हमले भी हुए हैं। वहां की सरजमीं पहले भी कई दफ़ा रक्त रंजित हुई है।

इतिहास में झांककर देखेंगे तो वहां बहुत कुछ उठा-पटक मिलती है। लेकिन, इस बार बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। 8 अक्टूबर 2023 को जब हमास तंजीम ने इजराइल पर हमला किया तब से पूरे मिडिल-ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस हमले के बाद से इस्माइल हानिया मोसाद के निशाने पर था। युद्ध शुरू हुए एक साल पूरा होने आया है और हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। कई दृश्य हमें विचलित करते हैं। युवा पीढ़ी को हमसमर सता की बजाय हिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या वाकई में यह स्थितियां खतरनाक नहीं हैं..? इजराइल-हमास युद्ध के बरक्स कुछ युद्ध पिपासु और वॉर इकोनॉमी की आड़ में अपनी जेबें भरने वालों ने पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। जबकि मानव जीवन का ध्येय यह होना चाहिए कि विश्वभर में शांति बनी रहे। महाविनाश के इस दौर में मनुष्यता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे आकर इन युद्धों पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अन्यथा मिडल-ईस्ट में जिस तरह के हालात उपज रहे हैं, उनसे लग रहा है कि युद्ध अवश्य विस्तारित होगा। इसलिए समय रहते धैर्य, संयम और शांति के साथ, बातचीत के जरिए मिडल-ईस्ट में शांति स्थापित की जानी चाहिए। युद्ध विराम हेतु अपने व्यक्तिगत हितों और आपसी टकराहटों से ऊपर उठकर अमेरिका और रूस को एक मंच पर आना चाहिए जिसकी अध्यक्षता भारत के हाथों में हो। इस निर्मम समय में महाविनाश को रोकने की बजाय महाशक्तियां एक-दूसरे के पक्ष-विपक्ष में खड़ी तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिख रही हैं। इस कारण आज दुनिया भी दो अलग-अलग मोर्चों पर खड़ी नजर आती है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। गाजा पट्टी तो पूरी तरह से खंडहरों में तब्दील हो चुकी है। क्या अतीत में हुए दो विश्व युद्धों से उठी कराहती हुई चित्कारें हम भूल रहे हैं? इस बात की सनद रहनी चाहिए कि उन युद्धों के अमिट निशां अब भी मौजूद हैं। युद्धों के इतर हमें उस मनुष्य की खोज करनी है जिसके हिस्से का आकाश बहुत छोटा है। हम विनम्र, सदाचारी और परोपकारी बनें, क्योंकि मनुष्यता की रक्षा के लिए यह समय बहुत विकट हालातों से भरा हुआ है। बहरहाल, जय-पराजय का यह समर किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन, दो महायुद्धों के बीच जन्मी प्रसाद की कामायनी का यह छंद- ''दुःख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात'' इस बात की ताकीद करता है कि दुख की पिछली रजनी को लांघकर, कभी न कभी सुख का नवल प्रभात अवश्य खिलेगा और उस दिन सारा विश्व समरसता की गूंज से भर उठेगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

आनंद, जिसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं

संकलित
दर्शन

कल्पना क्या है और सच्चाई क्या है! इसे समझने के लिए आपकी जड़ का मजबूत होना जरूरी है। सारी कल्पनाएं आपके अंदर हैं। यह कल्पना नहीं है, यह सच है। कल्पना में डूबना बड़ा आसान है, सच्चाई को जानना बहुत मुश्किल है। जिसको आप खोज रहे हैं, वह आपके अंदर है। उसे जानिए, पहचानिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि उसमें सबकुछ है। जो आपके भीतर है, वह है शांति। किसी चीज का न होना शांति नहीं है। किसी चीज का होना शांति है। जब मनुष्य खुद को जानेगा, खुद को समझेगा, तब उसके जीवन में शांति होगी। जैसे भोजन खा लेने पर भूख खत्म होती है, उसी प्रकार खुद को जान लेने पर तृष्णा मिट जाती है। शांति मिल जाती है। सोचें कि यह शरीर आपको क्यों मिला है? जिन तत्त्वों से शरीर बना है, वे सारे तत्त्व वहीं वापस चले जाएंगे जहां से ये आये थे। जिस तरह पानी, पानी में मिल जाता है। सारी चीजें प्रकृति में घुल जाएंगी। क्या समझते हैं आप कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस धरती का वजन बढ़ता है! या जब कोई मर जाता है तो इस धरती का वजन कम होता है! वजन न तो बढ़ता है न कम होता है। क्योंकि जिन चीजों से आप बने हुए हैं वे तो अभी यहीं हैं। परंतु क्या आपने उस चीज को जाना, समझा जो आपके शरीर के अंदर है? इसे जान गए, पहचान गए, फिर आनंद ही आनंद है। आपका नाम आपके शरीर का नाम है। नाम कमाने से क्या होगा। नाम नहीं, ज्ञान कमाइये। आनंद कमाइए। ये आप अपने साथ ले जा सकते हैं।

श्रमरहित जीवन विकास के द्वार बंद करता है

संकलित
प्रेरणा

महर्षि वेदव्यास ने एक कीड़े को तेजी से भागते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछाः हे क्षुद्र जंतु, तुम इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? उनके प्रश्न ने कीड़े को चोट पहुंचाई और वह बोलाः हे महर्षि, आप तो इतने ज्ञानी हैं। यहां क्षुद्र कौन है और महान कौन? क्या इस प्रश्न और उसके उत्तर की सही-सही परिभाषा संभव है? कीड़े की बात ने महर्षि को निरुत्तर कर दिया। फिर भी उन्होंने उससे पूछाः अच्छा यह बताओ कि तुम इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? कीड़े ने कहाः मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। देख नहीं रहे, पीछे से कितनी तेजी से बैलगाड़ी चली आ रही है। कीड़े के उत्तर ने महर्षि को चौंकाया। वे बोले, तुम तो इस कीट योनि में पड़े हो। यदि मर गए तो तुम्हें दूसरा और बेहतर शरीर मिलेगा। इस पर कीड़ा बोलाः महर्षि, मैं तो इस कीट योनि में रहकर कीड़े का आचरण कर रहा हूं, परंतु ऐसे प्राणी असंख्य हैं, जिन्हें विधाता ने शरीर तो मनुष्य का दिया है, पर वे मुझसे भी गया-गुजरा आचरण कर रहे हैं। कीड़े की बातों में महर्षि को सत्यता नजर आई। वे सोचने लगे कि वाकई जो मानव जीवन पाकर भी देहासक्ति और अहंकार से बंधा है, जो ज्ञान पाने की क्षमता पाकर भी ज्ञान से विमुख है, वह कीड़े से भी बदतर है। महर्षि ने कीड़े से कहाः नन्हें जीव, चलो हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं। कीड़ा बोलाः किंतु मुनिवर श्रमरहित पराश्रित जीवन विकास के द्वार बंद कर देता है। कीड़े के कथन ने महर्षि को ज्ञान का नया संदेश दिया।

अंतर्मन

आज की पाती

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती की जा रही है। अगर किसी नाबालिग को वाहन चलाते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो इसके लिए सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कानून के तहत लगभग 25 हजार जुर्माना और लगभग तीन साल की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए, स्कूलों में इसके लिए बच्चों को जागरूक भी किया और स्कूलों ने विद्यार्थियों के माता-पिता को इसके लिए नोटिस भी भेजे हैं कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। दोपहिया वाहन एक्सीडेंट का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर एक्टिवा चलाते समय हैल्मेट का प्रयोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए जरूर करना चाहिए, न कि चालान के डर से।

- सांकेत वर्मा, भाटापारा

ट्रेंड

भगवान शिव से प्रार्थना की

राजस्थान के सूरसागर की पूर्व विधायक और भाजपा की वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। क्षेत्र में जनकल्याण के अपने कार्यों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। ओम शांति!
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सड़कें जल्द ठीक होंगी

उन्होंने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे। आज मैंने मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सड़क का निरीक्षण किया। दिल्ली की सड़कों को जल्द ठीक कराया जाएगा। अब मैं वापस आ गया हूं, दिल्ली के लोग चिंता न करें।
-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम दिल्ली

अपने सपनों को पूरा करें

एक बार जब आप कुछ शुरू करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। आगे बढ़ने वाला हर छोटा कदम आपको महानता के करीब लाता है।
- मनु भाकर, भारतीय शूटर

'ताल' की 25वीं वर्षगांठ

मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुंबई में फिल्म ताल की 25वीं वर्षगांठ मनाने और जनता की मांग पर 136 थिएटरों में ताल की रिलीज के लिए फिर से ताल के होर्डिंग्स दिखाई देंगे। बड़े पर्दे पर संगीतमय चलचित्र देखना युवाओं के लिए नया अनुभव होगा।
-सुभाष घई, फिल्म निर्देशक

करंट अफेयर

उ. कोरिया के पास बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम

दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने बृहस्पतिवार को सांसदों को बताया कि ऐसी आशंका है कि उत्तर कोरिया ने कई बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम संवर्धन कर लिया है और वह दक्षिण कोरिया को निशाना बनाने के लिए अधिक शक्तिशाली व सटीक निशाने लगाने वाली मिसाइलें बनाने के अपने प्रयासों में आगे बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने हथियार बनाने के लिए आवश्यक यूरेनियम के उत्पादन के लिए स्थापित एक गुप्त संयंत्र की दुर्लभ झलक पेश की थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने सांसदों को स्थिति से अवगत कराया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहरा चुके हैं। बैठक में भाग लेने वाले सांसदों में से एक ली सियोंग-क्वेन के अनुसार, दक्षिण कोरियाई एजेंसी का आकलन है कि किम द्वारा संयंत्र के बारे में खुलासा करने का उद्देश्य संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले वाशिंगटन को चेतावनी देना और गहराते आर्थिक संघर्षों के बीच घरेलू स्तर पर अपनी सैन्य उपलब्धियों का प्रदर्शन करना था।

ऑफ बीट

भविष्य के आहार में आयरन जैसे तत्वों की कमी होगी

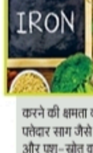

आयरन की कमी दुनिया भर में पोषक तत्वों की कमी के सबसे आम रूपों में से एक है। जैसे-जैसे लोग वनस्पति आधारित आहार अपनाने पर विचार करेंगे, आयरन की कमी का खतरा बढ़ने की संभावना होगी। इससे पता चलता है कि अगर खाद्य उत्पादन और आपूर्ति के 'वैश्विक पैटर्न' नहीं बदले, तो 2040 तक आहार में आयरन की कमी हो सकती है। इसका मतलब है कि हमें अपने आहार में आयरन की कमी को दूर करना होगा। ब्रेड और अनाज जैसे सामान्य खाद्य पदार्थ सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ में पहले से ही अतिरिक्त पोषक तत्व हैं। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में अक्सर उच्च मात्रा में फाइबर और फाइटेट होते हैं, जो शरीर की आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देते हैं। साबुत अनाज, नट, बीज, फलियां और पत्तेदार साग जैसे वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में आयरन भरपूर होता है और पशु-स्रोत वाले खाद्य पदार्थों में मौजूद आयरन की तुलना में कम आसानी से अवशोषित होता है। मिश्रित आहार यानी सब्जियां, अनाज और पशु-स्रोत वाले खाद्य पदार्थ जैसे कुछ मछलियों, लाल मांस या मुर्गे का सेवन आयरन अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है।

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोनः 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

प्रबंधन कर्मचारियों के साथ जैसा बर्ताव करता है, उसका असर सभी चीजों पर पड़ता है। -साइमन सिनेक

पर्यावरण डाटा कंपनी कैरोस का शोध बताता है कि कार्बन डाई ऑक्साइड से भी घातक मीथेन गैस के उत्सर्जन में कटौती की शपथ लेने के बावजूद अमेरिका लगातार वातावरण में ज्यादा से ज्यादा मीथेन छोड़ रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है।

खतरे की घंटी

आगामी पांच नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भले ही वहां ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन पर्यावरण डाटा कंपनी कैरोस के शोध का यह बताना कि अमेरिका सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस मीथेन की बेहद अधिक मात्रा वायुमंडल में छोड़ रहा है, अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, जो पर्यावरणीय दावों और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में अमेरिका उन पहले देशों में शामिल था, जिन्होंने वैश्विक मीथेन शपथ पर हस्ताक्षर किए थे। कुल 158 देशों ने इस शपथ पर हस्ताक्षर करके मीथेन के उत्सर्जन को एक दशक के भीतर 2020 के स्तर से 30 फीसदी कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके बावजूद अगर अमेरिका, जो जलवायु परिवर्तन की वैश्विक लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने का दावा भी करता है, अपने मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव घातक भी हो सकते हैं। पहले से ही जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जूझ रहे विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सो अलग। दरअसल, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के ज्यादातर प्रयास अब तक कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर ही केंद्रित रहे हैं। लेकिन इसकी तुलना में मीथेन का प्रभाव करीब 80 गुना अधिक होता है। गौरतलब है कि धरती को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों में सबसे खतरनाक मीथेन ही है, जो कार्बन डाई ऑक्साइड के विपरीत खपत से नहीं, बल्कि गैस के उत्पादन व परिवहन से पैदा होती है। पशुधन, अपशिष्ट पदार्थों के निपटान वाली जगहों के साथ आर्द्र भूमि में भी यह पाई जाती है। वनाग्नि, सूखा, बाढ़ और तूफानों में अप्रत्याशित वृद्धि का खतरा पहले ही मंडरा रहा है, अब अगर मीथेन पर काबू नहीं किया गया, तो प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि ही होगी। राष्ट्रपति बाइडन का नया कानून मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने की रणनीतियों पर अरबों डॉलर खर्च करने की बात जरूर करता है, लेकिन पिछले दशकों में पर्यावरणीय मुद्दों पर जो भी प्रतिबद्धताएं जाहिर की गई हैं, उनमें अमेरिका व चीन जैसे सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों का जैसा रवैया रहा है, उससे उम्मीद बंधती नहीं दिखती। चीन ने तो वैश्विक मीथेन शपथ पर हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। मीथेन उत्सर्जन कोई राष्ट्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक संकट है। ऐसे में समृद्ध देशों को अपने निहित स्वार्थों व दोहरे मापदंडों को त्यागते हुए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ठोस कदम उठाने ही होंगे।

सभी को काम करने का स्वस्थ माहौल मिले

काम की अधिकता की वजह से पुणे में 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत और चेन्नई में डिलीवरी में विलंब होने पर ग्राहक द्वारा डांटे जाने पर 19 वर्षीय युवक की खुदकुशी के मामले चेताते हैं कि भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने व स्थिर समाज के लिए जरूरी है कि सभी को काम करने का स्वस्थ माहौल मिले।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

कोई भी देश अपने युवाओं में तनाव के संकेतों पर ध्यान न देने का जोखिम नहीं उठा सकता। खासकर, विशाल आकांक्षाओं और युवा आबादी की बहुलता वाले देश के लिए युवाओं की चिंताओं के प्रति बेपरवाही बहुत ही घातक हो सकती है। अपने युवाओं के बिना देश का कोई भविष्य नहीं होता। हमें खुदकुशी, काम की अधिकता से होने वाली मौतों, कलहपूर्ण कार्य संस्कृति और शोषणकारी कार्य प्रथाओं जैसी देश के युवाओं को प्रभावित करने वाली डरावनी रिपोर्टों और इनके निहितार्थों पर खुलकर आवाज उठानी चाहिए।

ज्यादातर लोग 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की दुखद मौत के बारे में जानते हैं। कथित आरोप है कि उनकी मौत शीर्ष वैश्विक अकाउंटिंग फर्म ईवाई ग्लोबल की पुणे स्थित फर्म एसआर बाटलीबोई में काम की अधिकता के कारण हुई थी। खबरों के मुताबिक नौकरी जॉइन करने के चार महीने बाद पेरायिल की मौत जुलाई में हो गई थी। अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की मां अनीता ऑगस्टाइन की ओर से भारत में कंपनी के चेयरमैन को लिखा गया पत्र हाल ही में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत ज्यादा काम करवाने की वजह से हुई।

ऑगस्टाइन ने कहा कि उनकी बेटी ने नई नौकरी की मांगों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत की थी, लेकिन काम की अधिकता, नया माहौल और लंबे समय तक काम करने का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ा। देश का सोशल मीडिया इस होनहार युवा महिला की असमय मौत की वजह से गुस्से और आक्रोश से भरा हुआ है। श्रम मंत्रालय ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी को भारी विरोध वाली प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने एक बयान जारी कर सेबेस्टियन की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सभी कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वादा किया है। यह बहुत ही भयावह कहानी है, किंतु यह इस तरह की अकेली घटना नहीं है। न ही अधिक काम और तनाव केवल कंपनियों के उच्च अधिकारियों या शीर्ष कंपनियों में कार्यरत लोगों को प्रभावित कर रहा है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि ऐसे देश में जहां शिक्षित लोगों समेत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी का शिकार हैं और जहां बहुत ज्यादा लोग बेहद सीमित नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, असुरक्षा और तनाव युवाओं को अत्यधिक निराशा के गर्त में धकेल रहा है, जो कभी-कभी उनकी मौत का कारण भी बन रहा है।

अन्ना की कहानी दिल दहला देने वाली है। ऐसी ही कहानी पार्टटाइम डिलीवरी का काम करने वाले 19 वर्षीय जे पवित्रन की है, जिसने इसी माह डिलीवरी में विलंब होने पर एक ग्राहक द्वारा डांटे जाने पर खुदकुशी कर ली। यह युवा बी. कॉम का विद्यार्थी था। पुलिस के अनुसार, चेन्नई के पश्चिमी हिस्से में स्थित कोरात्तुर में पवित्रन को एक महिला ग्राहक के यहां किराने का सामान पहुंचाने में थोड़ा विलंब हो गया था, इस पर महिला ने उसको डांटा था। दरअसल, पवित्रन को उसका घर ढूंढने में कठिनाई हुई थी, जिसकी वजह से उसे विलंब हो गया। महिला ने डिलीवरी कंपनी में शिकायत की और आगे से पवित्रन को दोबारा डिलीवरी के लिए नहीं भेजने के लिए भी कहा।

भारतीय एक सप्ताह में औसतन 46.7 घंटे काम करते हैं, जो जापान (36.6 घंटे), दक्षिण कोरिया (38.16) और चीन (46.1) समेत कई अन्य एशियाई देशों से ज्यादा है। भारत का 51 प्रतिशत कार्यबल साप्ताहिक रूप से 49 घंटे से अधिक काम करता है, जिससे भारत विस्तारित कार्य घंटों के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में भूटान अपने 61 प्रतिशत कार्यबल के साथ 49 घंटे की सीमा को पार करने के साथ सबसे आगे है। हालांकि, केवल लंबे समय तक काम करना ही नहीं, बल्कि काम का माहौल, शोषणकारी प्रथाओं और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी के साथ ही सामाजिक सुरक्षा की कमी भी है, जो सामूहिक रूप से हमारे युवाओं पर भारी पड़ रही है।

अन्य देशों की तुलना में भारत में ज्यादातर युवाओं की मौतें खुदकुशी की वजह से हो रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डाटा के अनुसार, आत्महत्या के सभी मामलों में चालीस फीसदी से ज्यादा मामले तो 30 वर्ष से कम की उम्र वाले युवाओं के हैं। हाल में हुई मौत और खुदकुशी के मामले चेतावनी दे रहे हैं। ये मामले समग्र माहौल और काम की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं के लिए सहायता तंत्र की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इससे भारत में काम और जीवन संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य और श्रम नीति के जटिल मुद्दे भी उजागर होते हैं, क्योंकि देश के आधे से अधिक कार्यबल को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। इसलिए कुछ मिथकों को तत्काल खत्म करने की जरूरत है। काम की अधिकता और तनावपूर्ण कार्यस्थल उत्पादकता को बढ़ाते कतई नहीं हैं।

हतोत्साहित और तनावपूर्ण कार्यबल भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने और स्थिर समाज के निर्माण में सहायक नहीं होगा। उदाहरण के लिए भारत में कई श्रमिकों (गिग वर्कर्स) को अक्सर अत्यधिक तापमान में काम करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियां पैदा हो सकती हैं। श्रमिकों के अधिकार शीर्ष प्राथमिकता में होने चाहिए, भले ही वे उच्च स्तरीय कर्मचारी हों या असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक। वर्तमान में भारत में फिलहाल ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है, जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को लक्षित करते हुए विनियमित करता हो। सामाजिक सुरक्षा के नियम केवल यह परिभाषित करते हैं कि गिग वर्कर्स कौन हैं।

राजस्थान और कर्नाटक ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून जरूर बनाए हैं, लेकिन उनमें भी कमियां हैं। हमें ऐसे स्थायी कार्य वातावरण की जरूरत है, जो स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ावा दे और निराश श्रमिकों के परामर्श की व्यवस्था भी कराए। आत्महत्या को रोकने संबंधी परामर्श अधिक व्यापक रूप से सुलभ होने चाहिए। हाल ही में देश में हुई दुखद मौतों के पीछे बड़ा कारण बढ़ता मानसिक स्वास्थ्य संकट ही है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

निकोला टेस्ला

मां! एक बार फिर से मेरे मन में तुम्हारे बारे में विचार आ रहे हैं। मुझे उन रास्तों को चुनने के लिए माफ करें, जो मुझे आपसे दूर ले गए। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अब भी आपका हिस्सा हूं।

काश, मां के लिए एक गिलास पानी ला पाता!

मेरी प्यारी मां, जब मैं आपके बारे में सोचता हूं, मैं बेरंग हो जाता हूं और दुखी महसूस करता हूं। काश मैं आपके पास होता मां, और आपके लिए एक गिलास पानी ला पाता। मां, आपसे दूर मानवता की सेवा में बिताए इन सभी वर्षों में मुझे सिर्फ अपमान और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। आज सुबह मैं जल्दी उठ गया, भोर होने से पहले, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सुना, जो मैं पिछले कुछ दिनों से अपने सपनों में भी सुन रहा था। मेरे कानों में किसी दुख को बयां करने की आवाज आ रही थी। जब मेरी आंखें पूरी तरह से खुलीं और मैं अपने होश में आया, तो महसूस हुआ मानो यह आवाज हर तरफ से आ रही हो।

मुझे लगता है कि इन आवाजों के बारे में डॉक्टर लियोनेल को बताना चाहिए, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं रहा। एक बार फिर से मेरे मन में तुम्हारे बारे में विचार आ रहे हैं, मां, और फिर से वही बेचैनी और दुख महसूस हो रहा है। मां, मैंने पेटेंट कार्यालय को प्रयोग की तारीख को बदलने के लिए लिखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मां, मैंने सोच रखा था कि मानव जाति को उसके हक का उपहार देने के बाद ही तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन आपकी याद मुझे हरदम सताती है। मां, आज मैं कांग्रेस सत्र में शामिल हुआ। मैंने नियाग्रा फॉल्स की प्रयोगशाला में फोन कर टर्बाइन चालू करने को कहा। मशीन चालू होते ही, पूरा हॉल जगमगा उठा। जैसा मैंने कहा था कि यह सामान्य बिजली से दस गुना ज्यादा रोशनी थी। जब मैं चमकते हुए बल्ब को देख रहा था, तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इन सब का निर्माता नहीं था। मैंने उस चीज की खोज की, जो पहले से ही अस्तित्व में थी। इस जीत और खुशी के जश्न में, मुझे कुछ खोखलापन महसूस हो रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ बड़ा खो दिया है। मेरे चारों ओर वही आवाज सुनाई दे रही है। मां, मुझे अब इस बात का यकीन हो गया है कि यह पत्र आप तक कभी नहीं पहुंचेगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसे आपके लिए क्यों लिख रहा हूं, जब कि आप इसे पढ़ नहीं सकतीं। शांति से आराम करें मां और मुझे उन रास्तों को चुनने के लिए माफ करें, जो मुझे आपसे दूर ले गए। मैं आपके अंतिम संस्कार के लिए वहां नहीं पहुंच सका। मैंने वह टेलीग्राम पढ़ा, जिसमें आपकी मृत्यु की सूचना थी। मुझे उन लोगों से घृणा हो रही है, जो दो साल पहले तक यह समझने के लिए तैयार नहीं थे कि बिजली बिना तारों के भी स्थानांतरित की जा सकती है। मैं ट्रेन से ज्यूरिख आ रहा हूं और फिर सीधे घर। इसमें करीब दस दिन लगेंगे। जब मैं अपने गांव के कब्रिस्तान पहुंचूंगा, तो यह पत्र तुम्हारी कब्र पर रखूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं अब भी तुम्हारा हिस्सा हूं।

(आधुनिक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की खोज करने वाले महान सर्बियाई-अमेरिकी इंजीनियर द्वारा अपनी मां के निधन पर लिखे मार्मिक पत्र के संपादित अंश)

परीक्षा के लिए तैयार रहें

सूत्र

जीवन में उद्देश्य हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि यही उद्देश्य आपको अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। इन उद्देश्यों को पाने के लिए भी परीक्षा देनी होती है। जितना बड़ा उद्देश्य, परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। परीक्षा से भयभीत न हों और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें।

दूसरा पहलू

बिजली से भारत में प्रतिवर्ष करीब 2,000 लोगों की मौत होती है। इस वर्ष यूपी में गाज गिरने से 319 लोगों की जान जा चुकी है।

ताकि किसी पर बिजली न गिरे

अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रेंकलिन ने वर्ष 1753 में बिजली यानी गाज से जानमाल के बचाव के लिए तड़ित चालक रॉड का आविष्कार किया था। बेशक शहरों में भवनों पर लगे तड़ित चालक बिजली के प्रभाव को कम करने में कारगर साबित हो रहे हैं, पर ग्रामीणों की चिंता बरकरार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में हर साल 20 हजार से ज्यादा लोग बिजली की चपेट में आ जाते हैं। भारत में हर साल तड़ित वृष्टि से 2,000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में होती हैं और खेतों में काम करने वाले लोग इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं।

अमरनाथ

लोगों को सतर्क करने के लिए पांच साल पहले भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे द्वारा दामिनी लाइटनिंग एप लॉन्च किया गया था। अगर 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने वाली होती है, तो यह एप उपयोगकर्ता को 40 मिनट पहले सचेत कर देता है। देश में दस लाख से ज्यादा लोग अब तक इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में एंड्रॉयड मोबाइल फोन वाले लोग कम होने के कारण यह उपाय उतना कारगर साबित नहीं हो सका। चिंता इस बात की है कि आधुनिक जमाने में भी इस मानसून में बिजली गिरने से लोगों की जान चली गई। जागरूकता के लिए तमाम उपाय किए गए, फिर भी किसानों के लिए बिजली से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं हो सके।

दामिनी लाइटनिंग एप बिजली गिरने से 40 मिनट पहले ही लोगों को सचेत कर देता है कि 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में गाज गिरने की आशंका है।

ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज जैसे जिलों में ज्यादा बिजली क्यों गिरती है? कहीं इसके लिए बांध या खनिज जिम्मेदार तो नहीं? ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। इनके कारणों पर अभी और शोध करने की जरूरत है।

देश के सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से इस साल एक अप्रैल से अब तक 319 लोगों की मौत हो चुकी है। यदि ललितपुर जनपद की बात करें, तो इस साल गाज गिरने से 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले साल 14 लोगों की जान गई थी। जाहिर है कि इस बार बिजली गिरने की घटनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा हुई हैं। अब उत्तर प्रदेश के कई गांवों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी है। कई गांवों में ये सिस्टम लगा भी दिए गए हैं। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि बिजली गिरने के लिए मुख्य रूप से भौगोलिक स्थितियां जिम्मेदार हैं। बताया जाता है कि विंध्य क्षेत्र में सिलिका की पहाड़ियों और उसके आसपास खेतों में बिजली ज्यादा गिरती है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि बिजली से बचाव के लिए अभी कई स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज जैसे जिलों में ज्यादा बिजली क्यों गिरती है? कहीं इसके लिए बांध या खनिज जिम्मेदार तो नहीं? ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। इनके कारणों पर अभी और शोध करने की जरूरत है।

आंकड़े

आर्थिक वृद्धि

पिछले दस वर्षों में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की है। शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर है।

भारत	92.38%
चीन	83.50%
अमेरिका	62.06%
ब्रिटेन	20.02%
जर्मनी	19.38%

आंकड़े 2013-23 तक की आर्थिक वृद्धि के, प्रतिशत में। | स्रोत : IMF

भगवान को फल का भोग लगाने से पहले चक्रिक उसे खुद चखते थे, एक दिन पका हुआ फल उनके गले में चला गया, उन्हें दुख हुआ कि वह प्रभु को भोग नहीं लगा सके।

चक्रिक के समान कोई भक्त नहीं

अंतर्यात्रा
संकलित

द्वापर युग में चक्रिक नामक संत वन में निवास करते थे। वह सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वन में भगवान की एक मूर्ति थी। वह जब कोई सुंदर फल देखते, तो पहले उसे चखते और जो सबसे स्वादिष्ट होता, उसका भगवान को भोग लगाते।

एक दिन चक्रिक ने पका फल देखा और स्वाद जानने के लिए उसको जीभ पर रखा। फल बहुत ही स्वादिष्ट था। परंतु जीभ पर रखते ही वह गले में उतर गया। चक्रिक को बड़ा विषाद हुआ कि स्वादिष्ट भोग वह भगवान को नहीं लगा सका। उसने दाहिने हाथ से अपना गला दबा लिया, ताकि फल पेट में न चला जाए। वह चिंता करने लगा कि मैं भगवान को अत्यंत मधुर भोग न खिला सका, मेरे समान पापी और कौन होगा? अपने गले से फल निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फल नहीं निकला, तो अंत में उसने भगवान की मूर्ति के समीप आकर कुल्हाड़ी से अपना गला एक तरफ से काटकर फल निकाला और भगवान को अर्पण किया। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, 'चक्रिक के समान मेरा भक्त कोई नहीं!' भगवान ने उसे उठाया और उसकी सारी पीड़ा दूर कर दी। चक्रिक ने भगवान के दर्शन पर आनंदित होकर उनकी स्तुति की। भगवान ने वर मांगने के लिए बोला, तो चक्रिक ने कहा, 'हे कृपामय परमात्मन! जब मैंने आपके दर्शन किए हैं, तो मुझे और किसी वर की आवश्यकता नहीं है। बस यही वर दीजिए कि मेरा चित्त सदा आप में लगा रहे।'

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 14 अप्रैल, 1960

भू-समस्या भूदान से हल होगी : विनोबा

भू-समस्या भूदान से हल होगी

आचार्य विनोबा भावे ने सरकार की भूमि सुधार नीति पर पुनः प्रहार किया और कहा कि जोतों की अधिकतम सीमा तय करने से भूमि समस्या हल नहीं होगी। इसका एकमात्र हल भूदान है।

बहुत हुई बयानबाजी

मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में 56 युद्ध और गृहयुद्ध चल रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए वैश्विक नेतृत्व को ठोस उपाय करने होंगे।

भारत डोगरा

वैश्विक संकट

ऐसे समय में जब विश्व बहुत गंभीर पर्यावरण संकट से गुजर रहा है, होना तो यह चाहिए कि युद्ध की आशंका को समाप्त कर पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी देश आपस में सहयोग बढ़ाएं। लेकिन इस समय तो यह एक बहुत दूर का आदर्श लगता है। जिस समय विश्व में शांति व सहयोग की जरूरत सबसे अधिक है, उसी समय युद्ध का संकट वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है।

ग्लोबल पीस इंडेक्स की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में 56 युद्ध और गृहयुद्ध चल रहे हैं। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इस समय युद्ध व गृहयुद्ध की संख्या सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि अब युद्ध अधिक लंबे खिंच रहे हैं। 1970 के दशक में 23 प्रतिशत युद्धों का अंत शांति समझौतों से हुआ, जबकि 2010 के दशक को देखें, तो इसमें केवल चार प्रतिशत युद्धों का अंत शांति समझौतों के जरिये हुआ। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट ने बताया है कि किसी बड़े युद्ध की संभावना अब पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गई है।

यह स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हाल के समय में हथियार निरंतर अधिक विध्वंसक होते गए हैं। अनेक तरह के महाविनाशक हथियार मौजूद हैं, जिनमें परमाणु बमों का खतरा सबसे अधिक है। इस समय विश्व में लगभग 13,000 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 85 प्रतिशत अमेरिका और रूस के पास हैं। कुल नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं और लगभग पांच अन्य देशों में महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं। यदि कभी कुल उपलब्ध परमाणु हथियारों में से लगभग 5 से 10 प्रतिशत हथियारों (यानी 650 से 1300 हथियारों) का उपयोग हो गया, तो विश्व में मानव जीवन व अधिकांश अन्य तरह का जीवन लगभग समाप्त ही हो जाएगा। इन हथियारों के भयानक विस्फोट, आग व इनकी रेडियोधर्मिता से अधिकांश लोग मारे जाएंगे। फिर इससे इतना धूल-गुबार उठेगा कि धरती पर सूर्य की किरणों का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, पौधे नहीं उग पाएंगे व जो लोग बचेंगे वे भूख से मर जाएंगे। इसे 'न्यूक्लियर विंटर' की स्थिति कहा जाता है।

विश्व के ज्यादातर लोग इन बड़े खतरों से बेखबर होकर अपने जीवन की व्यस्तताओं में लगे हैं, लेकिन यह संकट निरंतर बना हुआ है। अब हथियारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का अधिक उपयोग होने लगा है, रोबोट या रोबोटिक्स के हथियार बन रहे हैं, जो और खतरनाक हैं। इनमें सबसे खतरनाक वे हथियार हैं, जो एक सीमा के बाद मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। इन प्रक्रियाओं के विरुद्ध विश्व के अनेक जाने-माने विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे हथियारों को मत लाओ, यह असहनीय तबाही करेंगे। पर बड़ी शक्तियां हथियारों की ऐसी दौड़ या होड़ में लगी हैं कि इन महत्वपूर्ण चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक महाशक्ति महाविनाशक हथियारों की दौड़ में एक कदम आगे बढ़ती है, तो दूसरी महाशक्ति दो कदम आगे बढ़ती है। महाशक्तियों में यह प्रवृत्ति भी बढ़ रही है कि अपने से छोटे देशों को एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर किया जाए। इसे परोक्ष युद्ध (प्रॉक्सी वार) कहा जाता है। यह परोक्ष युद्ध भी बहुत तबाही कर रहे हैं। उधर, अनेक अन्य देशों में गृहयुद्ध ने भी बहुत तबाही मचाई है, जैसा कि सूडान, यमन, म्यांमार आदि कई देशों में देखा जा सकता है।

युद्ध की संभावना को न्यूनतम करने के लिए विश्व नेतृत्व और संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक सक्रियता व प्रतिबद्धता दिखानी होगी। केवल विश्व शांति के नाम पर हो रही बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि विश्व का एक वर्ष का सैन्य खर्च 2,500 अरब डॉलर के आसपास है (हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार, यह इससे भी कहीं अधिक है) पर विश्व शांति प्रक्रियाओं व प्रयासों के लिए इसकी तुलना में एक प्रतिशत का भी बजट उपलब्ध नहीं है।

विश्व में शांति आंदोलन बहुत कमजोर है, जबकि इस समय इसका सशक्तीकरण अत्यावश्यक है। यदि विश्व के सभी अथवा अधिकांश देशों में, विशेषकर अधिक शक्तिशाली देशों में, यदि लाखों लोग अमन-शांति व निशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, तो विश्व शांति की मांग को आगे बढ़ाने वाला एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जो निरंतरता से युद्ध के संकट को कम करने व महाविनाशक हथियारों के संकट को कम करने के लिए प्रयास करेगा। प्रायः यह कहा जाता है कि इतनी बड़ी समस्याओं के समाधान में जनसाधारण की कोई भूमिका नहीं है। इस सोच के कारण ही विश्व शांति व निशस्त्रीकरण के लिए कोई बड़ा आंदोलन तैयार नहीं हो सका है। वास्तव में शांति आंदोलन से अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे, तो आसपास के जीवन में अमन-शांति व अहिंसा का प्रवेश होने से दैनिक जीवन में भी बहुत सुधार आएगा। इस तरह शांति आंदोलन को सशक्त करना, तो हर स्तर पर ही जरूरी है।

बढ़ता विचार

दैनिक बढ़ता राजस्थान

सम्पादकीय

कश्मीर घाटी में विदेशी राजनयिकों का दौरा, मोदी सरकार थपथपा रही अपनी पीठ

जम्मू-कश्मीर पर स्वाभाविक रूप से दुनिया की नजर रहती है। पाकिस्तान इस इलाके को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी के बारे में गलतबयानी करता रहता है, वहां आतंकवाद फैलाने में जुटा हुआ है। हालांकि, ऐसी गतिविधियों में अपना कोई हाथ होने से भी वह लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन उसकी कारगुजारियां जगजाहिर हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार ने वहां आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया है और अब जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में लोग काफी उत्साह से मतदान कर रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान घाटी में विभिन्न देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का दौरा हुआ है। उन लोगों ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोगों से बात की।

कूटनीति के लिहाज से यह कवायद सार्थक लगती है। मतदान के दौरान विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित दूतावासों में कार्यरत राजनयिकों के लिए घाटी की यात्रा आयोजित की। इसके पीछे तर्क दिया गया कि इससे विभिन्न देशों तक जम्मू-कश्मीर के हालात की असल जानकारी पहुंच सकेगी। पहले चरण में मतदाताओं का काफी उत्साह दिखा। दूसरे चरण में भी मतदान के आंकड़े उत्साहजनक रहे। हालांकि, राजनयिकों की इस यात्रा पर विपक्षी दलों ने एतराज जताया है। नैशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने तल्ख लहजे में कहा कि हमें इन राजनयिकों के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार विदेशी पत्रकारों को घाटी में आने की इजाजत नहीं देती, तो राजनयिकों को यहां लाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है।

दरअसल, अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद घाटी में पैदा हुए हालात को लेकर दो विपरीत धारणाएं फैलाई जाती रही हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद घाटी में स्थिति बेहतर हुई है, जबकि विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि वहां हालात ठीक नहीं हैं। आतंकी घटनाओं और सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ने को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन सबके बावजूद विधानसभा चुनाव में लोग बढ़-चढ़ कर मतदान करते देखे जा रहे हैं। पहले चरण में साठ फीसद से अधिक मतदान हुआ। दूसरे चरण में भी खूब उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में, केंद्र सरकार खुलकर कह सकती है कि विशेष राज्य का दर्जा हटाने का उसका फैसला गलत नहीं था और लोग उससे खुश हैं।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद, करीब चार वर्ष पहले भी यूरोपीय संसद के सदस्यों को घाटी में ले जाया गया था। तब भी सवाल उठाए गए थे। तब सरकार ने कहा था कि वह यात्रा एक स्वयंसेवी संगठन ने आयोजित की थी। पिछले महीने भी अमेरिका और जर्मनी के राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर की यात्रा कराई गई थी। दरअसल, जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद पर जब भी किसी देश ने मध्यस्थता की बात उठाई, भारत सरकार ने हमेशा उसे ठुकराया है। भारत सरकार का रुख रहा है कि जम्मू-कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है।

भाजपा के लिए दूसरा अयोध्या न बन जाए माता वैष्णो देवी की सीट!

भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और नासिक जैसी धार्मिक नगरी वाली सीट जीत नहीं सकी। यही नहीं उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंगलोर सीट पर मिली हार से भाजपा की काफी किरकिरी हुई थी। इतना ही नहीं प्रयागराज और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीट भाजपा हार गई थी। भाजपा को अयोध्या में तब चुनावी मात खानी पड़ी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में मिली चुनावी शिकस्त से भाजपा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। यही वजह है कि भाजपा अब श्री माता वैष्णो देवी सीट किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है।

अशोक भाटिया

जम्मू-कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर लगी हैं। ये सीट अनुच्छेद-370 के बाद हुए परिसीमन से अस्तित्व में आई है। इससे पहले ये क्षेत्र रियासी सीट का हिस्सा था। माता वैष्णो देवी सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। भाजपा के लिए ये सीट इसीलिए अहम हो गई, क्योंकि यह धार्मिक लिहाज से हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या और बद्रीनाथ जैसा सियासी हश्र भाजपा का माता वैष्णो देवी की सीट पर न हो जाए, इसके लिए किसी तरह कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 के खत्म होने के बाद हुए परिसीमन से माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई है। पहले यह इलाका रियासी सीट में ही आता था। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया था। इसके बाद 2014 में भी भाजपा जीतने में सफल रही। बीते 16 सालों से भाजपा का ही वर्चस्व बना हुआ है। इसी दबदबे को बनाए रखने के लिए भाजपा ने बलदेव राज शर्मा पर दांव खेला है तो कांग्रेस ने भूपेंद्र जामवाल को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया। माता वैष्णो देवी के नाम से विधानसभा सीट बनवाने का श्रेय भाजपा को जाता है। 2016 से वह इसे विधानसभा क्षेत्र बनाने को लेकर अच्छी खासी मेहनत की थी और आखिरकार मेहनत रंग लाई। कटरा में बनने वाले विश्व स्तरीय आईएमएस यानी कि इंटर मॉडल स्टेशन, दिल्ली-अमृतसर-कटरा सिक्स लेन कॉरिडोर और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रसाद परियोजना जिसके तहत करोड़ों रुपये की लागत से कटरा के समग्र विकास की दुहाई लेकर भाजपा वोट मांग रही है। माना जा रहा है कि भाजपा के लिए यह सियासी मुफीद साबित हो सकता है।

अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 26 सीटों के लिए हुए मतदान में 56 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। कई स्थानों पर उत्साह से भरे मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। इस दौरान सबसे अधिक वोटिंग हॉट सीट में शुमार वैष्णो देवी सीट पर हुई, जहां 79.95 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नई सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। भाजपा ने इस सीट को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी थी और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस सीट को लेकर प्रचार के लिए कटरा पहुंचे थे। 19 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा में करीब दो किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यहां (जम्मू-कश्मीर में) एक ऐसी सरकार की जरूरत है, जो हमारी आस्था का सम्मान करे और हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे। प्रधानमंत्री मोदी की वैष्णो देवी मंदिर को लेकर आस्था किसी से छिपी नहीं है। 2014 में जब उन्हें भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो उन्होंने लोकसभा अभियान की शुरुआत करने से पहले मंदिर में प्रार्थना की थी। इस बार, महत्व दोगुना हो गया है, क्योंकि 2022 के परिसीमन के बाद, अब श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट है, जो रियासी और उधमपुर विधानसभा क्षेत्रों से अलग हो गई है। गौरतलब है कि भाजपा हाल के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद (अयोध्या) सीट हार गई थी और फिर विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड की बदरीनाथ की सीट भी नहीं जीत पाई थी। इन दो सीटों को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर जमकर हमला बोला था। ऐसे में अब श्री माता वैष्णो देवी सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है और यही वजह है कि पार्टी ने प्रचार में यहां कोई कमी नहीं छोड़ी हालांकि, भाजपा की राह यहां आसान नहीं दिख रही है क्योंकि उसके उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा, जो पूर्व में रियासी से विधायक रह चुके हैं, उन्हें यहां कई तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने कुल सात उम्मीदवार हैं जिसमें कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह भी शामिल हैं। भाजपा के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि उसने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदला है। पहले इस सीट पर रोहित दुबे को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह बलदेव शर्मा को टिकट दे दिया गया। इसके बाद रोहित दुबे के समर्थक नाराज हो गए और सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, वैष्णो देवी मंदिर के पूर्व संरक्षक बारीदार भाजपा के लिए इस सीट पर सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। पहले भाजपा का समर्थन करने वाले इस समुदाय ने इस बार अपने उम्मीदवार शाम सिंह को मैदान में उतारा है। यदि शाम सिंह को समुदाय से 14,000 वोट मिलते हैं, तो वह भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीढ़ियों से वैष्णो देवी मंदिर में आरती करने वाले बारीदार, मंदिर में पूर्ण पूजा करने के अपने अधिकारों की बहाली और श्राइन बोर्ड में अपने परिवार के सदस्यों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। समुदाय के सदस्य अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होने के लिए भाजपा पर विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही मां वैष्णो देवी के पूर्व बारीदारों के हक की मांग है। 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर में आयोजित रैली में बारिदरों को हक दिलवाने का वायदा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बारीदार मतदाता नतीजे को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। बारीदार माता वैष्णो देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं और कहते हैं कि श्रीधर उन्हीं के वंशज थे। श्रीधर को ही माता ने दर्शन दिए और त्रिकुट पर्वत पर बसने की बात बताई थी। इसके बाद से बारीदार माता की पूजा करते हैं। देखा जाय तो फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सीट पर भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह शहर में विकास कार्यों के लिए बड़ी संख्या में तोड़े गए मकान और जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिलना था। माना जाता है कि अयोध्या के लोगों ने इसी के चलते भाजपा के खिलाफ वोट किए थे। ऐसी ही स्थिति श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी दिख रही है। बारीदारनाराज हैं और लंबे समय से अपने हक की मांग कर रहे हैं। दरअसल, 1986 में 30 अगस्त को बारीदारों को गुफा से बाहर कर दिया गया और सारे अधिकार श्राइन बोर्ड को दे दिए थे। ऐसे में बारीदारों की मांग है कि गुफा में चढ़ावा का एक तिहाई हिस्सा बारीदारों को दिया जाए। इसके अलावा बारीदारों को श्राइन के हॉस्पिटल और कॉलेज में नौकरी दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बारीदारों को हक दिलाने की भरोसा दिया था, जो कि पूरा नहीं हो सका है। भाजपा के बलदेव शर्मा सामने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह भी मजबूत दावेदार हैं जो कटरा और वैष्णो देवी मंदिर के बीच ट्रैक पर काम करने वाले पोनीवालों और पिठुओं के संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। शर्मा को इस सीट पर लगभग 9,000 मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन की उम्मीद है। पूर्व मंत्री जुगल किशोर, जो कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शामिल हो गए थे, वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें भी प्रचार अभियान के दौरान ठीक-ठीक समर्थन मिला था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस धार्मिक नगरी में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजती है। एक बात और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मां वैष्णो देवी के नए ताराकोट मार्ग पर बनाए जा रहे रोपवे केबल कार परियोजना को लेकर मतदाता नाराज हैं। उन्हें यह चिंता सता रही है कि उनका सारा व्यापार इस परियोजना को लेकर बुरी तरह से प्रभावित हो गया है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे ज्ञान से और जटिल सूत्रों को सुलझाने वाले सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों से भी, जहां यह सकारात्मकता हर्ष संवाद और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आप आज हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे।

वृष

स्वजनों एवं परिजनों के साथ विवाद हो सकता है। आज कोई नया काम शुरू ना करें। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और ज्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। आज आपका दिन बहुत लाभदायी है।

मिथुन

हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए वाणी में गुस्सा ना रखें। परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो, इसका खास ध्यान रखें।

कर्क

पानी वाली जगहों से दूर रहें। आज धन का व्यय अधिक होगा। आज आपका दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है और किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा। आज नियम विरुद्ध कामों से दूर रहें। आपका व्यवहार न्यायपूर्ण रहेगा।

सिंह

माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी।

कन्या

आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कामों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप में आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए आप सावधान ही रहें। संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन अशांत रहेगा। दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें।

तुला

मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे। नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं। तन-मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी। अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज आप के घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा।

वृश्चिक

आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। जरूरी कामों पर धन खर्च होगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दफ्तर में सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा। मित्रों से मुलाकात होगी।

धनु

अविवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने के योग हैं। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी। मित्रों से लाभ होगा। आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा। मित्रों से लाभ होगा।

मकर

बाहर जाना हो सकता है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सरकारी लाभ होगा एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। पहले से निर्धारित काम के लिए आपका प्रयास ज्यादा रहेगा।

कुंभ

नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे। आपकी पदोन्नति के योग हैं। अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगा। परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी। घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है।

मीन

आप तन-मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आज भाग्य आपका साथ देगा। इनकम बढ़ेगी। परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा। महिलाओं के मायके से समाचार आने के योग हैं।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

'हर तरफ जहां भागमभाग है ,जहां दो मिनट किसी के लिए किसी के पास समय नहीं जहां संबंध मतलब के लिए बनाए जाएं ऐसी की दुनियां में कुछ ऐसे विचित्र शख्स भी हैं जो ओरों के लिए जीते हैं जो उनके अपने तो नहीं पर अपनो से कम भी नहीं'

नमस्कार मित्रों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं अलवर के पहले शीशु रोग विशेषज्ञ डॉ.सुनील रस्तोगी जी। इतने बेहतरीन इंसान हैं कि हमेशा सामाजिक सेवाओं के लिए तैयार रहते हैं। इस उम्र में भी सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना उनके ना केवल व्यक्तित्व को बयां करता है बल्कि इंसानियत की गवाही भी देता है। 1971 में एमबीबीएस जीआरमेडिकल कॉलेज ग्वालियर से की। एम.डी पीडियाट्रिक्स 1976 जी.आर.मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से की,5 साल तक केंद्र सरकार के लिए काम किया और अपनी मेडिकल सेवाए दी। सन 1982 में अलवर में अपना अस्पताल शुरू किया। उस समय बच्चों की तबीयत खराब होनें पर लोगों को दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता था ऐसे में अलवर जिले में सबसे पहले चिल्ड्रेन अलवर नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल शुरू किया गया।

अलवर जिले में निजी क्षेत्र में नवजात शिशु नर्सरी प्रारंभ करने वाली प्रथम : 1995 मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू किया। सबसे पहले निजी क्षेत्र में सर्जरी शुरू की। पेशेवर और सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। 2023 में एनआईएमएस अस्पताल जयपुर के साथ हाथ मिलाया, जिसमें अत्याधुनिक आईसीयू, ओटी, एनआईसीयू, लेबर रूम, 50 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल,मेडिसिन, बाल रोग, सर्जरी, ऑर्थो, गायनिका एंडो- यूरोए नेफ्रो और गैस्ट्रो में सुपरस्पेशलिटी के साथ शामिल है। सामाजिक कार्यों में सैदव ऊर्जा व नौजवान के रूप में सक्रियता निभाई। रोटेरियन के रूप में गरीबों के लिए विभिन्न मुफ्त चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया। पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। शहर में वृक्षारोपण किया, जिला स्तर पर कई पदों पर कार्य किया

इनकी दिवंगत पत्नी डॉ.वीणा गुप्ता बेहतरीन स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता में से एक रहीं, जो गरीबों को राहत देने में सक्रिय रूप से शामिल रहीं थी उन्हें मदर टेरेसा और भारत के राष्ट्रपति माननीय डॉ. शंकर दयाल शर्मा की पत्नी से कई प्रशंसाएं मिलीं। जब श्रीमती उषा शर्मा नगर परिषद अलवर में प्रशासक थीं, तब

डॉ.सुनील रस्तोगी
(वरिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ)

डॉ.वीना गुप्ता की सबसे अच्छी परियोजनाओं में से एक सब्जी मंडी की सफाई थी। इस परियोजना को समाज द्वारा बहुत सराहा गया था, उन्हें पॉल हैरिस फेलो के रूप में भी सम्मानित किया गया था।

धर्म पत्नी के देहवासन के बाद टूटे नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिती दर्ज करवाने लगे। आज डॉ.सुनील रस्तोगी आर्दश हैं युवाओं के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से इनकी कार्यशैली को जानता हूं। सच में इंसान के रूप में ईश्वर हैं। गरीब लोगों की मदद करना इनकी सबसे अच्छी विशेषताएं हैं। जमीन से जुडाव रखने वाले इन ऊर्जावान शख्सियत को मेरा दिल से प्रणाम है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्वल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

27 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- चीन के चिली की खाड़ी में 1290 को भूकंप से करीब एक लाख लोगों की मौत हुई।
- मीर कासिम 1760 में बंगाल के नवाब बने।
- मैक्सिको को 1821 में स्वतंत्रता मिली।
- इंग्लैंड में 1825 को स्टॉकटन-डार्लिंगटन लाइन की शुरुआत के साथ दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन शुरू हुआ।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली, जर्मनी एवं जापान ने 1940 में धूरी राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- मिहिर सेन 1958 में ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने।
- सिएरा लियोन 1961 में संयुक्त राष्ट्र का सौवां सदस्य बना।
- अमेरिकी अंतरिक्ष यान 1988 में 'डिस्कवरी' का केप कैनेवरल से प्रक्षेपण।
- बोस्निया में 1995 को संघर्षरत तीन दलों के मध्य अमेरिकी मध्यस्थता में समझौता सम्पन्न।
- अफगानिस्तान में 1996 को तालिबान द्वारा काबुल पर अधिकार, पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह एवं उनके भाई को सरेआम फांसी।
- इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना 1998 में हुई।
- जर्मनी में 1998 को सम्पन्न हुए चुनाव में गेरहार्ड श्रोयडर ने हेल्मट कोल को हराकर नये चांसलर बने।
- वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ओपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2000 को शुरू।
- न्यूयार्क में विश्व बैंक व आइएमएफ की वार्षिक बैठक 2002 को शुरू।
- ध्वनि से भी अधिक तेज गति से उड़ने वाले ब्रिटिश एयर के कॉनकर्ड विमान ने 2003 में न्यूयार्क से लंदन के लिए आखिरी उड़ान भरी।
- बिल गेट्स 2005 में लगातार ग्यारहवें साल दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने।
- पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2007 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए परचा भरा।
- भारत-पाक के विदेश मंत्रियों की बातचीत 2009 में शुरू हुई।
- इराक की राजधानी बगदाद की एक मस्जिद में 2013 को बम विस्फोट में सात लोगों की मौत।

विशेष आलेख

विश्व पर्यटन दिवस : पर्यटन से पनपती है शांति एवं मुस्कान की संभावनाएं

ललित गर्ग

विश्व पर्यटन दिवस दुनियाभर में पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। हर साल 27 सितंबर को आयोजित होने वाला यह दिन अंतरराष्ट्रीय एकता, शांति, सौहार्द और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में पर्यटन की शक्ति की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। इस दिवस की 2024 की थीम है 'पर्यटन और शांति।' दुनिया में शांति एवं अयुद्ध को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतर-सांस्कृतिक बातचीत को प्रोत्साहित करता है। लोग जितना अधिक यात्रा करते हैं, उतना ही वे विविध संस्कृतियों का अनुभव करते हैं, जिससे अधिक सहिष्णुता और समझ विकसित होती है, एक दूसरे के नजदीक आने का अवसर मिलता है। इससे शांति, अमन एवं सौहार्द का वातावरण निर्मित होता है। पर्यटन बाधाओं को तोड़ सकता है और राष्ट्रों के बीच स्थायी बंधन बना सकता है। यह रोजगार प्रदान करके और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों को ऊपर उठाने में भी मदद करता है, इस प्रकार क्षेत्रों की दीर्घकालिक शांति और समृद्धि में योगदान देता है।

पर्यटन न केवल एक आर्थिक चालक है, बल्कि एक अधिक समावेशी और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का एक साधन भी है। पर्यटन क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है और लाखों नौकरियाँ प्रदान करता है। यह स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है और सामुदायिक बुनियादी ढाँचे में निवेश को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन लोगों को अपनी संस्कृतियों, परंपराओं और ज्ञान को साझा करने का अवसर देता है। यह आदान-प्रदान सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और विविध समुदायों के बीच सम्मान, सौहार्द, सद्भावना और समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है। संधारणीय पर्यटन प्रथाएँ यात्रियों को पर्यावरण की रक्षा करने और जिम्मेदारी से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इससे पारिस्थितिकी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है और हमारे ग्रह की बेहतर देखभाल को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन से स्थानीय क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएँ और सेवाएँ मिल सकती हैं, जिससे आगंतुकों और निवासियों दोनों को लाभ होगा। यह विकास स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। भारत में पर्यटन उद्योग ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। पर्यटन क्षेत्र द्वारा 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 21.15 ट्रिलियन रुपये (लगभग 253 बिलियन डॉलर) जोड़ने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। भारत विश्व स्तर पर पाँचवाँ सबसे बड़ा यात्रा और पर्यटन बाजार बनने के लिए तैयार है, जिसका अनुमान है कि 2027 तक आउटबाउंड पर्यटन व्यय 89 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो 2019 में 38 बिलियन डॉलर था। भारत असंख्य पर्यटन अनुभवों और मोहक स्थलों का देश है। चाहे भव्य स्मारक हो, प्राचीन मंदिर या मकबरे हो, नदी-झरने, प्राकृतिक मनोरम स्थल हो, इसके चमकीले रंगों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रौद्योगिकी से चलने वाले इसके वर्तमान से अटूट संबंध है। केरल, शिमला, गोवा, आगरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मथुरा, काशी जैसी जगहें तो अपने विदेशी पर्यटकों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। भारत में अपने लोगों के साथ लाखों विदेशी लोग प्रतिवर्ष भारत घूमने आते हैं। भारत में पर्यटन की उपयुक्त क्षमता है। यहां सभी प्रकार के पर्यटकों को चाहे वे साहसिक यात्रा पर हो, सांस्कृतिक यात्रा पर या वह तीर्थयात्रा करने आए हों या खूबसूरत समुद्री-तटों की

यात्रा पर निकले हो, सबके लिए खूबसूरत जगहें हैं। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में तो लोगों को घूमते-घूमते महीना बीत जाते हैं। 2024 के लिए, इतिहास, संस्कृति और लुभावने परिदृश्यों से समृद्ध देश जॉर्जिया विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी करेगा। जॉर्जिया पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के चौराहे पर स्थित है, जो संस्कृतियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। यह अपने प्राचीन चर्चों, वाइन क्षेत्रों और आश्चर्यजनक पर्वत श्रृंखलाओं के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्जिया का पर्यटन क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे लाखों अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। अपने खूबसूरत नज़ारों के साथ, जॉर्जिया यह दिखाने के लिए एकदम सही जगह है कि पर्यटन किस तरह शांति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1980 से 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। पर्यटन दिवस को वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है एवं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित तथा जागरूकता फैलाने के लिए है कि किस प्रकार पर्यटन वैश्विक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को तथा आपसी समझ बढ़ाने में सहायता कर सकता है। हर व्यक्ति किसी-ना-किसी परेशानी से घिरा हुआ है, भय और जीवनसंकट के इस दौर में ऐसा लगता है मानो खुशी एवं मुस्कान तो कहीं गुम हो गई है। बावजूद इन सबके हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जिसमें खुशी, शांति एवं प्रसन्नता के पल जीवंत हो सके, इसका सशक्त माध्यम है पर्यटन। पर्यटन सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पलों को वापस लाने में ही मदद नहीं करेगा बल्कि यह किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम भी बनेगा। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन-उद्योग के इर्द-गिर्द घूमती रही है। यूरोपीय देश, तटीय अफ्रीकी देश, पूर्वी एशियाई देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत आदि ऐसे देश हैं जहां पर पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। भारत जैसे देशों के लिए पर्यटन का खास महत्व है। देश की पुरातात्विक विरासत या सांस्कृतिक धरोहर केवल दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल के लिए नहीं है बल्कि यह राजस्व प्राप्ति का भी स्रोत है। पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी-रोटी भी जुड़ी है। आज भारत जैसे देशों को देखकर ही विश्व के लगभग सभी देशों में पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, संवर्द्धन किया जाने लगा है। भारत में प्राचीन समय से पर्यटन की व्यापक संभावनाएं एवं स्थितियां रही है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब भारत के पर्यटन स्थल खतरे में नजर आने लगे और लगने लगा कि शायद अब भारत पर्यटक स्थल के नाम पर पर्यटकों की पहली पसंद नहीं रहेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार